

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 23.01.2024

उद्घोषित तिथि: 07.02.2024

रि.या.(सि.) 8794/2018

ब्लूबेल्स स्कूल अंतर्राष्ट्रीय कैलाश

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कमल गुप्ता, श्री स्पर्श अग्रवाल,  
सुश्री कृति गुप्ता और श्री मनीष  
वशिष्ठ, अधिवक्तागण

बनाम

शिक्षा निदेशालय

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: शिक्षा निदेशालय की ओर से श्री  
संतोष कुमार त्रिपाठी, स्थायी  
अधिवक्ता (सिविल) जी.एन.सी.टी.डी.  
सहित श्री उत्कर्ष सिंह, अधिवक्ता  
पक्षकार की ओर से श्री खगेश बी. झा  
एवं सुश्री शिखा शर्मा बग्गा  
अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)6419/2019

लीलावती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कमल गुप्ता, श्री स्पर्श अग्रवाल,  
सुश्री कृति गुप्ता और श्री मनीष  
वशिष्ठ, अधिवक्तागण

बनाम

शिक्षा निदेशालय

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: शिक्षा निदेशालय की ओर से श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता (सिविल) जी.एन.सी.टी.डी. सहित श्री उत्कर्ष सिंह, अधिवक्ता

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर**

**आदेश**

**07.02.2024**

**रि.या.(सि.)8794/2018**

1. याचिकाकर्ता ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल एक निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हालांकि स्कूल का निर्माण सरकार से पट्टे पर दी गई भूमि पर किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित करने वाले आवंटन पत्र या पट्टा विलेख में कोई शर्त नहीं है, जिसके तहत भूमि पट्टे पर दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को शुल्क बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय (डीओई) से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान रिट याचिका में दावा किया गया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ता का एकमात्र दायित्व डीओई को अपनी फीस संरचना के बारे में सूचित करना है, जैसा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 ("डी.एस.ई. अधिनियम") की धारा 17(3) के अनुसार आवश्यक है।

2. 19 जनवरी 2016 को, इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने जस्टिस फॉर ऑल बनाम जीएनसीटीडी मामले में अभिनिर्धारित किया कि डीओई को यह

सुनिश्चित करना था कि सभी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल जिन्हें सरकार या नगर निकायों द्वारा आवंटन पत्र या पट्टा विलेख में एक खंड सहित भूमि आवंटित की गई थी, स्कूल को अपनी फीस ("भूमि खंड") बढ़ाने से पहले डीओई की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इस आवश्यकता का विधिवत पालन किया जाता है और डीओई की पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी फीस में वृद्धि नहीं की जाती है। यह निर्णय डी. ओ. ई. द्वारा सभी स्कूलों के प्रमुखों और निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों को 19 फरवरी 2016 के आदेश के माध्यम से प्रसारित किया गया था। 16 अप्रैल 2016 को, डीओई ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा भूमि खंड सहित आवंटित भूमि वाले सभी स्कूलों को 2016-2017 शैक्षणिक सत्र हेतु ट्यूशन फीस में वृद्धि के लिए अपना प्रस्ताव, यदि कोई हो, डीओई की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, ताकि शुल्क बढ़ाने से पहले पूर्व मंजूरी प्राप्त की जा सके। यह अधिकतम 31 मई 2016 तक किया जाना था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आवश्यकता उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि उसे किसी भी "भूमि खंड" के साथ भूमि आवंटित नहीं की गई थी।

3. "भूमि खंड" के साथ आवंटित या पट्टे पर दी गई भूमि पर स्थित स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने से पहले डीओई से पूर्व अनुमोदन लेने का आदेश इस न्यायालय द्वारा 31 मई 2016 के आदेश में *एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट*

**स्कूल बनाम शिक्षा निदेशालय** में दोहराया गया था। उक्त निर्णय का उद्धरण देते हुए, डीओई ने 3 जून 2016 को आदेश जारी किया, जिसमें गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव दाखिल करने का समय 31 जुलाई 2016 तक बढ़ा दिया गया।

4. 19 नवंबर 2015 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें सीपीसी) ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। संशोधन को 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 [“सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम] 25 जुलाई 2016 को अधिसूचित किया गया था।

5. 19 अगस्त 2016 के परिपत्र द्वारा, डीओई ने सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमों को अपनाया और इस प्रकार, अपने कर्मचारियों के संबंध में 7वीं सीपीसी सिफारिशों को लागू किया।

6. हालांकि, इसके बाद 6 जनवरी 2017 को एक और परिपत्र जारी किया गया, जिसमें सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे 2017-2018 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस में वृद्धि के लिए अपनी प्रबंधन समितियों की कोई भी बैठक सक्षम प्राधिकारी के किसी भी निर्णय के लंबित होने तक आयोजित

न करें, क्योंकि निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में 7 वीं सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के तरीके के संबंध में निर्णय अभी भी विचाराधीन था।

7. डीओई द्वारा 27 मार्च 2017 को एक और स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबंधन समितियाँ स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य पाठ्यक्रमों में फीस के संशोधन के संबंध में निर्णय ले सकती हैं, लेकिन 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप फीस में संशोधन के लिए ऐसा कोई भी निर्णय लेने से रोक दिया गया। आगे यह दोहराया गया कि जो स्कूल डीडीए/सरकार द्वारा "भूमि खंड" के सहवर्ती प्रदान की गई भूमि पर स्थित है - जो वर्तमान याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है - उन्हें डीओई की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. दिनांक 6 जनवरी 2017 और 27 मार्च 2017 के परिपत्रों को एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स द्वारा रि.या.(सि) 2637/2017 (एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल बनाम डीओई) के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 30 मार्च 2017 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि, प्रथम दृष्टया, "शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले एक वर्ष में किए जाने वाले प्रमुख व्यय

को ध्यान में रखते हुए फीस संरचना को अधिसूचित करने के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के निरंकुश अधिकार को केवल आधार पर कम या कम नहीं किया जा सकता है कि व्यय के एक प्रमुख विषय के संबंध में निर्णय अर्थात् सातवें वेतन आयोग के कारण वेतन में वृद्धि, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के कुछ दिनों में शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इसलिए, यदि डीओई ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 7वीं सीपीसी को लागू करने का निर्देश दिया हो, तो इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता-स्कूलों को 7वीं सीपीसी के कार्यान्वयन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संशोधित शुल्क अनुसूची को डीओई को सूचित करने की अनुमति दी, और यह उक्त सूचना 30 मार्च 2017 को दाखिल की गई मानी जाएगी।

9. 31 मार्च 2017 को, याचिकाकर्ता-स्कूल ने अपनी वैधानिक रूप से गठित प्रबंधन समिति के माध्यम से, जिसमें DoE के नामांकित व्यक्ति शामिल थे, वर्ष 2017-2018 के दौरान उसके द्वारा ली जाने वाली शुल्क संरचना का निर्णय लिया। डीओई नामांकित व्यक्तियों ने प्रस्तावित शुल्क संरचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसे डीएसई अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार डीओई को विधिवत सूचित किया गया था।

10. 17 अक्टूबर 2017 को ही DoE ने एक आदेश जारी किया, जिसमें "दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की

सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश" शामिल थे। उन स्कूलों के संबंध में जिनकी स्थापना के लिए भूमि आवंटन दस्तावेजों में कोई "भूमि खंड" नहीं था, आदेश इस प्रकार निर्धारित किया गया:

"1. सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सामान्य निर्देश, चाहे भूमि की स्थिति कुछ भी हो:-

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए फीस वृद्धि अनिवार्य नहीं है।

(ख) सभी स्कूलों को, सबसे पहले, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों के भुगतान में किसी भी कमी को पूरा करने हेतु मौजूदा आरक्षित निधि का उपयोग करने की संभाव्यता तलाशनी चाहिए।

(ग) स्कूलों को फीस में वृद्धि को अपने राजस्व को बढ़ाने का एकमात्र स्रोत नहीं मानना चाहिए। उन्हें राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ाने के लिए अन्य अनुमेय उपायों पर भी काम करना चाहिए।

(घ) स्कूलों की मान्यता से पूर्व शर्त के रूप में और सरकार के पक्ष में गिरवी रखी गई जमा राशि पर ब्याज का उपयोग वर्तमान मामले में बकाया भुगतान हेतु भी किया जाना चाहिए।

\*\* \*\*

(च) माता-पिता/छात्रों से एकत्र की गई फीस/निधि का उपयोग दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 176 और 177 के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। किसी स्कूल के मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल फंड से सोसायटी या ट्रस्ट या किसी अन्य संस्थान को कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(छ) ट्यूशन शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि डी.ए., बोनस इत्यादि के प्रावधानों सहित स्थापना की मानक लागत को कवर किया जा सके, और सभी टर्मिनल लाभों के साथ-साथ पाठ्यक्रम या निर्धारण से संबंधित राजस्व प्रकृति का व्यय भी छात्रों/अभिभावकों से लिया जाएगा।

\*\*\*\*\*

(i) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार गैर-व्यावसायिक संगठन/गैर-लाभकारी संगठन पर लागू खाते के सिद्धांतों पर खातों का रखरखाव करेंगे। ऐसे स्कूल विभाग द्वारा दिनांक 16/04/2016 के आदेश सं. एफ.डीई-15/एक्ट-1/डब्ल्यूपीसी-4109/भाग/13/7905-7913 के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपना वित्तीय विवरण तैयार करेंगे जिसमें तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और रसीद व भुगतान खाता शामिल होंगे।

(ज) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को विभाग द्वारा दिनांक 03/07/2017 के आदेश सं. एफ./डीई/पीएसबी/2017/16604 द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार अधिनियम की धारा 17(3) के तहत आगामी सत्र से पहले प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक फीस का विवरण दाखिल करना होगा।

(ट) हालांकि, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु ट्यूशन फीस में वृद्धि एकमात्र विकल्प नहीं है, फिर भी, यदि स्कूल की प्रबंधन समिति उपरोक्त शर्तों के अनुसार सभी संभावनाओं को तलाशने के बाद ट्यूशन फीस में वृद्धि करना आवश्यक समझती है, तो स्कूल की प्रबंधन समिति शिक्षकों और अभिभावकों के समूह सहित एक बैठक करेगी जिसमें स्कूल के प्रत्येक अनुभाग से कम से कम एक अभिभावक प्रतिनिधि शामिल होगा और स्कूल औचित्य सहित और अनुलग्नक क में उल्लिखित सभी दस्तावेजों से साथ स्कूल का विस्तृत बजट, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु धन की



आवश्यकताएं, स्कूल निधि खाते में नकदी/आरक्षित निधि/बचत की उपलब्धता आदि सहित शुल्क वृद्धि यदि कोई हो, के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे। अभिभावकों और शिक्षकों के प्रतिनिधियों से सहयोग मांगा जाएगा। या तो प्रबंधन समिति उनके सुझावों पर विचार कर सकती है और अपने प्रस्ताव को संशोधित कर सकती है, या अपनी असहमति दर्ज कर सकती है। शिक्षा निदेशक के नामित व्यक्ति (डी.ई. के नामांकित व्यक्ति) को बैठक में उपस्थित रहना होगा। इस बैठक के कार्यवृत्त और उपस्थिति पत्र, डी.ई. के नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, बैठक के लिए आमंत्रित अभिभावकों के विवरण और बैठक की तस्वीरों सहित स्कूल द्वारा संबंधित डी.डी.ई. (जिला) को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अनुभाग के अभिभावकों के प्रतिनिधियों के समक्ष फीस वृद्धि के प्रस्ताव की प्रस्तुति को माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12/08/2011 को रि.या.सि. 7777/2009 अर्थात् दिल्ली अभिभावक महासंघ बनाम जी.एन.सी.टी.डी. के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों के प्रतिनिधियों की मंजूरी की मांग के रूप में नहीं माना जाएगा।

(1) मध्य सत्र वृद्धि के संदर्भ में 01/01/2016 से ट्यूशन शुल्क में वृद्धि के उद्देश्य से, एक्शन कमेटी अनएडेड रेकग्निज्ड स्कूल बनाम डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन अर्थात् रि.या.सि. 2637/17 मामले में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30.03.2017 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“अधिनियम की धारा 17(3) में 31 मार्च, 2017 के महत्व और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए और इक्विटी को संतुलित करने हेतु, इस न्यायालय का निर्देश है कि यदि प्रत्यर्थी द्वारा सातवें वेतन आयोग को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू करने का निर्देश दिया जाता है, तो

याचिकाकर्ता स्कूलों के पास सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संशोधित शुल्क अनुसूची को सूचित करने का विकल्प होगा। और इसे 30 मार्च 2017 को दायर किया गया माना जाएगा।

\*\*\*\*\*

3. ट्यूशन शुल्क में वृद्धि की प्रक्रिया

1. निजी भूमि पर या डीडीए/एलएंडडीओ द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों के लिए किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) की पूर्व मंजूरी लेने की शर्त नहीं है।

क. पैरा (1) में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के बाद, यदि कोई स्कूल अभी भी ट्यूशन शुल्क में वृद्धि करना आवश्यक समझता है, तो वह डीई के नामांकित व्यक्तियों सहित स्कूल की प्रबंधन समिति के समक्ष प्रत्येक खाते की आय और व्यय को दर्शाने वाले विस्तृत वित्तीय विवरणों सहित अपना मामला प्रस्तुत करेगा।

ख. स्कूल ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखने से पहले धारा 18(4), नियम 172, 173, 174, 175, 176 और 177 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश, विभिन्न न्यायिक घोषणाएं, और **मॉडर्न स्कूल मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और **दिल्ली अभिभावक महासंघ बनाम डीओई** (रि.या.सि. 7777/2009) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात का भी अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

\*\*\*\*\*

ड. डी.ई. के नामितों सहित प्रबंधन समिति निधि/आरक्षितियां/हाथ नकदी/बैंक शेष/अधिशेष की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फीस में वृद्धि हेतु स्कूल के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी। यदि डी.ई. का नामांकित व्यक्ति ट्यूशन फीस में वृद्धि के प्रस्ताव से असहमत है या दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों, समय-समय पर जारी

निर्देशों/दिशानिर्देशों और इस संबंध में न्यायिक घोषणा के आधार पर प्रस्ताव के खिलाफ ट्यूशन फीस में कम वृद्धि के लिए सहमत है, तो वह बैठक के कार्यवृत्त में शुल्क में कम वृद्धि या शुल्क में कोई वृद्धि नहीं करने को उचित ठहराने वाले प्रावधानों और अन्य कारणों का हवाला देते हुए अपना असहमति नोट लिखित रूप में दर्ज करेगा और उसके बाद ही बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करेगा। स्कूल के डी.ई. के नामित व्यक्ति सभी मामलों में जानकारी और अभिलेख हेतु बैठक के कार्यवृत्त को संबंधित जिले के उप निदेशक को भेजेंगे। डी.ई. का नामांकित व्यक्ति संबंधित डीडीई को प्रबंधन समिति की बैठकों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसने भाग लिया था।

च. स्कूल की प्रबंधन समिति डीएसईएआर, 1973 की धारा 17(3) के तहत शुल्क का पूरा विवरण विभाग द्वारा दिनांक 03/07/2017 के आदेश के तहत प्रसारित प्रोफार्मा में संबंधित डीडीई को दाखिल करेगी।

\*\*\*\*\*

ज. ट्यूशन फीस में वृद्धि के परिणामस्वरूप, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल द्वारा वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, निर्धारित शुल्क जैसी कोई अन्य फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।

11. 30 नवंबर 2017 को, स्कूल ने 7वें सी. पी. सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुपालन में अपनी शुल्क संरचना की एक प्रति प्रस्तुत की। शुल्क संरचना को स्कूल की प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें डीओई के नामांकित व्यक्ति शामिल थे। यह भी कहा गया कि शिक्षा विभाग के नामांकित व्यक्तियों ने प्रस्तावित शुल्क संरचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। एक स्कूल के रूप में जो किसी भी "भूमि खंड" के अधीन नहीं था, याचिकाकर्ता का दावा है कि रिट याचिका में केवल

डी.एस.ई. अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत अपनी शुल्क संरचना के बारे में डीओई को सूचित करने की आवश्यकता थी, जो इस प्रकार किया गया था।

12. 13 अप्रैल 2018 को, शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें भूमि पर संचालित स्कूलों के संबंध में 17 अक्टूबर 2017 के आदेश को वापस ले लिया गया, जिस पर "भूमि खंड" लागू होता है। इसलिए, 13 अप्रैल 2018 का आदेश याचिकाकर्ता पर लागू नहीं हुआ, जिसके संबंध में 17 अक्टूबर 2017 का पूर्व आदेश जारी रहा।

13. याचिकाकर्ता-स्कूल में कुछ छात्रों के माता-पिता ने 15 मई 2018 को स्कूल को एक शिकायत संबोधित की, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्कूल ने अवैध रूप से अपनी फीस में वृद्धि की है और डीओई की पूर्व मंजूरी के बिना बकाया की मांग की है, जैसा कि डीओई द्वारा जारी 13 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसार आवश्यक है। इन परिस्थितियों में, शिकायत में स्कूल से या तो डीओई से 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार फीस बढ़ाने और बकाया वसूली को अधिकृत करने का आदेश मांगा गया या फीस वृद्धि को वापस लेने, बकाया वसूली को बंद करने और पहले से एकत्रित बकाया राशि की वापसी की मांग की गई। शिकायत को डिप्टी डीओई द्वारा उसी दिन, अर्थात् 15 मई 2018 को स्कूल को भेज दिया गया और तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया।

14. स्कूल ने 17 मई 2018 के अपने जवाब में बताया कि यह किसी भी "भूमि खंड" के अधीन नहीं था और केवल तीन किशतों में देय बकाया सहित अपने शिक्षण शुल्क में वृद्धि की थी, और शुल्क में वृद्धि डीओई के दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के आदेश के अनुसार थी।

15. डीओई ने 25 मई 2018 को आदेश जारी किया, जिसमें स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस करने और 2017-2018 के दौरान ली जा रही मात्रा के अनुसार फीस लेने का आदेश दिया गया, क्योंकि (i) 7वें सीपीसी के अनुसार स्कूल द्वारा फीस में किसी भी वृद्धि के लिए डीओई द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी और (ii) प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत हुआ कि स्कूल द्वारा फीस में वृद्धि उच्च स्तर पर थी, और डीओई द्वारा इसकी विस्तार से जांच की जानी थी।

16. स्कूल ने 13 जून 2018 को जवाब देते हुए कहा कि 2017-2018 के दौरान उसके द्वारा ली गई संशोधित शुल्क डीओई के 17 अक्टूबर 2017 के आदेश के अनुसार थी और जहां तक 2018-2019 शैक्षणिक वर्ष का संबंध है, स्कूल की प्रबंधन समिति ने 13 मार्च 2018 को अपनी बैठक में, 2018-2019 शैक्षणिक वर्ष में वेतन वृद्धि, डीए, परिणामी वैधानिक देनदारियों और मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय देनदारियों को पूरा करने हेतु शुल्क में 10% की मामूली वृद्धि की। यह भी बताया गया कि 2018-2019 हेतु प्रस्तावित शुल्क अनुसूची को तुरंत शिक्षा विभाग रि.या.(सि.) 8794/2018

को भेज दिया गया था और माता-पिता को 4 अप्रैल 2018 को विधिवत सूचित किया गया था। एक स्कूल के रूप में जो उस भूमि पर स्थित नहीं था जिस पर कोई "भूमि खंड" लागू होता था, यह प्रस्तुत किया गया था कि स्कूल को 7वीं सीपीसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के वित्तीय निहितार्थों को पूरा करने हेतु अपनी फीस बढ़ाने से पहले डीओई की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

17. इसके बाद, 11 जून 2018 के पत्र के माध्यम से, शिक्षा विभाग ने स्कूल से कुछ दस्तावेज मांगे, जो 15 जून 2018 को प्रदान किए गए थे। इसके बाद, स्कूल को शिक्षा विभाग के 11 जुलाई 2018 के पत्र के *माध्यम* से सूचित किया गया कि स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और 17 जुलाई 2018 को निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण विधिवत किया गया और मांगे गए सभी दस्तावेज स्कूल द्वारा समिति को उपलब्ध कराए गए। निरीक्षण की कोई रिपोर्ट स्कूल को कभी नहीं दी गई।

18. इसके बाद, डीओई ने अपने पत्र दिनांक 23 जुलाई 2018 के *माध्यम* से स्कूल को दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा। उक्त दस्तावेजों में से कुछ 26 जुलाई 2018 को प्रदान किए गए थे, और शेष 30 जुलाई 2018 के अभ्यावेदन सहित 1 अगस्त 2018 को प्रदान किए गए थे।

19. 1 अगस्त 2018 को डीओई द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

## "आदेश

जबकि, ब्लू बेल्ल्स स्कूल इंटरनेशनल, कैलाश, नई दिल्ली एक निजी मान्यता प्राप्त स्कूल है जो रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के तहत कार्यरत है और इसे दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। साथ ही शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वैधानिक निर्देशों का पालन करें।

और जबकि, ब्लू बेल्ल्स स्कूल इंटरनेशनल, कैलाश, नई दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता द्वारा, विशेष रूप से स्कूल द्वारा मांगी गई 7वीं सीपीसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अनधिकृत शुल्क वृद्धि और बकाया के संबंध में, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के कार्यालय से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

और जबकि, उक्त शिकायत स्कूल को उनकी टिप्पणियों हेतु भेज दी गई थी। धारा 17(3) के तहत फीस वृद्धि के संबंध में स्कूल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और दिए गए कारणों के अवलोकन पर, यह देखा गया कि स्कूल को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार दिनांक 17.07.18 को उक्त विद्यालय के निरीक्षण के समय उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सुना गया।

और जबकि, स्कूल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण के विश्लेषण के दौरान कुछ बिंदु उभर कर सामने आए हैं जैसे कि स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि स्कूल डीडीए भूमि पर है और इसमें फीस वृद्धि से पहले शिक्षा निदेशक की पूर्वानुमति लेने की शर्त नहीं लगाई गई है।

और जबकि, स्कूल के अध्यक्ष/प्रबंधक को फीस वृद्धि के अपने दावे को सही ठहराने के लिए कुछ प्रासंगिक दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने/प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। निरीक्षण समिति ने दिनांक 11/07/2018 के पत्र सं. डीडीई/एसई/2018-2019/1675 और आगे दिनांक 23/07/2018 के पत्र सं. डीडीई/एसई/2018-2019/224 के माध्यम से "नैसर्गिक न्याय" को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन सब व्यर्थ।

और जबकि, शिक्षा निदेशक ने स्कूल की भूमि की स्थिति की परवाह किए बिना दिनांक 17.10.2017 के आदेश सं. डीई15(318)/पीएसबी/201619786 के माध्यम से दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में 7वीं सीपीसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

उक्त आदेश के अनुसरण में शिक्षा उप निदेशक (दक्षिण-पूर्व) की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें डीडीई (जोन-25), एडीई (एसई) और खाता अधिकारी (एसई) ने डीएसईए, 1973 की धारा 17(3) के तहत स्कूल के शुल्क विवरण की जांच की है और निम्नानुसार देखा गया-

1. दिनांक 11.02.2009 के आदेश सं. एफ.डीई/15(56)/अधिनियम/2009/778 के खंड 14 के अनुसार, फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए संसाधनों के पूरक हेतु विकास शुल्क, कुल वार्षिक ट्यूशन फीस का 15% से अधिक नहीं लिया जा सकता है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और इसके तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, यह पाया गया है कि स्कूल उपरोक्त खंड 14 के उल्लंघन में विकास शुल्क का उपयोग कर रहा है। विकास निधि के दुरुपयोग का विवरण इस प्रकार है:

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
फर्नीचर और फिक्स्चर की मरम्मत	5,45,534	1,54,408	3,20,944
इमारत की मरम्मत और रखरखाव	16,38,039	73,60,715	13,05,773
चौकीदार और वार्डन	10,15,196	-	-
विद्युत समान और मरम्मत	3,73,319	1,98,010	1,38,161
कंप्यूटर की मरम्मत और रखरखाव	13,71,179	1,91,318	20,45,844
संरक्षण शुल्क	32,95,365,	-	-
वनस्पति और विज्ञान पार्क गतिविधियाँ	6,84,579	-	-



सामान्य मरम्मत और रखरखाव	1,28,236	-	3,27,266
बहुउद्देशीय हॉल की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन	-	-	1,40,545
भाषा प्रयोगशाला उपकरण रखरखाव	-	-	1,24,033
शैक्षणिक विस्तार परियोजना व्यय	3,28,896	-	-
खेल मैदान का व्यय	18,79,9	-	-
जेनसेट मरम्मत	1,93,778	-	2,49,519
पुस्तकालय पुस्तकें	1,36,638	16,991	1,36,755
खेल सामग्री	13,398	1,75,340	97,511
कुल	97,42,956	80,96,782	48,86,351

2. डीएसईआर, 1973 के नियम 180 के अनुसार, स्कूल को अन्य बातों के अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत संपरीक्षित की गई रसीदें और भुगतान खाते की प्रति जमा करना आवश्यक है। हालांकि, स्कूल वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए रसीदें और भुगतान खाता प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

3. यह ध्यान दिया जाता है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्कूल ने क्रमशः 23,43,634 रुपए और 20,56,553/- रुपए की राशि से डबल डेस्क और सिंगल डेस्क खरीदे हैं। वित्तीय विवरणों में डबल डेस्क और सिंगल डेस्क के प्रारंभिक अतिशेष का विवरण नहीं दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें स्कूल के फर्नीचर और फिक्स्चर के खंड में मिला दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान फर्नीचर और फिक्स्चर का कोई विक्रय/बिक्री नहीं हुई। स्कूल की प्रस्तुति के अनुसार, दिनांक 15.07.2018 तक केवल 1930 छात्र हैं। स्कूल की छात्र संख्या और डेस्क की खरीद में शामिल राशि को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्कूल ने स्कूल फंड का उपयोग करते समय उचित औचित्य का पालन नहीं किया है।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि स्कूल छात्रों से परिवहन शुल्क वसूल रहा है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2015-16 तक स्कूल के वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया

गया है। डीएसईआर, 1973 के नियम 175 के सहपठित डीएसईए, 1973 की धारा 18(3) के अनुसार स्कूल को अपने खाते बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि फीस आदि के माध्यम से स्कूल को होने वाली आय को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सके और इसलिए, स्कूल डीएसईए एंड आर, 1973 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और अपने परिवहन शुल्क संग्रह और संबंधित व्यय को छुपा रहा है।

5. वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तुलना करने पर, दिनांक 01.04.2016 को प्रारंभिक अतिशेष में अंतर नोट किया गया है। भिन्नताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2016 को शेष राशि
सामान्य निधि	- 25,60,181.00	32,80,886.00
अवक्षयण आरक्षित निधि	5,17,05,360.00	5,53,51,574.00
वाहन प्रतिस्थापन निधि	-	8,05,000.00
सेवा हेतु वर्तमान दायित्व	1,956.00	6,081.00
स्थिर आस्तियां - सकल मूल्य	7,01,40,559.00	7,90,46,661.00
निवेश	1,30,39,638.00	1,41,24,748.00
कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	78,263.00	1,03,713.0
ठेकेदार को अग्रिम भुगतान	70,194.00	72,271.00
टीडीएस प्राप्य	3,58,491.00	4,20,117.00
बैंक में जमा राशि	42,78,598.00	43,01,460.00
बैंक एफडीआर पर ब्याज	11,87,249.00	12,75,429.00
जमा (अन्य बैंक से)	5,91,416.00	6,96,416.00

6. स्कूल ने 17(3) के तहत दायर अपने फीस विवरण में अधिक खर्च का प्रस्ताव दिया है।

क) 2016-17 में फिक्स्चर पर व्यय शून्य है, 2017-18 में अनुमानित व्यय 320944/- रुपए है लेकिन 2018-19 के लिए प्रस्तावित व्यय 48,38,500/- रुपए है।

ख) 2016-17 में कंप्यूटर खरीद पर व्यय 28,73,000/- रुपए था, 2017-18 में 50,00,000/- रुपए और 2018-19 के लिए प्रस्तावित व्यय 10,00,000/- रुपए है। कंप्यूटर एक पूंजी आस्ति है और कई वर्षों तक चलता है। हर साल इतना खर्च होना सही प्रतीत नहीं होता।

(ग) 2016-17 के दौरान शिक्षण सहायता पर व्यय 1,70,582/- रुपए था जबकि 2018-19 के दौरान प्रस्तावित व्यय 38,00,000/- रुपए और शिक्षण सहायता उपकरणों के उन्नयन के लिए 1,80,000/- रुपए है।

(घ) 2016-17 के दौरान किया गया ऊपरी व्यय 3,48,76,134/- रुपए है, जबकि 2018-19 के दौरान प्रस्तावित व्यय 5,48,03,790/- रुपए है, जो 41.33% की वृद्धि है और इस तरह यह सही प्रतीत नहीं होता है।

7. वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध कुल धनराशि 20,16,52,361/- रुपए है, जिसमें से वर्ष 2017-18 में नकदी बहिर्प्रवाह 17,61,95,435 रुपए होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप 2,54,56,926/- रुपए की धनराशि अधिशेष हो गई। विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (रु.)
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.17 को नकदी और बैंक शेष।	86,29,460
जमा: संपरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार 31.03.17 को निवेश	1,41,87,811
निकले: सीबीएसई आरक्षित निधि हेतु सावधि जमा	7,63,858
उपलब्ध निधि	2,20,53,413
जमा: लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार 2016-17 के लिए	17,80,12,041

शुल्क (हमने माना है कि 2016-17 में प्राप्त राशि कम से कम 2017-18 में एकत्रित होगी)।	
जमा: लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 2016-17 के लिए अन्य आय (हमने माना है कि 2016-17 में प्राप्त राशि कम से कम 2017-18 में एकत्रित होगी)।	15,86,907
2017-18 के लिए निधि की अनुमानित उपलब्धता	20,16,52,361
निकले: स्कूल द्वारा दिनांक 15.06.2018 के पत्र द्वारा प्रस्तुत प्राप्तियों और भुगतान खाते के अनुसार सत्र 2017-18 के लिए अनंतिम व्यय	17,61,95,435
शुद्ध अधिशेष	2,54,56,926

उपरोक्त जांच को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्कूल के पास अपने व्यय को पूरा करने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय प्रभावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, स्कूल प्राधिकरण को सत्र 2017-18 के लिए शुल्क के किसी भी मुख्य स्रोत में शुल्क वृद्धि नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।

अब इसलिए, मैं, जूही अग्रवाल, शिक्षा उपनिदेशक, धारा 17(3) के तहत शिक्षा निदेशक की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और निदेशक (शिक्षा) के दिनांक 13/10/2017 के आदेश सं. डीई. 15(318)/पीएसबी/2016/19742 के तहत हस्ताक्षरित शक्ति का प्रयोग करते हुए और स्कूल के अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधक/एचओएस ब्लू बेल्स स्कूल इंटरनेशनल, कैलाश, नई दिल्ली को डीएसईएआर, 1973 की धारा 24(3) के तहत निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का निर्देश देती हूँ:

i. 7वें सीपीसी के कार्यान्वयन सहित किसी भी कारण से सत्र 2017-18 हेतु प्रस्तावित शुल्क वृद्धि के अनुसरण में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा और यदि शुल्क पहले ही बढ़ा दिया गया है, तो उसे अभिभावकों को वापस कर दिया जाएगा या अनुवर्ती महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

- ii. स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि की अस्वीकृति के बारे में अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और परिपत्र के माध्यम से सूचित करना।
- iii. शुल्क का उपयोग डीएसईएआर, 1973 के नियम 177 के भाव और **मॉडर्न स्कूल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाना चाहिए।
- iv. छात्रों से एकत्रित शुल्क का उपयोग डीएसईएआर, 1973 के नियम 177 के प्रावधानों और इस निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।”

20. वर्तमान रिट याचिका 1 अगस्त 2018 के उपरोक्त आदेश को रद्द करते हुए सर्टिओरारी की रिट की मांग करती है।

### प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

21. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कमल गुप्ता और रा.रा.क्षे.दि./डीओई के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संतोष त्रिपाठी को, साथ ही श्री खगेश पी. झा को, जिन्हें कुछ अभिभावकों की ओर से हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, विस्तार से सुना है।

22. श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित मुद्दा **रामजस स्कूल बनाम डी.ओ.ई. व महाबीर सीनियर मॉडल स्कूल बनाम डी.ओ.ई.** मामले में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा कवर किया गया है।

23. विशेष रूप से, श्री गुप्ता निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ देते हैं:

(i) आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। प्रस्तावित अस्वीकृतियों की गणना करते हुए डीओई द्वारा

कभी भी स्कूल को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, और इसलिए जवाब देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में, चूँकि स्कूल किसी भी प्रतिकूल आदेश से अनभिज्ञ था, इसलिए वह कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं माँग सकता था।

(ii) वर्तमान रिट याचिका के जवाबी शपथ पत्र में, डीओई ने यह तर्क देने की मांग की है कि कानून को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई के किसी भी अवसर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यह **रामजस स्कूल** और **महाबीर सीनियर मॉडल स्कूल** के फैसलों के विपरीत है।

(iii) याचिकाकर्ता के खिलाफ शिक्षा के व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी का कोई आरोप नहीं है। ऐसे किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में, डीओई के पास उस तरीके में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसमें याचिकाकर्ता ने आगामी वर्ष के लिए अपनी फीस तय की थी। ऐसा कोई भी हस्तक्षेप भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन होगा।

(iii) प्रत्येक स्कूल उचित अधिशेष बनाए रखने का हकदार था, और अधिशेष का अस्तित्व मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण का संकेत नहीं देता था।

(iv) डीओई के पास स्कूल के पास उपलब्ध अधिशेष की पर्याप्तता की जांच करने या यह आकलन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था कि अधिशेष को देखते हुए, स्कूल का फीस बढ़ाना उचित था या नहीं।

(v) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 ("डीएसई नियम") के नियम 190(6)8 का भी उल्लंघन किया गया था, क्योंकि स्कूल के निरीक्षण की रिपोर्ट उसे प्रदान नहीं की गई थी। वर्तमान मामले में, स्कूल को सूचित करने वाला नोटिस कि उसका निरीक्षण किया जाएगा, 11 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। निरीक्षण 17 जुलाई 2018 को हुआ था। इसके बाद, 23 जुलाई 2018 को, डीओई ने स्कूल को पत्र लिखकर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए 12 प्रमुखों के तहत सूचीबद्ध जानकारी/दस्तावेजों को अग्रेषित करने का निर्देश दिया। 1 अगस्त 2018 के आक्षेपित आदेश जारी होने से पहले स्कूल के साथ कोई और संचार नहीं हुआ था, जो कथित तौर पर स्कूल से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इसका शुद्ध अधिशेष ₹ 2,54,56,926/- था, जो शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के वित्तीय निहितार्थ को पूरा करने के लिए पर्याप्त

था। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से डीएसई नियमावली के नियम 190 के विपरीत थी।

इसके अतिरिक्त, श्री गुप्ता ने यह भी प्रस्तुत करने की मांग की है कि जिस तरीके से आक्षेपित आदेश स्कूल के पास उपलब्ध अधिशेष की गणना करता है, उसमें तथ्यात्मक अशुद्धियां या त्रुटियां हैं। हालांकि, मैं उस पहलू की जांच करना आवश्यक नहीं समझता, उन कारणों से जो वर्तमान में स्पष्ट हो जाएंगे।

**24.** उपरोक्त प्रस्तुतियों के संदर्भ में, श्री गुप्ता *महावीर सीनियर मॉडल स्कूल* मामले में इस न्यायालय के निर्णय के निम्नलिखित अंशों पर भरोसा करते हैं:

"11. वर्तमान मामला फीस निर्धारण में निजी स्कूलों की स्वायत्तता और उस पर सरकारी नियंत्रण की सीमा के बीच एक क्लासिक झगड़े को सामने लाता है, एक ऐसा मुद्दा जो नियमित रूप से इस न्यायालय से जुड़ा रहता है। डीओई ने जोर देकर कहा कि "निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल" की स्थिति के बावजूद, उनकी पूर्व अनुमति के बिना कोई शुल्क तय नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, स्कूलों ने तर्क दिया कि उन्हें अपने मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता है, जिसमें फीस का निर्धारण भी शामिल है। उस को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के समक्ष विचार करने योग्य बात यह है कि क्या आक्षेपित आदेश पारित करने में, डीओई ने डीएसईए और डीएसईआर या किसी अन्य मौजूदा नियम/विनियम के तहत निहित अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है, जिससे शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 हेतु उनकी फीस संरचना के निर्धारण में याचिकाकर्ता स्कूलों की स्वायत्तता प्रभावित होगी।



\*\*\*

क्या स्कूलों द्वारा प्रस्तावित फीस वृद्धि मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण है  
 17. भले ही डीएसईए के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस वृद्धि से पहले डीओई से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता हो, फिर भी, डीओई डीएसईए और डीएसईआर की धारा 17(3) और 18(3) और (4) के अंतर्गत आने वाले नियामक नियंत्रण का प्रयोग करता है। हालांकि, शुल्क संरचना को विनियमित करते समय, डीओई अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है। इसमें स्कूल द्वारा प्रयोग किए गए निर्णय की शुद्धता का विश्लेषण करने की शक्ति निहित नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण में शामिल न हो। नियामक क्षेत्राधिकार की सीमाएँ सीमित और प्रतिबंधित हैं, जैसा कि इसके बाद उल्लिखित न्यायिक उदाहरणों द्वारा बताया गया है।

\*\*\*\*\*

आक्षेपित आदेश को समझना: दांव पर लगे कानूनी मुद्दों को सुलझाना  
 23. यह हमें आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के आधार पर लाता है। स्कूलों ने आरोपों का जवाब देने का अवसर न दिए जाने के कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ऑडी अल्टरम पार्टम का यह सिद्धांत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आधारशिला है और किसी भी कानूनी प्रक्रिया में उचित और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश प्रस्तावित अस्वीकृतियों की पूर्व सूचना के बिना जारी किया गया था। इस विवाद का कोई ठोस जवाब नहीं है। न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश में उल्लिखित कथित विसंगतियों को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले स्कूलों को बताया जाना चाहिए था, जिससे उन्हें जवाब देने का पर्याप्त अवसर मिल सके। इस सिद्धांत का पालन निर्णय लेने की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी बना देगा और किसी मामले के नतीजे को प्रभावित करने से पक्षपात या प्रतिकूल को रोक देगा। इस प्रकार, डीओई को यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि स्कूलों को सभी प्रासंगिक सामग्री और जानकारी प्रदान की जाए, जिसमें शुल्क विवरण की जांच करते समय नियामक अधिकारियों द्वारा उठाए गए किसी भी आपत्ति या चिंता का आधार भी शामिल है। इससे स्कूलों को सार्थक तरीके से अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इसमें कहा गया है, न्यायालय की राय में, इस समय मामले को डीओई को वापस भेजने के बजाय, अपने गुणों के आधार पर आक्षेपित आदेश की वैधता का मूल्यांकन करना उचित होगा।

\*\*\*\*\*

29. इसके बाद, मुद्दा यह आता है कि क्या अधिशेष निधि का संचय मुनाफाखोरी के समान है। सबसे पहले तो यह आरोप पहली बार किसी याचिका के प्रत्युत्तर में न्यायालय के समक्ष लगाया गया है। दूसरे, डीओई का "शिक्षा के व्यावसायीकरण" का आरोप केवल "स्कूल के संचालन हेतु पर्याप्त धन" की उपस्थिति पर आधारित है। इस प्रकार, विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं: (क) क्या केवल अधिशेष की उपलब्धता स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने से अयोग्य ठहराती है; और (ख) क्या डीओई के पास मुनाफाखोरी का पता न चलने पर स्कूलों के पास उपलब्ध धन की पर्याप्तता निर्धारित करने की शक्ति है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कारणों से नकारात्मक में दिए जाने चाहिए।

30. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के खातों और अन्य अभिलेखों की जांच करने की डीओई की शक्ति का स्रोत डीएसईए की धारा 17(3) में है, जिसे डीएसईआर के नियम 180(3) के साथ पढ़ा जाता है(यहां ऊपर जांच की गई है)। नियम 180(3) के तहत, एक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल द्वारा रखे गए खाते और अन्य अभिलेख निदेशक द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन होंगे। अधिनियम और नियम स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करते हैं कि डीओई के पास स्कूलों के खातों की तलाश करने और उनकी जांच करने का अधिकार है। हालांकि, इस नियामक शक्ति का प्रयोग उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों में बताए गए कानून

के दायरे में किया जाना चाहिए। स्कूल प्रणाली के विस्तार और शिक्षा के विकास के लिए उचित अधिशेष बनाए रखने के हकदार हैं। शैक्षिक/बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और बेहतरी के लिए धन उत्पन्न करने के लिए शुल्क में वृद्धि, जैसा कि सीनियर स्कूल के मामले में है, कानून में स्वीकार्य है। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अपनी शैक्षिक सुविधाओं और सेवाओं के आगे विकास और सम्मान के उद्देश्य से अधिशेष बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्कूल की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए अधिशेष धन का संचय आवश्यक है जो उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचे, उपकरण और संसाधनों में निवेश करने में सक्षम बनाता है। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को बुनियादी ढांचे के निर्माण या सुधार में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे नई कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं का निर्माण या नए कंप्यूटर, टैबलेट और सॉफ्टवेयर जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन। ये वेतन वृद्धि आम तौर पर अधिशेष निधि से प्राप्त की जाती है और स्कूल को नवीनतम तकनीकों के साथ अद्यतित रहने और अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन और पारिश्रमिक, संस्थान को चलाने की लागत, निवेश, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ संस्थान के विस्तार और विकास हेतु भविष्य की योजनाओं जैसे कई कारकों पर विचार करना शामिल है। चूंकि गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पूरी तरह से उनके द्वारा एकत्र की गई फीस पर निर्भर हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन आवंटित करना चाहेंगे और इसलिए, अधिशेष की योजना बनाना और बनाए रखना शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि इस तरह के फंड का उपयोग स्कूल के सुधार और विकास के बजाय पूरी तरह से व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है, तो इसे शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में माना जा सकता है।

31. वर्तमान मामले में, डीओई ने स्कूलों के पास उपलब्ध अधिशेष की पुनर्गणना की है और अभिनिर्धारित किया है कि यह उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार, उन्हें शुल्क बढ़ाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। न्यायालय की राय में डीओई द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण गलत और अस्वीकार्य है। "उचित" अधिशेष का निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा जैसे कि स्कूल का आकार, प्रदान की गई बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का स्तर, कर्मचारियों का वेतन और स्कूल की समग्र वित्तीय स्थिति। अपने शुल्क विवरण में, सीनियर स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2018-2019 में होने वाले अनुमानित खर्चों और उनके द्वारा उत्पन्न आय का एक विस्तृत चार्ट शामिल किया है। इसलिए, उनके वित्तीय संचालन में पारदर्शिता है और उन्हें धन के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रबंधन 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्कूल प्लांट का पुनर्गठन और पुनरोद्धार करने का इरादा रखता है, और इस उद्देश्य के लिए एक वास्तुकार के साथ एक अनुबंध भी किया है। चूंकि न्यायालय अपील में इस मुद्दे पर विचारण करना नहीं चाहेगी, इसलिए उसने उसमें उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता की जांच करने से परहेज किया है, फिर भी श्री गुप्ता की दलील में काफी योग्यता पाई गई है कि 1983 से संचालित सीनियर स्कूल को पुनर्निर्माण और संबद्ध गतिविधियों हेतु निधि की आवश्यकता होगी। डीओई को याद रखना चाहिए कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने प्रशासन में स्वायत्तता प्राप्त है, जिसमें इसके विकास और विस्तार की कल्पना करने और योजना बनाने की स्वायत्तता शामिल है; वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्कूलों के लिए पर्याप्त राशि क्या है, इस पर अपनी व्यक्तिपरक राय नहीं थोप सकते। वर्तमान मामले में, स्कूलों द्वारा प्रदान किये गए संपरीक्षित तुलन पत्र और सामग्री को बिना किसी वैध स्पष्टीकरण के दोबारा तैयार किया गया है। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का संपरीक्षित तुलन पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो उनकी वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को दर्शाती हैं। ये दस्तावेज स्कूल की आर्थिक स्थिति की स्पष्ट और पारदर्शी

तस्वीर प्रदान करते हैं और यह आकलन करने में मदद करते हैं कि क्या स्कूल के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और क्या फीस वृद्धि उचित है। डीओई किसी सबूत के अभाव में यह दिखाने के लिए कि खाते लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे या कर अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे, एक अपीलिय निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और उक्त वित्तीय दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं कर सकता है। प्रासंगिक रूप से, स्कूलों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और दस्तावेजों के प्रारूप पर आपत्ति डीओई द्वारा उठाई गई थी; हालाँकि, उक्त प्रश्न के उत्तर में, स्कूलों ने स्पष्ट किया था कि वे निर्धारित प्रारूप का पालन कर रहे हैं। आक्षेपित आदेश में इस मुद्दे पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। इसलिए, डीओई ने उचित कारणों का खुलासा किए बिना, या मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायीकरण का पता लगाए बिना तुलन पत्र को फिर से तैयार करने की कवायद शुरू की है। यह प्रयोग, बिना किसी वस्तुनिष्ठ मानदंड के डीओई की व्यक्तिपरक राय को दर्शाता है, जिससे पूरा अभ्यास मनमाना और अनुचित हो जाता है। छात्रों से ली जाने वाली फीस निर्धारित करने के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के अधिकार को केवल उनके बही खातों में उचित अधिशेष की उपस्थिति के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता है। डीओई स्कूलों द्वारा प्रस्तुत अधिशेष आंकड़ों की सत्यता की जांच कर सकता था, लेकिन शुल्क में वृद्धि से इनकार करने के लिए, उन्हें विश्वसनीय आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण, मुनाफाखोरी या प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाने में शामिल है। स्कूल प्रबंधन समिति ने संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट तय करने का कार्य सावधानी से किया था और शिक्षा में मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण का कोई संदेह नहीं था। डीओई ने सीनियर स्कूल की प्रस्तावित फीस वृद्धि को अस्वीकार करने में अपनी शक्तियों से अधिक काम किया है और विधि द्वारा संरक्षित स्कूलों की स्वायत्तता को प्रभावित किया है।”

(जोर दिया गया)

श्री गुप्ता बताते हैं कि, हालांकि **महावीर सीनियर मॉडल स्कूल** के निर्णय को ले.पे.अ. में चुनौती दी गई है, लेकिन उसमें कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

25. श्री गुप्ता पैरा 117 और **इंडियन स्कूल बनाम राजस्थान राज्य** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं:

*"117. इस प्रकार, महामारी की स्थिति के प्रबंधन की आड़ में, दो निजी पक्षकारगण जिनके साथ राज्य का कोई सीधा कारण संबंध नहीं है, के बीच वैध मौजूदा अनुबंधों/लेन-देन के वाणिज्यिक या आर्थिक पहलुओं के संबंध में निर्देश जारी करना या "दूसरे की कीमत पर" दो निजी पक्षकारगण में से "एक को शमन" प्रदान करना राज्य सरकार की अधिकारिता में नहीं है। यह इसकी टोपी उसके सिर जैसा है। यह एक अलग मामला है, अगर एक नीति के रूप में, राज्य सरकार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की स्कूल फीस में सब्सिडी देने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत विवादित निर्देश (स्कूल प्रबंधन को संबंधित शैक्षणिक वर्ष हेतु कम स्कूल फीस एकत्र करने के लिए) जारी करने की शक्ति अपने पास नहीं रख सकती है। हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार के पास दो निजी पक्षकारगण के बीच वैध मौजूदा अनुबंधों/लेन-देन के आर्थिक पहलुओं के संबंध में भी निर्देश जारी करने की शक्ति के अस्तित्व का दावा, यदि इसे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना के संबंध में स्वीकार किया जाता है, राज्य के लिए अपरिभाषित अनंत जोखिम और अनिश्चितता से भरा है।"*

(जोर दिया गया)

26. श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभिव्यक्ति "प्रतिव्यक्ति शुल्क" अब बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ("आरटीई रि.या.(सि.) 8794/2018

अधिनियम") की धारा 2 के खंड (ख) में "स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या अंशदान या भुगतान" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही, आरटीई अधिनियम की धारा 13(1) सभी स्कूलों को किसी बच्चे को प्रवेश देते समय, किसी भी प्रतिव्यक्ति शुल्क को इकट्ठा करने या बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावकों को किसी भी जांच प्रक्रिया के अधीन करने से रोकती है।

27. इस प्रकार, श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि 1 अगस्त 2018 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और डीएसई नियमों के नियम 190 का उल्लंघन करते हुए डीओई में निहित क्षेत्राधिकार से अधिकता में जारी किया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।

### श्री त्रिपाठी और श्री झा की प्रस्तुतियाँ

28. श्री त्रिपाठी ने तर्क दिया कि **रामजस स्कूल** का निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न है, क्योंकि वर्तमान मामले में, आक्षेपित आदेश अभिभावकों द्वारा प्राप्त शिकायत से निकला है। वह डीएसई अधिनियम की धारा 18(4)10 पर भरोसा करते हैं, जो आक्षेपित आदेश में विशिष्ट निष्कर्ष के अनुरूप है, कि स्कूल अपने द्वारा एकत्र किए गए विकास शुल्क का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा

अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा था जिनके लिए विकास शुल्क का उपयोग किया जा सकता था।

29. श्री त्रिपाठी की दलीलों को पूरा करते हुए, श्री झा ने कहा कि रामजस स्कूल के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2015-2016 तक स्कूल के वित्तीय विवरणों में विकास शुल्क के दुरुपयोग, छात्रों से एकत्र किए गए परिवहन शुल्क को न दर्शाने जैसे कोई आरोप नहीं थे, जो डीएसई अधिनियम की धारा 18(3) के सहपठित डीएसई नियमों के नियम 17511 का उल्लंघन है एवं 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक अतिशेष में अंतर है, जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 हेतु स्कूल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से परिलक्षित होता है, विशेष रूप से जिसे 1 अप्रैल 2018 के आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता-स्कूल के खिलाफ लगाया गया है। उनका यह भी प्रस्तुत करते हैं कि स्कूल द्वारा मध्यावधि में फीस बढ़ाने की पूर्व शर्तों का कोई अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि डीओई के 17 अक्टूबर 2017 के आदेश में निहित है। श्री झा प्रस्तुत करते हैं कि न ही 17 अक्टूबर 2017 के डीओई आदेश में सामान्य निर्देश 1(ख) का अनुपालन किया गया था जिसके तहत सभी स्कूलों को सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों के भुगतान में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा सुरक्षित निधि का उपयोग करने की संभाव्यता तलाशनी होगी।



30. श्री झा का कहना है कि "व्यावसायीकरण" और "प्रतिव्यक्ति शुल्क" कोई मंत्र नहीं हैं, जिन पर विशेष रूप से इतने सारे शब्दों में आरोप लगाया गया है और यदि आक्षेपित आदेश में आरोप शिक्षा के व्यावसायीकरण या प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने के समान हैं, तो यह आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त होगा। उनका कहना है कि आक्षेपित आदेश में परिलक्षित "अधिशेष" गैरकानूनी तरीके से एकत्र की गई रकम से उत्पन्न अधिशेष है।

31. इसलिए, श्री झा, श्री त्रिपाठी के कथन से सहमत हैं कि वर्तमान मामले की तुलना *रामजस स्कूल* या *महावीर सीनियर मॉडल स्कूल* से नहीं की जा सकती है।

प्रत्युत्तर में श्री कमल गुप्ता की प्रस्तुतियाँ

32. श्री गुप्ता ने प्रत्युत्तर में दोहराया कि, शिक्षा के व्यावसायीकरण या प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने के किसी विशेष निष्कर्ष के अभाव में, डीओई उस तरीके को अपने अधीन करने का हकदार नहीं है जिसमें स्कूल अपने द्वारा ली जाने वाली फीस को अपने व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर तय करता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल द्वारा फीस में बढ़ोतरी पर डीओई द्वारा केवल तभी रोक लगाई जा सकती है, जब शिक्षा में मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण हो। डीओई मुनाफाखोरी के किसी भी आरोप के अभाव में केवल

पर्याप्त अधिशेष के निष्कर्ष पर फीस बढ़ाने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

33. आक्षेपित आदेश में कथित विसंगतियों के संबंध में, श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी विसंगतियां ऐसे हर आदेश में आरोपित की जाती हैं, और यह डीओई के लिए स्कूल की फीस बढ़ाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बन सकते हैं ताकि 7वीं सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को पूरा किया जा सके।

34. श्री गुप्ता मेरा ध्यान *रामजस स्कूल* के निर्णय के पैरा 85 और 86 की ओर आकर्षित करते हैं, जो इस प्रकार है:

"85. अब, 18 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश का विज्ञापन करते हुए, आदेश को तीन अलग-अलग खंडों में विभाजित करना संभव है। आक्षेपित आदेश 26 दिसंबर, 2016 के पिछले आदेश को जारी करने के तथ्य, उसके खिलाफ याचिकाकर्ता-स्कूल द्वारा प्रतिनिधित्व, और याचिकाकर्ता-स्कूल को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने से शुरू होता है। इसके बाद, यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का "विश्लेषण" करने के लिए आगे बढ़ता है। इस विश्लेषण को तीन खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहले का शीर्षक "वित्तीय विसंगतियां", दूसरे का "अन्य विसंगतियां" है, और तीसरा, हालांकि शीर्षक रहित है, परंतु याचिकाकर्ता-स्कूल के पास उपलब्ध कथित "अधिशेष निधि" से संबंधित है। पहला खंड तीन "वित्तीय विसंगतियों" को निर्धारित करता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को केवल उस संबंध में की गई सिफारिशों का पालन करना होगा, और अपना आश्वासन दर्ज करना होगा कि वह ऐसा करेगा। दूसरा खंड, जो "अन्य विसंगतियों" से संबंधित है, याचिकाकर्ता की दलील को भी दर्ज करता है, कि विसंगतियों को

ठीक किया जाएगा, और अगले शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के समय इसके अनुपालन पर विचार किया जाएगा। इस न्यायालय के समक्ष विवाद, अनिवार्य रूप से, आक्षेपित आदेश के तीसरे खंड से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास, "1,18,42,701/- रुपए की अधिशेष निधि" थी और वह उस संबंध में एक सारणीबद्ध विवरणी प्रदान करता है। इस प्रकार देखने के बाद, आक्षेपित आदेश यह निष्कर्ष निकालने के लिए आगे बढ़ता है कि "वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सभी बजटीय व्यय को पूरा करने के बाद भी स्कूल के पास पर्याप्त धन (था) है"। इसके बाद, आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को निर्धारित लेवी के लिए अलग निधि बनाए रखने, उसके विचलन से बचने और एक अलग विकास निधि बनाए रखने के लिए कुछ निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ता है, इस प्रकार निष्कर्ष निकालने से पहले:

“और जबकि, प्रासंगिक सामग्रियों के साथ इन सिफारिशों को शिक्षा निदेशक के समक्ष विचार हेतु रखा गया था और जिन्होंने अभिलेख पर सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद पाया है कि स्कूल के पास वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय निहितार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिशेष निधि है। और इस संबंध में दिनांक 03.02.2017 के अभ्यावेदन और उसके बाद किए गए प्रस्तुतीकरण में शुल्क में वृद्धि की मंजूरी के संबंध में कोई गुणागुण नहीं पाए गए और उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया।

तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि रामजस स्कूल, सेक्टर-IV, आर.के. पुरम, नई दिल्ली- 110022, की फीस वृद्धि के अभ्यावेदन को शिक्षा निदेशक ने खारिज कर दिया है।”

(जोर दिया गया)

86. अंतिम "दिशानिर्देश" अनुसरण करते हैं।

35. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहा है। इस संदर्भ में, वह सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए *इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य* मामले में न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा के सहमति वाले निर्णय के पैरा 156 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा बनाए जा सकने वाले अधिशेष के संबंध में यह राय दी गई थी कि "उचित अधिशेष सामान्यतः 6% से 15% तक भिन्न होना चाहिए क्योंकि इस तरह अधिशेष का उपयोग प्रणाली के विस्तार और शिक्षा के विकास के लिए किया जाएगा"। इस सिद्धांत को लागू करने पर, चूंकि एक वर्ष के दौरान याचिकाकर्ता-स्कूल द्वारा ली गई फीस से रिटर्न ₹ 18 करोड़ था, ₹ 2.7 करोड़, फीस के 15% के रूप में, एक उचित अधिशेष होगा, जबकि आक्षेपित आदेश के अनुसार, अधिशेष याचिकाकर्ता-स्कूल के फंड में केवल ₹ 2.55 करोड़ थे। इसलिए, तथ्यों के आधार पर भी, यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपने मामलों को चलाने के लिए आवश्यक राशि से अधिक कोई अधिशेष बनाए हुए था।

36. *रामजस स्कूल* में निर्णय से, श्री गुप्ता निम्नलिखित अंशों पर जोर देते हैं:

"15. उपरोक्त मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर न्यायालय के उत्तरों को बहुमत की राय (न्यायाधीश बी.एन. किरपाल द्वारा लिखित, जैसा कि वह उस समय थे) के निष्कर्ष की ओर सूचीबद्ध किया गया इस मुद्दे से निपटने के दौरान कि क्या वैधानिक प्रावधान, प्रशासन के विनियमन तथ्यों जैसे शैक्षिक एजेंसियों पर नियंत्रण, शासी निकायों पर नियंत्रण, कर्मचारियों,

कर्मचारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों की संबद्धता और नियुक्ति की शर्तें, उनकी सेवा शर्तों सहित और फीस का विनियमन आदि, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्थान को प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं लेना चाहिए"। इसी तरह, **जे.पी. उन्नीकृष्णन** मामले में अपने पहले के दृष्टिकोण की स्थिरता की जांच करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में उसके द्वारा बनाई गई योजना को असंवैधानिक करार देते हुए, फिर भी, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“हालांकि, यह सिद्धांत कि प्रतिव्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, सही है। हालांकि, सुविधाओं के विस्तार और वृद्धि की लागत को पूरा करने के लिए उचित अधिशेष मुनाफाखोरी नहीं है।

(जोर दिया गया)

\*\*\*\*\*

47. आक्षेपित आदेश सं. एफ. डीई-15/एक्ट-1/डब्ल्यूपीसी-4109/पीएआरटी/13/831, दिनांकित 18 जुलाई, 2017 के माध्यम से, डीओई ने डीओई द्वारा जारी 26 दिसंबर, 2016 के आदेश के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 30 जनवरी, 2017 के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया गया है, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह याचिकाकर्ता के इस कथन के संबंध में निःशब्द है कि, एक स्कूल के रूप में, भूमि का आवंटन, जिसे किसी भी 'भूमि खंड' द्वारा सशर्त नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता के खातों की लेखापरीक्षा, उसके निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2016 के आदेश के अभिलेख और जारी करना शुरू से ही गलत था।

इसके बजाय, आक्षेपित आदेश शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए अपनी फीस बढ़ाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की अस्वीकृति को उचित ठहराने हेतु आगे बढ़ता है, इस प्रक्रिया में, निम्नलिखित निष्कर्ष पर वापस आता है:

(निष्कर्षों को छोड़ दिया गया है क्योंकि संपूर्ण आदेश इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है)

\*\*\*\*\*

56. याचिकाकर्ता सक्षमता के साथ-साथ गुणागुण के आधार पर, आक्षेपित आदेश की आलोचना करता है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि डीओई के पास याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर अपील करने, अपनी फीस बढ़ाने, सिवाय इसके कि यह सुनिश्चित करने की सीमा तक कि याचिकाकर्ता प्रतिव्यक्ति शुल्क, या मुनाफाखोरी में शामिल नहीं है, के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के परिसर का निरीक्षण करने, खातों का लेखा परीक्षित करने और 26 दिसंबर, 2016 पूर्वोक्त के आदेश को पारित करने की पूरी प्रक्रिया, जैसा कि यह प्रस्तुत करने की मांग की गई है, एक गलत धारणा पर आधारित थी। याचिकाकर्ता को डीओई द्वारा जारी 16 अप्रैल, 2016 पूर्वोक्त और 15 जुलाई, 2016 पूर्वोक्त के आदेशों द्वारा सुरक्षित किया गया था। गुणागुण के आधार पर भी, याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि फीस में वृद्धि, उसकी ओर से उचित थी, और एक गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल के रूप में, याचिकाकर्ता अपनी फीस के निर्धारण के संबंध में कुछ हद तक स्वायत्तता का हकदार था। जिसे डीओई द्वारा अनुमोदन के अधीन नहीं बनाया जा सका। इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि डीओई द्वारा, याचिकाकर्ता के खिलाफ, 26 दिसंबर, 2016 के आदेश में, या 18 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश में, याचिकाकर्ता के प्रतिव्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी में शामिल होने का कोई परिणाम नहीं है।

\*\*\*\*\*

59. याचिकाकर्ता द्वारा लिखित रूप में और साथ ही विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस के दौरान, 18 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश के गुणागुण और 1,18,42,701/- रुपए के कथित अधिशेष की गणना

के तरीके के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियाँ भी दी गई हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता का कहना है कि, डीओई के अनुसार, बिना किसी स्पष्टीकरण, याचिकाकर्ता के पास कथित अधिशेष, दिनांक 26 दिसंबर, 2016 'पूर्वोक्त के आदेश में 8,45,05,819/- रुपए के आंकड़े से कम होकर दिनांक 18 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश में 1,18,42,701/- रुपए हो गया है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि यह अपने स्वयं मनमाने ढंग से प्रकट होता है जिसमें डीओई शैक्षणिक सत्र 2016-2017 हेतु अपनी फीस बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की जांच कर रहा था।

\*\*

\*\*

67. 18 जुलाई, 2017, के विवादित आदेश, में डी.ओ.ई. द्वारा याचिकाकर्ता-स्कूल के साथ अभिकथित अधिशेष की गणना करने के तरीके को उचित ठहराते हुए विस्तृत निवेदन भी अभिलेख पर रखे गए हैं।

\*\*\*\*\*

77. इसलिए, इस न्यायालय की राय में, जहाँ तक डी.ओ.ई. की शक्ति और अधिकार का दायरे का संबंध है, एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा शुल्क के निर्धारण में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अस्पष्ट क्षेत्र नहीं है। यह नाकारा नहीं जा सकता है; कि डी.ओ.ई. कुछ हद तक यह नियंत्रण रखती है आखिरकार, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एकल स्वायत्त नहीं हैं। डी.ओ.ई. की नियामक शक्ति, हालांकि, केवल ऐसे गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के उद्देश्य से मौजूद है। वास्तव में, इस कानूनी स्थिति को डी.ओ.ई. के दिनांक 26 दिसंबर, 2016 के आदेश में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जो स्पष्ट रूप से तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि "शिक्षा निदेशालय को शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए शुल्क और अन्य

भरों को विनियमित करने का अधिकार है।" "उच्चतम न्यायालय के अनुसार, शिक्षा का व्यावसायीकरण उन मामलों से संबंधित होगा जहाँ संस्थान या तो प्रतिव्यक्ति फीस लेता है या मुनाफाखोरी में लिप्त होता है। यहाँ पहले उद्धृत अधिकारियों के एक संयुक्त और समग्र अध्ययन से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय ने "शिक्षा के व्यावसायीकरण" की अवधारणा नहीं दी है, विशिष्ट रूप में जहाँ तक यह अवधारणा गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होती है, प्रतिव्यक्ति फीस और मुनाफाखोरी से अलग या अलग है। बल्कि, ऐसे संस्थानों के मामले में, "शिक्षा का व्यावसायीकरण" एक अलग श्रेणी का गठन करता है, जिसमें प्रतिव्यक्ति फीस और मुनाफाखोरी शामिल हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा पहचानी गई और अलग की गई दो अलग-अलग श्रेणी हैं। गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के मामले में, यह केवल वहीं है जहां वे प्रतिव्यक्ति फीस लेते पाए जाते हैं, या मुनाफाखोरी में लिप्त पाए जाते हैं, कि उन्हें शिक्षा के व्यावसायीकरण का दोषी ठहराया जा सकता है, और अन्यथा नहीं।

\*\*\*\*\*

79. डी.ओ.ई. ने अपने जवाबी-शपथपत्र के साथ, याचिकाकर्ता के खर्चों के विभिन्न शीर्षों के विवरण के संबंध में डी.ओ.ई. की टिप्पणियों को निर्धारित करते हुए एक सारणीबद्ध बयान दायर किया है। उक्त सारणीबद्ध बयान के नोट 6 में, आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा, "खरीद के लिए इसकी आवश्यकता से अधिक विकास शुल्क एकत्र करके "विकास निधि का संचय", फर्नीचर और फिक्स्चर और उपकरणों का उन्नयन और प्रतिस्थापन खरीद " हमारे समक्ष उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेख में, याचिकाकर्ता द्वारा "मुनाफाखोरी" में लिप्त होने का कोई अन्य संदर्भ नहीं है। हमारे सामने संपूर्ण "मुनाफाखोरी" का पूर्व-उद्धृत संदर्भ भी, इस न्यायालय के समक्ष डी.ओ.ई. द्वारा याचिकाकर्ता के खर्चों के विभिन्न शीर्षों के बारे में दायर टिप्पणियों में है, न कि दिनांकित 18 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश या दिनांकित 26 दिसंबर, 2016 के आदेश में, जिसे वह बरकरार



रखना चाहता था। उक्त आदेशों में से किसी में भी इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिव्यक्ति फीस लेने या मुनाफाखोरी करने में लिप्त था।

\*\*\*\*\*

85. अब, 18 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश का उल्लेख करते हुए, आदेश को तीन अलग-अलग खंडों में विभाजित करना संभव है। आक्षेपित आदेश की शुरुआत 26 दिसंबर, 2016 के पूर्व आदेश को जारी करने, याचिकाकर्ता-स्कूल द्वारा उसके खिलाफ प्रतिनिधित्व और याचिकाकर्ता-स्कूल को व्यक्तिगत सुनवाई के अनुदान के तथ्य पर ध्यान देने के साथ होती है। इसके बाद यह याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलीलों का "विश्लेषण" करने के लिए आगे बढ़ता है। इस विश्लेषण को तीन खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहले का शीर्षक "वित्तीय विसंगतियां" है, दूसरा "अन्य विसंगतियां" है, और तीसरा, हालांकि शीर्षकहीन है, याचिकाकर्ता-स्कूल के पास उपलब्ध कथित "अधिशेष निधि" से संबंधित है। पहला खंड तीन "वित्तीय विसंगतियों" को निर्धारित करता है, जिसमें केवल याचिकाकर्ता को उस संबंध में की गई सिफारिशों का पालन करने और अपना आश्वासन दर्ज करने की आवश्यकता होती है, कि वह ऐसा करेगा। "अन्य विसंगतियों" से निपटने वाला दूसरा खंड भी याचिकाकर्ता के निवेदन को दर्ज करता है, कि विसंगतियों को ठीक किया जाएगा, और अगले शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के समय इसके अनुपालन पर विचार करता है। इस न्यायालय के समक्ष विवाद, अनिवार्य रूप से, आक्षेपित आदेश की तीसरे खंड से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास इसके साथ, "1,18,42,701/- रुपए की अधिशेष निधि", और उस संबंध में एक सारणीबद्ध कथन प्रदान करता है। इस प्रकार देखने के बाद, आक्षेपित आदेश एक निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है कि "वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सभी बजट व्यय को पूरा करने के बाद भी स्कूल के पास पर्याप्त धन था।" इसके बाद, आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को कुछ निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि निर्धारित शुल्कों के लिए अलग-

अलग धन बनाए रखा जा सके, इसके परिवर्तन से बचा जा सके और इस प्रकार निष्कर्ष निकालने से पहले एक पृथक विकास निधि, बनाए रखें:

" और जबकि, प्रासंगिक सामग्रियों के साथ इन सिफारिशों को शिक्षा निदेशक के समक्ष विचार के लिए रखा गया था और जिन्होंने अभिलेख पर सभी सामग्री पर विचार करने के बाद पाया है कि स्कूल में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय प्रभावों को लागू करने और दिनांकित 03.02.2017 प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त अधिशेष है इसके बाद इस संबंध में किए गए निवेदनों में शुल्क में वृद्धि की मंजूरी के संबंध में किसी प्रकार की कोई गुणागुण नहीं पाई गई और उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर इसे खारिज कर दिया जाता है।

तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि रामजस स्कूल, सेक्टर-IV, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022 की शुल्क वृद्धि के व्यपदेशन को शिक्षा निदेशक द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(जोर दिया गया)

37. श्री गुप्ता महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के निम्नलिखित अंशों को भी उद्धृत करते हैं:

"सन्दर्भ : अधिशेष और प्राप्यता निधियों की उपलब्धता के निष्कर्ष

26. याचीगण के अनुरोध को अस्वीकार करने का मूल तर्क अधिशेष का अस्तित्व और स्कूलों के व्यवस्थान में धन की पर्याप्तता है। यह आक्षेपित क्रम के निम्नलिखित उद्धरण से समझने योग्य है:

" अभिलेख-पर-सभी सामग्री की विस्तृत जाँच करने और विद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात , अंत में यह मूल्यांकन/निष्कर्ष निकाला गया कि :

वर्ष 2018-2019 के लिए उपलब्ध कुल राशि रुपए 9,67,96,579 और रुपए 6,49,46,324 है, जिसमें से वर्ष 2018-2019 में महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के संबंध में

क्रमशः रुपए 7,48,15,500 और रुपए 78,03,236 होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के लिए क्रमशः रुपए 2,19,81,079 रुपए और 5,71,43,088 का शुद्ध अधिशेष है।

\*\*\*\*\*

महावीर सीनियर मॉडल स्कूल द्वारा डी.एस.ई.ए., 1973 की धारा 17 (3) के तहत शुल्क के विवरण के साथ प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए अनुमानित खर्च के अनुसार, स्कूल ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान कुल खर्च का अनुमान रुपए 9,44,60,500 (विकास शुल्क के विरुद्ध 1205000 रुपये के पूंजीगत व्यय सहित) लगाया था। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के इस बजट व्यय को पूंजीगत व्यय की राशि (विकास निधि के बदले में किए जाने वाले), सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान (ऊपर दी गई तालिका में अलग से माना गया), और मूल्यहास (गैर-नकद व्यय) के साथ समायोजित किया गया है, और ऊपर दी गई तालिका में रुपए 7,48,15,50 के शुद्ध व्यय पर विचार किया गया है। इसके अलावा महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनंतिम वित्तीय विवरणों में रुपए 1,14,21,270 के कुल व्यय के मुकाबले, 2017-2018 की शुद्ध राशि पर सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान के समायोजन के बाद रुपए 78,03,236 की शुद्ध राशि पर विचार किया गया है। (ऊपर दी गई तालिका में अलग से विचार किया गया), आरक्षित निधि के प्रावधान (ऊपर दी गई तालिका में अलग से विचार किया गया) और मूल्यहास (गैर-नकद व्यय), क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट खर्च स्कूल द्वारा अलग से प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए शुल्क विवरण की उपरोक्त जांच और बाद में निवेदनों और स्कूल के अभ्यावेदन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्कूल के पास वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए सभी बजट व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है।

(ii) शिक्षा निदेशालय द्वारा 16 अप्रैल 2010 के परिपत्र संख्या 1978 के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि 'सभी स्कूलों को, सबसे पहले, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों के भुगतान में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा निधि/संचय का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना और उसे समाप्त करना चाहिए। आरक्षित निधि का एक हिस्सा जिसका वर्षों से उपयोग नहीं किया गया है, का उपयोग शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव से पहले कमी को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। स्कूल के पास मौजूदा शुल्क संरचना के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए स्कूल के संचालन को जारी रखने के लिए पर्याप्त धन है[...]"

27. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के शुल्क विवरणों में उल्लिखित निधियों की पर्याप्तता की जांच की है और उन्हें कई शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया है, और फिर निष्कर्ष निकाला है कि जूनियर स्कूल के पास 5,71,43,088 रुपये और सीनियर स्कूल के पास 2,19,81,079 रुपये का अधिशेष था। इन संचित भंडारों के आधार पर, शिक्षा विभाग ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता स्कूलों ने डी.ओ.ई. की गणना के आधार को चुनौती दी है और दोनों पक्षों के उपलब्ध निधियों के तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किए। हालांकि, न्यायालय को आंकड़ों का समर्थन करने वाले अंकगणितीय कार्यों जो की विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक प्रकृति के हैं, का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे डी.ओ.ई. के अधिकारिता के दायरे में आते हैं, आक्षेपित आदेश में अपनी जाँच को निर्धारित निष्कर्षों तक सीमित रखेंगे।

\*\*\*\*\*

30. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के खातों और अन्य अभिलेखों की जाँच करने की डी.ओ.ई. की शक्ति का स्रोत डी.एस.ई.ए. (यहाँ ऊपर जाँच की गई ) की धारा 17(3) और डी.इस.ई.आर. के नियम 180 (3) में मिलता है। नियम 180 (3) के तहत, एक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल द्वारा रखे गए खाते और अन्य अभिलेख निदेशक द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों और

निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जाँच के अधीन होंगे। अधिनियम और नियम किसी भी अनिश्चित शर्तों में निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि डी.ओ.ई. के पास स्कूलों के खातों की तलाश और जाँच करने का अधिकार है। हालाँकि, इस नियामक शक्ति का प्रयोग उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों में बताए गए कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। स्कूल प्रणाली के विस्तार और शिक्षा के विकास के लिए उचित अधिशेष बनाए रखने के हकदार है। शैक्षणिक/बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और बेहतरी के लिए धन जुटाने के लिए शुल्क में वृद्धि, जैसा कि सीनियर स्कूल के मामले में है, कानून में स्वीकृत है। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आगे के विकास और अपनी शैक्षिक सुविधाओं और सेवाओं के सम्मान के उद्देश्य से अधिशेष बनाए रखें। स्कूल की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए अधिशेष धन का संचय आवश्यक है जो उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचे, उपकरणों और संसाधनों में निवेश करने में सक्षम बनाता है। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को बुनियादी ढांचे के निर्माण या सुधार में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि नई कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं या प्रौद्योगिकी उन्नयन, जैसे कि नए कंप्यूटर, टैबलेट और सॉफ्टवेयर का निर्माण। ये वेतनवृद्धि आम तौर पर अधिशेष निधि से प्राप्त की जाती है और स्कूल को नवीनतम तकनीकों के साथ कदम से कदम बढ़ाते रहने और अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, किसी भी शैक्षणिक सत्र सम्बन्धी वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और पारिश्रमिक, प्रतिष्ठान चलाने की लागत, निवेश, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ संस्थान के विस्तार और विकास के लिए भविष्य की योजनाओं जैसे कई कारकों पर विचार किया जाता है। चूंकि गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पूरी तरह से उनके द्वारा एकत्र किए गए शुल्क पर निर्भर हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन निर्धारित करना चाहेंगे और इसलिए, अधिशेष की योजना बनाने और उसे बनाए रखने को शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में

नहीं माना जा सकता है। यदि इस तरह के धन का उपयोग स्कूल के सुधार और विकास के बजाय विशुद्ध रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है, तो ही इसे शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में माना जा सकता है।”

38. श्री गुप्ता यह भी इंगित करते हैं कि इन दोनों मामलों में अर्थात् **रामजस स्कूल और महावीर सीनियर मॉडल स्कूल**, न्यायालय ने मामले के प्रतिपेक्षण को डी.ओ.ई. को जानबूझकर नहीं सौंपने का निर्णय लिया। वह इस न्यायालय से वर्तमान मामले में भी ऐसा ही करने का आग्रह करेंगे।

श्री झा, प्रत्युत्तर के जवाब में

39. श्री झा, प्रत्युत्तर के जवाब में, **मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम रिसर्च सेंटर बनाम मध्यप्रदेश राज्य**. में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और **सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बनाम डी. ओ. ई.<sup>16</sup>** में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय से निम्नलिखित पैराग्राफ का उद्धरण देते हैं:

मॉडर्न डेंटल कॉलेज से

"15. प्रश्नगत अधिनियम की धारा 4(1), 4(8) और 9 के सम्बन्ध में शुल्क के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने इन शैक्षिक संस्थानों, के अधिकारों को मान्यता दी जैसा की **टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन** में पाया गया है, उस पर निर्णय शुल्क निजी शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना है। इसके बावजूद, वही निर्णय राज्य को शैक्षणिक संस्थान की शक्ति के प्रयोग को संस्थान विनियमित करने की शक्ति देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई "मुनाफाखोरी" न हो और 2007 अधिनियम की धारा 4 और 9 का उद्देश्य केवल उस उद्देश्य को प्राप्त करना था। संक्षेप में, ये प्रावधान समिति को यह संतुष्ट

करने का अधिकार देते हैं कि एक निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं है और यह अधिनियम 2007 की धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था। न्यायालय ने कहा की धारा 9(1) में उल्लिखित कारक शुल्क के निर्धारण के लिए प्रासंगिक कारक थे क्योंकि उन्होंने ऐसे शुल्क का निर्धारण सुनिश्चित किया था जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति, भूमि और भवन की लागत, उपलब्ध आधारभूत संरचना, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और उपकरण, प्रशासन और रखरखाव पर खर्च, के साथ पेशेवर संस्थानों की उन्नति और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष पर विचार करता था। यह वास्तव में आदेश था।

40. यह इंगित करना आवश्यक हो जाता है कि शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन को "व्यवसाय" के रूप में मानते हुए, न्यायालय ने श्रेणीगत किया कि इस गतिविधि को "व्यवसाय" या "पेशे" के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस अधिकार से व्यवसाय जारी रखना कि शिक्षा भी वही है यह अन्य व्यवसायों या व्यापार गतिविधियों यहाँ तक कि अन्य पेशों के बराबर नहीं रखा गया है। यह एक भिन्न श्रेणी है जिसे टी.एम.ए.पे. पाई फाउंडेशन में इस न्यायालय द्वारा प्रथक किया गया था। यहाँ ऐसा न करने का एक एक विशिष्ट उद्देश्य था। शिक्षा को "कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं" के आधार पर एक महान "व्यवसाय" के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, जो लोग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करते हैं और उनका प्रबंधन कर रहे हैं, उनसे मुनाफाखोरी या इस नेक गतिविधि का व्यावसायीकरण करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार और शुल्क निर्धारण के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी। जहां तक छात्रों के प्रवेश का सवाल है, न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब उच्च शिक्षा की बात आती है, खासकर व्यावसायिक संस्थानों में तो ऐसे प्रवेश गुणागुण के आधार पर होने चाहिए।

\*\*\*\*\*

48. इस मामले पर पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया था। और यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन के निर्णय के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और शुल्क संरचना का निर्धारण करने के लिए दो समितियों को नियामक उपायों के रूप में अनुमेय किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे छात्र समुदाय के साथ-साथ अल्पसंख्यक स्वयं गैर-शोषक शर्तों पर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखते हैं। इससे अनुच्छेद 30(1) या अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन नहीं होता। ऐसा देखा गया:

*"145. ... जब तक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता द्वारा निर्देशित उपलब्ध सीटों पर प्रवेश देने की बुरी और अनुचित प्रथा पर अंकुश लगाना असंभव होगा।।"*

(जोर दिया गया)

इस आधार पर, संस्थानों द्वारा अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को स्वीकार करने के बाद पश्च संपरीक्षा के द्वारा द्वारा समितियों का गठन किया गया था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों का सुझाव, को खारिज कर दिया। इस प्रकार, समितियों को दाखिलों और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए तब तक जारी रखने की अनुमति दी गई जब तक कि राज्यों द्वारा एक यथोचित विधान या विनियम नहीं बनाए जाते। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि वे प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत, यथोचित विधान बनाएं। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले में पैरा 68 को यह कहते हुए समझाया गया था कि प्रबंधन को कुछ सीटें



आरक्षित करने की अनुमति देने वाली टिप्पणियां स्थानीय जरूरतों के अनुसार गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए थीं। इसका मतलब गुणागुण को नजरअंदाज करना नहीं था। यह भी अभिनिर्धारित कि सी.ई.टी. आयोजित किया जा सकता है, अन्यथा गुणागुण आकस्मिक हो जाती है। इस प्रकार, जब कानून में ऐसा प्रावधान हो तो किसी राज्य अभिकरण द्वारा सी.ई.टी. आयोजित किए जाने पर कोई रोक नहीं है।

\*\*\*\*\*

71. हम खुद को फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हालांकि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार को "व्यवसाय" करने के अधिकार के रूप में माना जाता है, जो कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत मौलिक अधिकार है, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में न्यायालय ने भी ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण में लिप्त नहीं होने के लिए आगाह किया था। यह निर्णय इन शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिव्यक्ति फीस लेने से भी पूरी तरह से रोकता है। यह अपीलार्थीगण द्वारा माना जाता है कि व्यावसायीकरण और शोषण की अनुमति नहीं है और शैक्षणिक संस्थानों से "कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं" के आधार पर चलने की उम्मीद की जाती है। निस्संदेह, यह भी माना गया कि शिक्षा की लागत एक संस्था से दूसरी संस्था की तुलना में भिन्न हो सकती है - कारकों संबंध में शुल्क निर्धारित करते समय कई परिवर्तनशील और इस को यह भी माना जाता है कि शैक्षणिक संस्थान शुल्क ले सकते हैं जो इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों का ध्यान रखेगा और साथ ही भावी पीढ़ी के लिए शिक्षा के विस्तार का प्रावधान भी करेगा। साथ ही उपस्थित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अनुचित मांग नहीं की जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए, केवल "उचित अधिशेष" उत्पन्न किया जा सकता है।

\*\*

75. संक्षेप में कहें तो, हालांकि शुल्क शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और यह ऐसे प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने

वाली शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर संस्थान से संस्थान में भिन्न हो सकता है, व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षणिक संस्थान व्यावसायीकरण और शोषण में लिप्त न हो, सरकार नियामक उपाय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्तियों से सुसज्जित है कि यह ये शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यावश्यक और मूलभूत भूमिका निभाते रहें न कि धन अर्जित करने के लिए है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है की जब सरकार के ध्यान में यह आता है की कोई विशेष संस्थान शुल्क या अन्य शुल्क ले रहा है जो की अत्यधिक है, तो उसे ऐसे संस्थान को इसे कम करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।

\*\*\*\*\*

80. *पी. ए. इनामदार* के निर्णय में, हालांकि *इस्लामी अकादमी ऑफ़ एजुकेशन*, के निर्णय की समीक्षा करने की मांग की गई थी, लेकिन समितियों के तंत्र को अबाधित रखने की व्यवस्था छोड़ दी गई। *पी. ए. इनामदार*, के निर्णय में पैरा 129 में, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य विनियमन न्यूनतम होना चाहिये और केवल प्रवेश प्रक्रिया में केवल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए होना चाहिए और अत्यधिक धन प्रतिव्यक्ति फीस वसूल कर होने वाले शोषण को देखना। पैरा 140 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पूंजी शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, मुनाफाखोरी की भी अनुमति नहीं है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि (एस.सी.सी. पी. 605, पैरा 140) यह शिक्षा के व्यावसायीकरण की कठोर वास्तविकताओं और कई संस्थानों द्वारा अपने निजी या स्वार्थी हितों के लिए बड़ी मात्रा में कमाई करने के लिए अपनाई जा रही बुरी प्रथाओं के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। इसके तहत बनाए गए प्रश्न 3 के संबंध में, जो निजी संस्थानों के मामले में सरकारी विनियमन के संबंध में था, इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा

141 में जवाब दिया कि प्रत्येक संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे मुनाफाखोरी को रोकने के हित में विनियमित किया जा सकता है और साथ ही किसी प्रकार की प्रतिव्यक्ति फीस नहीं ली जा सकती है। पैरा 145 में, पश्च संपरीक्षा के पश्चात या जाँच के सुझाव को अस्वीकार कर दिया जाता है यदि संस्थान अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को अपनाते हैं क्योंकि इस न्यायालय का विचार था कि शुल्क के निर्धारण को प्रारंभिक चरण स्वयं में ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए।

81. यह उपरोक्त संदर्भ में है कि हमें इस प्रश्न का निर्धारण करना होगा कि क्या शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का उल्लंघन करते हैं या वे विनियामक प्रकृति के हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) को ध्यान में रखते हुए अनुमेय है, यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास मुनाफाखोरी को रोकने के हित में शुल्क निर्धारण को विनियमित करने की शक्ति है और इसके अलावा शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना है। जब हम 2007 के अधिनियम की धारा 9 को बारीकी से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि शुल्क निर्धारित करते समय जिन मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे वास्तव में वही हैं जो ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित किए गए हैं। यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति, अर्थात् *प्रवेश और शुल्क नियामक समिति*, केवल एक नियामक कार्य का निर्वहन कर रही है। एक विशेष शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों से जो शुल्क लेना चाहता है, वह उक्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ही सुझाया जाना चाहिए। समिति को इस उद्देश्य से अधिकार दिया गया है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क के रूप में निम्नलिखित शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के लिए और 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित बोधगम्य कारकों पर आधारित था। इसलिए, हमारे विचार में, यह केवल एक विनियामक उपाय है और अपने स्वयं के शुल्क तय करने के

लिए शैक्षणिक संस्थान की शक्तियों को नहीं छीनता है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में इन प्रावधानों का विश्लेषण।[निजी डेंटल और मेडिकल कॉलेजों का संघ बनाम मध्य प्रदेश राज्य<sup>18</sup>], पैरा 42 में निहित, पूरी तरह से आदेश में है, जिसमें इसे नीचे के रूप में देखा जाता है।

"42. हमारा विचार है कि 2007 अधिनियम की धारा 4 (1) और 4(8) को 2007 अधिनियम की धारा 9 (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उन कारकों से संबंधित है जिन्हें समिति द्वारा एक निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। 2007 के अधिनियम की धारा 9 के उप-खंड (1) को पढ़ने से पता चलेगा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान का स्थान, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति, भूमि और भवन की लागत, उपलब्ध बुनियादी ढांचा, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और उपकरण, प्रशासन और रखरखाव पर खर्च, व्यावसायिक संस्थान के विकास और प्रगति के लिए आवश्यकता होती उचित अधिशेष की और किसी अन्य प्रासंगिक कारक को समिति द्वारा एक निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, समिति को शुल्क निर्धारित करते समय विशेष रूप से निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान के सभी लागत घटकों के साथ-साथ संस्थान के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक उचित अधिशेष और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक अन्य सभी कारकों पर विचार करना होगा। 2007 के अधिनियम की धारा 4(8) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि समिति किसी निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक

शैक्षणिक संस्थान से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जो समिति को प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान उन शुल्कों के संबंध में जानकारी जुटा सकता है जो वह प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से सभी लागत घटकों को ध्यान में रखते हुए लेने का प्रस्ताव करता है, जो उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक उचित अधिशेष है। वृद्धि और विकास और अन्य प्रासंगिक कारक में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 2007 अधिनियम की धारा 9(1) में दिया और समिति का कार्य केवल यह पता लगाना है कि संस्थान के समक्ष सुने जाने का उचित अवसर दिया गया जैसा कि 2007 अधिनियम की धारा 9 (2) में उपबंध किया गया है कि क्या संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क छात्र से लिया जाने वाला 2007 के अधिनियम की धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित हैं और इसके शिक्षा का लाभ और व्यावसायीकरण के बराबर नहीं था। "निर्धारण" शब्द को *ब्लैक लॉ डिक्शनरी*, के आठवें संस्करण में, परिभाषित किया गया है। जिसका अर्थ न्यायालय या प्रशासनिक अभिकरण द्वारा अंतिम निर्णय। इसलिए, समिति, शुल्क का निर्धारण करते समय प्रस्तावित शुल्क को केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही अंतिम मंजूरी देती है कि यह 2007 अधिनियम की धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है और इसमें कोई मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण नहीं है। 2007 अधिनियम की धारा 4(1) में अभिव्यक्ति "फीस निर्धारण" का अर्थ है कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से लिया जाने वाला शुल्क छात्र-दर-छात्र अलग-अलग नहीं होगा और एक निश्चित अवधि के लिए भी तय रहेगा। जो

की 2007 अधिनियम की धारा 4(8) में उल्लेखित है। जैसा की उच्चतम न्यायालय द्वारा *पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आरबीआई*<sup>9</sup> में अभिनिर्धारित किया गया है न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कानून के प्रावधानों के सार की जाँच करनी होगी कि क्या कानून के प्रावधान आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगते हैं। प्रावधानों में 2007 के अधिनियम की धारा 4(1), 4(8) और 9 में प्रावधान समिति को केवल इस बात से संतुष्ट होने का अधिकार देता है कि एक निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायिक के बराबर नहीं है और यह 2007 अधिनियम की धारा 9(1) में उल्लिखित कारक पर आधारित था। इसलिए, 2007 अधिनियम के प्रावधान निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान के अपनी फीस वसूलने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।"

82. राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली सरकारी परीक्षा के माध्यम से छात्रों के प्रवेश से संबंधित प्रावधान और प्रावधान निगरानी के लिए एक समिति की स्थापना द्वारा शुल्क निर्धारण से संबंधित जो देखेगा कि संस्थान वो राशी न ले जिससे प्रतिव्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी हो यह उचित प्रतिबंध हैं और किसी भी संवैधानिक दोष से ग्रस्त नहीं हैं। इसलिए, अधिनियम और नियमों के प्रावधान **पीए इनामदार** में निहित भावनाओं और निर्देशों के अनुरूप हैं।

\*\*\*\*\*

87. विनियामक तंत्र, या जिसे विनियामक अर्थशास्त्र कहा जाता है, वर्तमान समय की व्यवस्था है। पिछले 60-70 वर्षों में, इस देश की आर्थिक नीति अबंध नीति से मिश्रित अर्थव्यवस्था तक , यह से विनियामक शासन के साथ उदार अर्थव्यवस्था तक गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आगमन के

साथ, सार्वजनिक क्षेत्र में तेजी आई और विमानन, बीमा, रेलवे, बिजली/बिजली, दूरसंचार आदि जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार हो गया। इस अवधि के दौरान सरकार के सख्त नियंत्रण के साथ लाइसेंस/परमिट राज प्रचलित था, यहाँ तक कि उन उद्योगों के संबंध में भी जहाँ निजी क्षेत्रों को संचालित करने की अनुमति थी। हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 90 के दशक की शुरुआत में एल.पी.जी .मॉडल यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों का अनुभव किया। जुलाई 1991, में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए सुधारों की शुरुआत के साथ, भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आर्थिक परिवर्तन की इस अवधि का अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।”

**सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी. पब्लिक स्कूल से**

"13. पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए दुग्गल समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:-

" 7.19. इन विसंगतियों पर काबू पाने के साथ-साथ अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों सहित स्कूलों द्वारा किसी भी संभावित 'दुरुपयोग' की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए, समिति ने सिफारिश की है कि लगाए गए शुल्कों को नीचे दी गई चार व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

- i) पहली श्रेणी में पंजीकरण शुल्क और छात्र के प्रवेश के समय लगाए गए सभी 'एक बार के शुल्क' जैसे प्रवेश शुल्क और जमानत राशि शामिल होनी चाहिए। जबकि डी.एस.ई. अधिनियम, 1973 की धारा 16 के तहत निर्धारित नियम 135,137 और 138 के तहत छात्र के पूरे प्रवास के दौरान प्रवेश शुल्क एक से अधिक बार नहीं लिया जाना चाहिए, स्कूलों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे किसी छात्र के स्कूल छोड़ने के समय जमानत राशि बिना

छात्र/अभिभावक द्वारा इसका दावा किए ब्याज सहित वापिस करे।

- ii) दूसरी श्रेणी में "शिक्षण शुल्क" शामिल होना चाहिए। यह इस तरह से तय किया जाना चाहिए कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10 (1) के तहत उल्लिखित महंगाई भत्ता, बोनस और सभी अंतिम लाभों के प्रावधान सहित प्रतिष्ठान की मानक लागत को शामिल किया जा सके; साथ ही पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विज्ञान शुल्क और दसवीं कक्षा तक कंप्यूटर शुल्क और परीक्षा जैसी पाठ्यक्रम संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए राजस्व प्रकृति के सभी खर्चों को भी शामिल किया जा सके। और प्रतिष्ठान की मानक लागत निर्धारित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मापदंड, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्र-शिक्षक अनुपात और प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का अनुपात हो सकता है।
- iii) तीसरी श्रेणी 'वार्षिक शुल्क' की होनी चाहिए-एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अधिकतम अनुशासन की आवश्यकता है। यह शुल्क इस तरह से निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि है राजस्व की प्रकृति के सभी व्यय को पूरा करने के लिए प्रयाप्त हो जो (ii) उपरोक्त में शामिल नहीं, खेल के मैदान पर अतिरिक्त और खर्च, खेल उपकरण, व्यायामशाला, सांस्कृतिक और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर व्यय, जो स्कूल की पाठ्यक्रम गतिविधि से अलग हों।
- iv) चौथी श्रेणी में स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सभी 'निर्धारित शुल्क' शामिल होने चाहिए, जो केवल 'उपयोगकर्ता' छात्रों से उन सुविधाओं लाभ उठाने के संबंध में वसूल किए जाने चाहिए, जैसे कि परिवहन शुल्क, स्विमिंग पूल शुल्क, घुड़सवारी, टेनिस, मध्याह्न भोजन आदि। निर्धारित शुल्कों से होने वाली आय को केवल उस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए ये एकत्र किए जाते हैं, जिसमें स्कूल की भूमिका 'कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं' के आधार पर सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक उत्प्रेरक या सुविधा प्रदाता तक सीमित होनी चाहिए।



7.20 'निर्धारित' गतिविधियों से संबंधित सभी लेनदेन स्कूल खातों के अभिन्न भाग से होने चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी सेवाओं के खाते एक अवधि में आत्मसंतुलन कर रहे हैं-, स्कूल द्वारा प्रत्येक गतिविधि/सेवाओं के लिए पृथक खाते रखे जाने चाहिए।

### विश्लेषण

40. मेरी राय में, विवाद का मुद्दा सीधे **रामजस स्कूल** में इस पीठ के निर्णय और **महावीर सीनियर मॉडल स्कूल** में समन्वय एकल पीठ के फैसले से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद श्री त्रिपाठी और श्री झा ने इस न्यायालय को अन्यथा समझाने के साहसी प्रयास किए हैं।

41. यह **रामजस स्कूल, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल** आक्षेपित आदेशों के प्रासंगिक पाठ को सहज रूप से पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा और वर्तमान याचिका इस प्रकार है:

### रामजस स्कूल में आक्षेपित आदेश:

#### वित्तीय विसंगतियाँ:-

क्रमांक सं.	विसंगति का विवरण	स्कूल प्रस्तुतियाँ	टिप्पणी
1.	डी.ओ.ई. के आदेश संख्या डीई. 15/ए.सी.टी/ Duggal.com/203/99/23033-23980, दिनांक 15/12/1999, छात्रों, से जमानत राशि के रूप में एकत्रित की गई राशि को अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा और छात्र को स्कूल छोड़ने के समय बैंक के ब्याज	भविष्य में डी.ओ.ई. के दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को ब्याज सहित जमानत राशि को वापस कर	स्कूल ने भविष्य में भी ऐसा ही होगा यह अनुपालन सुनिश्चित किया है।

	सहित वापस कर दिया जाएगा। फिर भी यदि स्कूल उपरोक्त दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहा है। तो जमानत राशि पर ब्याज अर्जित करने की बजाए धन को छात्र कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है।	दिया जाएगा।	
2.	डी.ओ.ई. के आदेश संख्या. डी.ई./15/150/अधिनियम/2010/4854-69, दिनांक 09/09/2010, के अनुसार, ऐसे पूर्व- छात्रों के मामलों में जिन्हें जमानत राशि वापस नहीं की गई है, स्कूल उन्हें उनके अंतिम रूप से दर्शाए गे पते पर उक्त राशी 30 दिनों के भीतर जमा करने के लिए लिखित में दे। 30 दिनों के समाप्ति के बाद, पूर्व-छात्रों से संबंधित अप्रतिदाय जमानत राशि को अगले वित्तीय वर्ष की आय के रूप में दर्शाया जाएगा और इसे दायित्व के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। हालाँकि, स्कूल उपरोक्त दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहा है। पूर्व-छात्रों की अप्रतिदेय जमानत सावधानी राशि को जमानत राशि खाते में रखा जाता है और तीन साल तक देनदारी के रूप में दर्शाया जाता है। इसके बाद, व्यपगत जमानत राशि को छात्र कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है लेकिन इसे कभी भी आय के रूप में नहीं माना जाता है।	यह ध्यान दिया जाता है कि डी.ओ.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करेंगे।	स्कूल ने भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया है।
3.	भवन और भूमि स्कूल की लेख	यह इमारत	अगली शुल्क

	पुस्तकों की संपत्ति में दिखाई नहीं दे रहे हैं और स्कूल ने सूचित किया है कि यह बुनियादी पुस्तकों, में दिखाई दे रहे हैं, जबकि संबंधित खर्चों को दर्ज किया गया है, लेकिन आय को स्कूल की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है ।	रामजस फाउंडेशन के समेकित वित्तीय विवरण में दिखाई दे रही है।	वृद्धि के लिए आवेदन करने से पहले, चालू वर्ष की आय का प्रस्ताव प्रामाणपत्र विवरण वसूली योग्य राशि में जोड़ा जाना है।
--	--	---	---

### अन्य विसंगतियाँ

क्रमांक सं.	विसंगति का विवरण	स्कूल के निवेदन	टिप्पणी
1.	शुल्क संग्रहण के विरुद्ध मूल रसीदें संरक्षित नहीं का जाती हैं और जमानत राशि, प्रवेश शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रसीदों को छोड़कर संपरीक्ष के समापन/ समाप्ति के पश्चात नष्ट कर दी जाती हैं.	एक बार संपरीक्षा पूर हो जाने के बाद, शुल्क जमा पर्ची क्योंकि हमारे पास शुल्क रजिस्टर और बैंक खाता विवरण में सभी अभिलेख हैं	विचारित
2.	अचल संपत्ति रजिस्ट्रों को उचित रूप से बनाए नहीं रखा जाता है और	अचल संपत्ति रजिस्टर ठीक से बनाए रखा जाता है और पहचान संख्या विधिवत	स्कूल के इस दावे को साबित करने के लिए कोई समर्थन नहीं है

	वित्त अभिलेख के साथ भी मिलान नहीं किया जाता है। कई मामलों में संपत्ति की पहचान संख्या और उनके स्थान का उल्लेख नहीं किया जाता है।	उल्लेख किया जाता है।	अनुपालन का सत्यापन स्कूल के अगले शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के समय किया जाएगा, यदि कोई हो।
3.	निविदा के माध्यम से खरीद प्रक्रिया और उनकी सीमा, यदि कोई हो, प्रबंधन द्वारा तैयार नहीं की गई है।	हम निविदाओं के माध्यम से खरीद प्रक्रिया का ठीक से पालन कर रहे हैं केवल और भविष्य में प्रणाली को और मजबूत करेगा।	स्कूल के अगले शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के समय अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा, यदि कोई हो।
4.	नियुक्ति के आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुभव दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और स्कूल प्रबंधन भी इसके ले नहीं कह रहे हैं।	सत्यापन के लिए संबंधित संस्थानों से संपर्क किया जाता है और भविष्य में पत्राचार का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।	स्कूल के अगले शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के समय अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा, यदि कोई हो।
5.	स्कूल न्यायिक स्टॉप पत्र के बजाय सादे कागज पर अनुबंध करता है।	वित्त वर्ष 2016-17 से, सभी अनुबंध न्यायिक स्टॉप पत्र पर किए जाएंगे	स्कूल द्वारा स्वीकृत

और जबकि, दिनांक 30.01.2017 के अभ्यावेदन और 12.05.2017 को हुई सुनवाई

के दौरान स्कूल द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ इस निदेशालय के पास

उपलब्ध स्कूल के वित्तीय विवरण/बजट को देखने के बाद, यह सामने आता है कि: -

निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्कूल के पास 1,18,42,701/- रुपए की अधिशेष  
निधि है:-

विवरण	राशि (रु.)
संपरिक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को नकद और बैंक शेष	37,33,902
संपरिक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार 31.03.2016 तक निवेश	12,12,42,543
कुल	12,49,76,76,445
घटाएँ: संपरिक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार विकास निधि	4,63,02,138
घटाएँ: संपरिक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार मूल्यहास आरक्षित निधि	1,05,11,284
घटाएँ: उपदान के लिए प्रावधान*	3,48,36,745
घटाएँ: अवकाश भुनाने/नकदीकरण का प्रावधान*	98,62,301
उपलब्ध कोष	2,34,63,301
वित्तीय विवरण के अनुसार 2015-16 के लिए शुल्क (हमने मान लिया है कि 2015-16 में प्राप्त राशि कम से कम 2016-17 में प्रोदभूत होगी)	8,40,95,053
वित्तीय विवरण के अनुसार 2015-16 के लिए अन्य आय	9,27,671
2016-17 के लिए धन की अनुमानित उपलब्धता	10,84,86,701
घटाएँ: घटाएँ: स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सत्र 2016-17 के लिए बजट व्यय (राजस्व)	9,66,44,000
शुद्ध अधिशेष	1,18,42,701

\*स्कूल को इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर एल.आई.सी. (या किसी अन्य अभिकरण) के साथ सेवानिवृत्ति लाभ के खिलाफ निवेश समतुल्य निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वैधानिक देनदारियों की रक्षा की जा सके। और उपदान और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

और जबकि, उपरोक्त जाँच को देखते हुए, यह है यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सभी बजटीय व्यय को पूरा करने के बाद भी स्कूल के पास पर्याप्त अधिशेष निधि है।

और जबकि, आदेश संख्या एफ.डी.ई./15(56)ए.सी.टी./2009/778 दिनांक 11/02/2009, के खंड 22 के अनुसार उपयोगकर्ता प्रभार बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए जिसके लिए इन्हें एकत्र किया जाता है। तदनुसार, स्कूल को सलाह दी जाती है की वे डी.एस.ई.ए. और आर, 197 और उसके अंतर्गत जारी आदेशों, परिपत्रों आदि के अनुसार विधार्थियों से प्रभारित प्रत्येक निर्धारित शुल्क के संबंध में अलग-अलग निधि रखें। यदि छात्रों से एकत्र किए गए किसी निर्धारित शुल्क के तहत बड़ी मात्रा में अधिशेष राशि है तो अगले शैक्षिक सत्र में प्रभारित किए जाने वाले निर्धारित शुल्क का निर्धारण करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा अथवा समायोजित किया जाएगा।

और जबकि, आदेश संख्या एफ.डी.ई./15(56)/अधिनियम./2009/778 दिनांक 11.02.2009, के खंड संख्या 14 के अनुसार, 'विकास' शुल्क, जो कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए संसाधनों के पूरक के लिए जा सकता है। विकास शुल्क, यदि लिया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में माना जाएगा और केवल तभी एकत्र किया जाएगा जब स्कूल राजस्व लेखों में प्रभारित बहिष्करण के समतुल्य मूल्यहास आरक्षित निधि बनाए हुए है और इस शीर्ष के अंतर्गत

संग्रहण और इस निधि से किए गए निवेश से सृजित आय को अलग से अनुरक्षित विकास निधि खाते में रखा जाएगा। तदनुसार, स्कूल को सूचित किया जाता है कि वे अलग से विकास निधि का रखरखाव करें और डी.एस.ई.ए. एंड आर, 1973 और उसके तहत जारी आदेशों, परिपत्रों आदि के अनुसार इसका सख्ती से उपयोग करें।

और जबकि, प्रासंगिक सामग्रियों के साथ इन सिफारिशों को शिक्षा निदेशक के समक्ष विचार के लिए रखा गया था और जिन्होंने अभिलेख पर सभी सामग्री पर विचार करने के बाद पाया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय निहितार्थ को पूरा करने के लिए स्कूल के पास पर्याप्त अधिशेष धन है और 03.02.2017 के अभ्यावेदन और उसके बाद इस संबंध में किए गए निवेदनों में फीस में वृद्धि की मंजूरी के संबंध में कोई गुणागुण नहीं पाई गई है और इसके द्वारा उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर खारिज कर दिया गया।

**महावीर सीनियर मॉडल स्कूल में आक्षेपित आदेश -**

और जबकि, स्कूल द्वारा किए गए सभी निवेदन को अभिलेख पर लिया जाता है और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के प्रावधानों और उसके तहत जारी निर्देशों के अनुसार विश्लेषण किया जाता है।

क्रम.सं.	टिप्पणियों	विद्यालय की प्रस्तुतियाँ	टिप्पणी
1.	दिनांक 23-03-1999 के आदेश संख्या 15072-15871 के अनुसार “ दिल्ली में पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा स्कूल परिसर में या उसके बाहर उपयुक्त	जूनियर स्कूल की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी लेकिन यह आपत्ति निदेशालय कार्यालय द्वारा पहली बार ली गई है। हालाँकि आवेदक ने अब महावीर	स्कूल द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और निवेदनों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, स्कूल की निधि की स्थिति को अवगत किया गया है और

<p>प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों की शाखाओं के रूप में चलाए जा रहे सभी प्री-प्राइमरी स्कूलों को सभी प्रयोजनों के लिए एक संस्थान माना जाएगा। इसके अलावा उपलब्ध विवरण के अनुसार, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल में दाखिला लेने वाले 106 में से 92 (यानी 86.7%) छात्र महावीर जूनियर मॉडल स्कूल से हैं, हालांकि, महावीर जूनियर मॉडल स्कूल की फीस संरचना सहित वित्तीय जानकारी को "बयान" में शामिल नहीं किया गया था। डी.एस.ई.ए. 1973 की धारा 173 के तहत शुल्क निदेशालय को जमा किया गया। इसके अलावा, स्कूल द्वारा संयुक्त वित्तीय विवरणों के बजाय खातों और वित्तीय विवरणों की पुस्तकों के अलग-अलग</p>	<p>सीनियर मॉडल स्कूल और महावीर जूनियर मॉडल स्कूल दोनों का एक संयुक्त निधि विवरण तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुकाबले उपलब्ध निधि के सही आंकड़े दिखाए गए हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, स्कूल प्रबंधन ने बताया कि शुल्क बढ़ाने से पहले निदेशालय की पूर्व मंजूरी लेने की शर्त का उल्लेख महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के भूमि आवंटन में किया गया है, न कि महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के भूमि आवंटन पत्र में। इस प्रकार, सीनियर स्कूल के शुल्क बढ़ाने के लिए निदेशालय की पूर्व स्वीकृति लागू नहीं</p>	<p>इस आदेश के बाद के भाग में संलग्न किया गया है। महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के संबंध में डी.डी.ए द्वारा दिनांकित 02-11-1987 को जारी भूमि आवंटन पत्र के खंड 15 को पढ़ने के बाद, जिसमें कहा गया है स्कूल " शिक्षा निदेशक दिल्ली एडिन की पूर्व स्वीकृति के बिना ट्यूशन फीस की दरों में वृद्धि नहीं करेगा और दिल्ली स्कूल महावीर सीनियर मॉडल स्कूल, शिक्षा अधिनियमनियमों/, 1973 के प्रावधानों का पालन करेगा। और समय समय-पर अन्य अनुदेश जारी करेगा"। यह नोट किया गया कि जूनियर स्कूल निदेशालय की पूर्व स्वीकृति के बिना फीस बढ़ा रहा है। तदनुसार, महावीर जूनियर मॉडल स्कूल को वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान छात्रों से एकत्र किए गए बढ़े हुए शुल्क को वापस</p>
--	---	---



	सेट तैयार किए जाते हैं	होगी।	करनेसमायोजित करने का / वर्ष ) निर्देश दिया जाता है जब शुल्क बढ़ाने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपने भूमि आवंटन पत्र में शर्त वाले स्कूलों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थीऔर उसके ( बाद। इसके अतिरिक्त, महावीर जूनियर मॉडल स्कूल को निदेश दिया जाता है कि निदेशालय के पूर्वानुमोदन के बिना कोई शुल्कप्रभार न / बढ़ाया जाए।
2.	दिनांक 04.05.1997 की सार्वजनिक सूचना के खंड 2 के अनुसार, "स्कूल छात्रों से भवन निधि नहीं लेगा क्योंकि यह सोसाइटी की एकमात्र जिम्मेदारी है जिसने स्कूल की स्थापना की है कि वह अन्य संघों से दान के अपने स्वयं के स्रोतों से इस तरह की धनराशि जुटाए क्योंकि स्कूल की अचल संपत्ति	यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल ने छात्रों से भवन निधि कभी नहीं ली है। यह इंगित किया गया है कि महावीर मॉडल सीनियर स्कूल के मामले में भवन का निर्माण वर्ष 1980 से 1983 में महावीर फाउंडेशन नामक सोसायटी द्वारा किया गया था और	स्कूल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रस्तुतियों के आधार पर, स्कूल को निर्देश दिया जाता है कि वह भवन/बुनियादी ढांचे पर कोई भी पूंजीगत व्यय करने से पहले डी.ई.एस.आ.र, 1973 के नियम 177 का अनुपालन सुनिश्चित करे, अन्यथा सोसायटी को भवन के निर्माण की लागत वहन करनी चाहिए।

<p>सोसायटी की एकमात्र संपत्ति बन जाती है। इसके अतिरिक्त, डी.इस.ई.ए. और आर. 1973 के नियम 177 में उल्लेख किया गया है यदि स्कूल के पास पर्याप्त अधिशेष नहीं है तो उसे भवन में अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, स्कूल ने ट्यूशन फीस से महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के निर्माण की योजना बनाई है, जिसके लिए स्कूल ने वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान "शिल्पकार और "स्थान निरीक्षण को "4,53,000 रुपये का भुगतान किया है। साथ ही स्कूल ने स्कूल भवन के निर्माण के लिए 12,79,04,645 रुपये का भी प्रस्ताव रखा है। स्कूल को डी.एस.ई.ए. और आर. 1973 के नियम 177 के अनुसार बचत की</p>	<p>मॉडल स्कूल के महावीर सीनियर के नाम और शीर्षक से स्कूल चलाने के लिए महावीर सीनियर मॉडल स्कूल की प्रबंध समिति को सौंप दिया गया था। स्कूल ने 1983 के शैक्षणिक सत्र से काम करना शुरू कर दिया। आगे यह इंगित किया गया है कि समाज और स्कूल एक ही इकाई के रूप में एक हैं। इसके द्वारा उत्पन्न निधि से समाज द्वारा निर्मित संपत्ति समाज की संपत्ति बनी रहती है और यह संपत्ति पक्ष में खाते की किताबों में परिलक्षित होती है। दूसरी ओर, यदि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 के नियम 177 उपखंड 2 (ख और ( )गके तहत स्कूल (</p>	
---	---	--

	<p>गणना दर्शाने वाला विवरण तैयार करना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए नियम 177 के अनुसार कोई बचत नहीं होने की स्थिति में निदेशालय को भवन में कोई पूंजीगत व्यय नहीं करना चाहिए।</p>	<p>द्वारा आकस्मिक बचत /से कुछ हिस्साविभाग या सुविधाएं तैयार की जाती हैं और इसे प्रतिबिंबित किया जाता है और शीर्ष भवन या पुस्तकालय प्रयोगशाला सुविधा और सम्मलेन कक्ष के तहत स्कूल की तुलनपत्र में एक संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, चूंकि इनका सृजन विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है ताकि वे आधारभूत संरचना के माध्यम से अपने शिक्षा प्रयासों में आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें।</p> <p>सोसायटी के साथ-साथ आवेदक स्कूल का प्रबंधन, उस भवन का नवीनीकरण और सुधार करने पर विचार कर रहा है जो वर्ष 1982</p>	
--	---	--	--

		<p>में बनाया गया था और एक आधुनिक भवन बनाया जाएगा जो अधिकारियों के सभी मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमों के साथ और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है।</p> <p>स्कूल ने वित्त वर्ष 1986 से 2018 तक की बचत की गणना सौंपी है</p>	
3.	<p>दिनांक 11/2/2009, को खण्ड 18 के आदेश संख्या एफ.डी.ई./15(56) के अनुसार "इस प्रकार एकत्र की गई जमानत राशि संबंधित स्कूल के नाम पर एक अनुसूचित बैंक में जमा की जाएगी और छात्र को उसके/उसकी स्कूल छोड़ने के समय बैंक ब्याज के सहित वापस कर दी जाएगी, भले ही वह वापसी के लिए अनुरोध</p>	<p>यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि:</p> <p>- यहाँ जमानत राशि के शीर्ष के लिए अनुसूचित बैंक में कोई विशिष्ट सावधि जमा या बचत जमा नहीं है।</p> <p>- स्कूल प्रत्येक छात्र के विवरण के साथ जमानत राशि की खाता बही और इस उद्देश्य के लिए एक रजिस्टर</p>	<p>स्कूल के स्पष्टीकरण के आधार पर कि वह वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान जमानत राशि एकत्रित करना बंद कर देगा और मौजूदा छात्रों को कुल जमानत राशि वापस/समायोजित करेगा, अनुपालन का पश्चात्वी वर्ष में विधिमान्यकरण किया जाएगा।</p>

	<p>करे या नहीं" / हालांकि, स्कूल ने अनुसूचित बैंक में जमानत राशि जमा नहीं कराई है। स्कूल इस संबंध में समय समय पर - निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।</p>	<p>बना रहा है।</p> <p>- स्कूल की सभी धनराशि अनुसूचित बैंक में बचतसावधि जमा / खाते में जमा की जाती है और जमानत राशि स्कूल द्वारा ऐसे खाते में जमा की गई जमा राशि में शामिल की जाती है।</p> <p>-स्कूल ने प्रत्येक छात्र को उसके/उसकी छोड़ने के समय देय राशि वापस कर दी है और प्रत्येक छात्र को लौटाई गई राशि की जानकारी के साथ एक चार्ट तैयार रखा है</p> <p>- इस प्रकार, अनुसूचित बैंक में जमा की गई जमानत राशी की आवश्यकता का आवेदक स्कूल द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। सभी जमानत राशी और अन्य निधि अनुसूचित</p>	
--	--	--	--

		<p>बैंक में सावधि जमा के माध्यम से स्कूल के नाम से जमा किए जाते हैं उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि ले.पे.अ. 291/2017 सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांकित 11.05.2018 के निर्णय के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक निधि के लिए एक अलग सावधि जमा खाता होना आवश्यक नहीं है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, स्कूल ने बताया कि वह वित्त वर्ष 2019-2020 से छात्रों से जमानत राशि लेना बंद कर देगा। साथ ही, मौजूदा छात्रों से एकत्र किए गए जमानत राशि</p>	
--	--	--	--

		को वित्त वर्ष 2019-2020 में समायोजित किया जाएगा।	
4.	<p>आदेश संख्या एफ.डी.ई.15/ए.सी.टी.-I/रि.या.(सि.) - 4109/भाग/13/7905-7913 दिनांकित 16 अप्रैल 201 के अनुसार "निदेशक एतद्वारा निर्दिष्ट करते हैं कि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के परिशिष्ट-II के साथ पठित नियम 180 के तहत स्कूलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिफल का प्रारूप और दस्तावेज भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के तहत स्कूलों द्वारा लेखांकन पर दिशानिर्देश लेख(2005) में</p>	<p>जहां तक किसी विशेष फार्मेट में विवरण की आवश्यकता का संबंध है,स्कूल द्वारा इसका हमेशा अनुपालन किया जाता है। जहाँ तक मूल्यहास की दरों का संबंध है, स्कूल आयकर अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत यथा निर्धारित दरों का अनुपालन कर रहे हैं। आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों और मार्गदर्शन नोट के परिशिष्ट -1 में अनुशंसित दरों के बीच बहुत मामूली अंतर है।-इसके अलावा, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान स्कूल ने वित्त</p>	<p>स्कूल द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कि उसने मार्गदर्शन नोट में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रभार लिया है, अनुपालन को बाद के वर्ष में मान्य किया जाएगा।</p>

	<p>स्थापित किया गया है या इस संस्थान द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है। इसके अलावा, दिशानिर्देश लेख के पैरा 58 (i) में कहा गया है की "एक स्कूल को मार्गदर्शन दिशानिर्देश लेख के परिशिष्ट I में अनुशंसित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार मूल्यहास चार्ज करना चाहिए।"</p>	<p>वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखा संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में बताया है कि दिशानिर्देश लेख 21 के तहत निर्धारित दरों पर मूल्यहास का आरोप लगाया।</p>	
5.	<p><u>विकास निधि के विरुद्ध खरीदी गई परिसंपत्तियां:</u> आदेश सं एफ.डी.ई./15(56)/ए.सी.टी. 2009/778 दिनांक 2-11-2009 के अनुसार फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरणों की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए संसाधनों की पूर्ति हेतु कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क के 15% से अनधिक विकास शुल्क प्रभारित किया जाए।</p>	<p>स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 1983 से वर्ष 1994-1995 तक स्कूल की बचत से वर्ष 1994-1995 में किया गया था बचत पर अर्जित ब्याज और विकास निधि से नहीं। कृपया ध्यान दें कि चारदीवारी व्यय में 76,695/- रुपये की</p>	<p>स्कूल का प्रतिविरोध विकास निधि के सुव्यवस्थित मुद्दे के प्रावधानों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या के अनुरूप नहीं है। फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण की खरीद, उन्नयन प्रतिस्थापन के अलावा अन्य पूंजीगत व्यय विकास निधि में से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, स्कूल को विकास</p>



<p>विकास शुल्क, यदि लिया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा और केवल तभी एकत्र किया जाएगा जब स्कूल राजस्व खातों में प्रभारित मूल्यहास के समतुल्य मूल्यहास आरक्षित निधि रख रहा हो और इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहण और इस निधि से किए गए निवेश से सृजित आय को अलग से रखे गए विकास निधि खाते में रखा जाएगा। हालांकि, स्कूल ने (टाटा डी .एल.- 1 पी.सी.- 3702) को छोड़कर विकास निधि से सभी संपत्ति खरीदी है, जिसमें निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं जो विकास निधि से खरीदे जाने के योग्य नहीं हैं। तदनुसार, स्कूल ने उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है ।</p>	<p>एक छोटी राशि शामिल है और चारदीवारी की मरम्मत पर खर्च किया गया था, सीमा का निर्माण पहले से ही वर्ष 1982-83 में किया गया था जब स्कूल भवन का निर्माण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि अनजाने में और गलत तरीके से पूंजीकृत की गई थी और इसलिए तुलन पत्र में दिखाई देती है, जिसे लेखा पुस्तकों से अपलिखित किया जा सकता है।</p> <p>पुस्तकालय की किताबें स्कूल का अनिवार्य हिस्सा हैं। पुस्तकालय पुस्तकें पूंजीगत परिसम्पत्ति होने के कारण शिक्षण शुल्क अथवा वार्षिक प्रभारों से दिनांकित 15-12-1999 के आदेश के अनुसार नहीं खरीदी जा</p>	<p>निधि के उचित उपयोग के संबंध में निदेशक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।</p>
--	---	--

क्रमांक सं.	विवरण	राशि (सकल ब्लाक)	सकती। यहाँ पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद के लिए विकास निधि के उपयोग में कोई विरोधाभास नहीं है।
1.	स्कूल भवन	1,23,01,906	पुस्तकालय की पुस्तकें भी गठन/निर्माण योग्य नहीं हैं इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती और इसलिए समाज द्वारा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस प्रकार, पुस्तकालय की पुस्तकें केवल विकास निधि से खरीदी जा सकती हैं और उन्हें पूंजीगत परिसंपत्ति और पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।
2.	चार दीवारी का निर्माण	76,6,95	स्कूल वाहन समय-समय पर खरीदे जाते रहे हैं और उनका उपयोगी जीवन समाप्त होने के बाद उनका अवमूल्यांकन करना और अपलिखित करना
3.	पुस्तकालय की पुस्तकें	6,69,265	
4.	वाहनों	18,39,678	

		<p>कर दिया गया है। वाहन केवल विकास निधि से खरीदे जा सकते हैं और कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, जैसा कि दिनांकित 15.12.1999 के आदेश के प्रावधानों में दिया गया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि विकास निधि का उपयोग कैसे किया जाए, जो कि फर्नीचर, फिक्सचर की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए संसाधनों के पूरक के रूप में है। और उपकरण। फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण को परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में संपत्ति शामिल मानी गई है, जिसकी स्कूल को समय-समय पर आवश्यकता होगी और कानून के जानकारों ने</p>	
--	--	--	--

		सूची को विस्तृत नहीं रखा है ताकि नई संपत्ति बनाई जा सके। समय की आवश्यकता के अनुरूप स्कूल की आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ी गई और विकास निधि से खरीदारी की गई।	
6.	यह देखा गया कि पुस्तकालय की पुस्तकें, विज्ञान उपकरण शिक्षण सहायक सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिका, शैक्षिक वीडियो और ऑडियो सी.डी. स्थापना की मानक लागत से प्रभारित की गई हैं। ये स्थापना लागत का हिस्सा नहीं हैं और इस प्रकार इसे शिक्षण शुल्क की गणना से बाहर रखा गया है, परन्तु वार्षिक शुल्क का हिस्सा माना जाता है	पुस्तकालय की पुस्तकें, विज्ञान उपकरण, शिक्षण सहायक सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिका, शैक्षिक ऑडियो और ऑडियो सी.डी. स्कूल की पाठ्यचर्या गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा हैं और इस प्रकार स्थापना की मानक लागत के लिए शुल्क लिया गया है।  कृपया ध्यान दें कि ऊपर सूचीबद्ध सभी पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर पाठ्यचर्या	स्कूल ने इस अवलोकन और अवलोकन संख्या 5 के जवाब में उल्लेख किया है कि पुस्तकालय की किताबें स्कूल की और इस प्रकार स्थापना की मानक लागत पर शुल्क लगाया गया है। विकास निधि से खरीदी जानी चाहिए, स्कूल ने ट्यूशन फीस के खिलाफ पुस्तकालय की पुस्तकों का भी शुल्क लिया है। इस प्रकार, स्कूलों के लेखा अभिलेख में पुस्तकालय पुस्तकों के लेखांकन में विसंगति है। बहुत नाम से, विज्ञान उपकरण और शिक्षण सहायक उपकरण पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाई देते हैं

		<p>गतिविधियों के स्वरूप में हैं, ये सभी वस्तुएं उपभोग्य वस्तुएं हैं और इनका एक वर्ष का उपयोगी जीवन है और इसलिए इसका पूर्णतः औचित्य है कि उनसे ट्यूशन फीस ली जानी चाहिए। पुस्तकालय की पुस्तकें, जैसा कि पहले बिंदु में बताया गया है, ये पूंजीगत प्रकृति की हैं और इस प्रकार विकास शुल्क से लिया जाना है।</p> <p>वार्षिक प्रभारों के संबंध में उपबंध से यह पूर्णत स्पष्ट हो जाता है कि वार्षिक प्रभारों में स्कूल के पाठ्यचर्या कार्यक्रमों से भिन्न खेल के मैदानों, खेल उपस्कर, सांस्कृतिक और अन्य पाठ्यचर्या क्रियाकलापों पर सभी</p>	<p>और ट्यूशन फीस से राजस्व व्यय के रूप में चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, समाचार पत्र और पत्रिकाएं सीधे स्कूल की पाठ्यचर्या गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं। स्कूल ने पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए उनके उपयोग के संबंध में शैक्षिक वीडियो और ऑडियो सीडी की प्रकृति और विवरण प्रस्तुत नहीं किया।</p> <p>हालाँकि उपरोक्त का स्कूल की निधि स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसे वार्षिक शुल्क/विकास निधि के विरुद्ध विभाजित किया जा सकता था, स्कूल को आदेश संख्या एफ.डी.ई./15(56) 2009/778 दिनांकित 11 फरवरी 2009 के खंड 19 का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है। जिसमें कहा गया है कि "शिक्षण शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि डीए, बोनस इत्यादि के</p>
--	--	--	---

		<p>राजस्व व्यय और व्यय शामिल होंगे। इस प्रकार, उपरोक्त लेख तत्कालीन स्कूल की पाठ्यचर्या गतिविधियों का हिस्सा हैं।</p>	<p>प्रावधानों और सभी सेवानिवृत्त लाभों के साथ-साथ राजस्व प्रकृति के व्यय सहित स्थापना की मानक लागत को पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में निर्धारित किया जा सके। ”</p> <p>इस प्रकार, केवल स्थापना व्यय और पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए शेष राजस्व प्रकृति का व्यय शिक्षण शुल्क के खिलाफ आरोपित किया जाना चाहिए और अन्य खर्चों को पूर्वोक्त आदेश के खंड 21 के अनुसार वार्षिक शुल्क के लिए आवंटित किया जाना चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि कोई वार्षिक शुल्क" तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वे सभी राजस्व व्यय को शामिल करने के लिए प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, स्कूल की पाठ्यचर्या गतिविधियों से अलग शिक्षण शुल्क/ और 'शीर्षक' और खेल के मैदानों,</p>
--	--	---	---

			खेल उपकरण, सांस्कृतिक और अन्य पाठ्यचर्या गतिविधियों पर खर्च में शामिल नहीं है।”
7.	<p>प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, स्कूल छात्रों से विकास शुल्क के रूप में एक वित्तीय वर्ष में लगभग 5 लाख एकत्र किया जा रहा है। हालांकि, स्कूल ने 1 अप्रैल 2017 तक 5.32 करोड़ रुपये आरंभिक अतिशेष के रूप में दिखाए हैं, जो एकत्र की गई राशि के साथ असंगत प्रतीत होता है। स्कूल को 31 मार्च 2017 तक एकत्रित, उपयोग में लाई गई विकास निधि और शेष राशि का समन्वय प्रदान करने के साथ-साथ "डीएसईए 1973 की धारा 17(3) के तहत फीस का विवरण" प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p>	<p>स्कूल ने 31 मार्च 2017 तक विकास राशी एकत्रित, उपयोग की गई और शेष राशि का समन्वय प्रस्तुत किया है। समन्वय विवरण स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि 01.04.2017 को 5.32 करोड़ के रूप में दिखाए गए शुरुआती शेष और एकत्र की गई राशि के बीच कोई असंगति नहीं है।</p>	विचार किया गया।
8.	महावीर जूनियर मॉडल	यह स्पष्ट किया जाता	स्कूल द्वारा प्रस्तुत

<p>स्कूल में उच्च छात्र शिक्षक अनुपात नीचे दिया गया है:</p> <table border="1" data-bbox="305 441 646 982"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चयन की संख्या (सभी) कक्षाएं (क)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>शिक्षक कर्मचारी (ख)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>नामांकित छात्रों</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	संख्या	चयन की संख्या (सभी) कक्षाएं (क)	6	शिक्षक कर्मचारी (ख)	5	नामांकित छात्रों	235	<p>है कि महावीर जूनियर मॉडल स्कूल में कुछ शिक्षक अनुबंध के आधार पर हैं। हुआ यं कि 31 दिसंबर 2017, को कुछ शिक्षकों का अनुबंध समाप्त हो गया और इसलिए वे चले गए। यह जनवरी और फरवरी के महीनों में केवल दो महीनों के लिए एक अस्थायी चरण था। 1 अप्रैल 2018 से सभी सहायक कर्मचारी वहां मौजूद हैं। यहां तक कि जनवरी और फरवरी 2018 की मध्य अवधि में भी, हमारे पास अभिभावक स्वयंसेवक, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और खेल गुरु से प्रशिक्षित थे।</p>	<p>स्पष्टीकरण और दस्तावेजों के आधार और अभिलेख पर लेने पर, जबकि स्कूल ने कुछ महीनों के लिए अस्थायी व्यवस्था की, स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थिति नियमित/बार-बार घटित नहीं होती है। और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षण कर्मचारी नियुक्त किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न हो।</p>
विवरण	संख्या									
चयन की संख्या (सभी) कक्षाएं (क)	6									
शिक्षक कर्मचारी (ख)	5									
नामांकित छात्रों	235									
<p>स्कूल द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार 6 अनुभागों के लिए 5 शिक्षक हैं</p>										

अभिलेख पर रखी सभी सामग्री की विस्तृत जाँच के बाद और स्कूल द्वारा प्रस्तुत



स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, अंततः यह मूल्यांकन निष्कर्ष/निकाला गया कि:

वर्ष 2018-2019 के लिए उपलब्ध कुल धनराशि रुपए 9,67,96,579 और रुपए 6,49,46,324 है, जिसमें से वर्ष 2018-2019 में रोकड़ बहिर्गमन क्रमशः महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के संबंध में रुपए 7,48,15,500 और रुपए 78,03,235 होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के लिए क्रमशः रुपये 2,19,81,079 और रुपये 5,71,43,088 का शुद्ध अधिशेष है। विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	राशी(रुपए)		
	महावीर सीनियर मॉडल स्कूल (क)	महावीर जूनियर मॉडल स्कूल (ख)	कुल(ग= क+ख)
31 मार्च 2018 को नकद और बैंक शेष वित्त) वर्ष 2017- 18 के अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार(	2,88,20,887	64,73,475	3,52,94,362

31 मार्च 2018 को निवेश सावधि जमा और) एल.आई.सी. के साथ जमा वित्त वर्ष) (2017-18 के अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार(	12,72,09,287	2,15,09,764	14,87,19,051
31 मार्च 2018 तक स्कूल के पास उपलब्ध कुल तरलता निधि	15,60,30,173	2,79,83,239	18,40,13,413
जोड़ें :स्कूल के वित्त वर्ष : 2017-18 के अनंतिम वित्तीय विवरण के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित शुल्क और अन्य आय संदर्भ) #)	8,71,75,117	1,75,11,126	10,46,86,24 3
जोड़ें :महावीर फाउंडेशन : से वसूली (सोसाइटी) स्कूल के ) राशियोग्य वित्त वर्ष2017-18 के अनंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार(*संदर्भ) (	-	3,52,45,744	3,52,45,744

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सकल अनुमानित उपलब्ध निधियां	24,32,05,290	8,07,40,109	32,39,45,400
घटा: विशिष्ट निधियों के खिलाफ एफ.डी.आर.ग्रहणाधिकार / संदर्भ) तहत के^)	1,59,26,780	15,170	1,59,41,950
घाट: विकास	5,59,84,513	1,13,09,266	6,72,93,779
31 मार्च 2018 को फंड बैलेंस वित्त वर्ष)2017-18 के अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार(			
घटा :31 मार्च 2018 को जमानत राशी शेष वित्त ) वर्ष2017-2018 के अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार(	10,81,491	9,56,000	20,37,491
घटामूल्यहास आरक्षित : संदर्भ) निधि~)	-	-	-
घटा: वेतन आरक्षित (** संदर्भ)	1,41,50,000	16,50,000	1,58,00,000

घटा: स्टाफ की आवश्यकता लाभ-उपादान और अवकाश नकदीकरण संदर्भ)^^)	5,92,65,927	18,63,349	6,11,29,276
वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए उपलब्ध निवल अनुमानित निधि	9,67,96,579	6,49,46,324	16,17,42,904
घटा :वित्त वर्ष -2018-2019 के लिए बजटीय व्यय देखें) ##(	7,48,15,500	78,03,236	8,26,18,736
31 मार्च 2019 तक अनुमानित अधिशेष	2,19,81,079	5,71,43,088	7,91,24,168

#स्कूल द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2017-2018 के अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार शुल्क और आय पर इस धारणा के साथ विचार किया गया है कि वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान आय की राशि कम से कम वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान अर्जित होगी। हालाँकि, एल.आई.सी. और आयकर से ब्याज आय को उपरोक्त आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह गैर आवर्ती आय है, जबकि बैंक खाते पर ब्याज और मूल्यहास संचय के खिलाफ जमा को शामिल किया गया है, जो उपयोग के लिए स्कूल के पास उपलब्ध है।

\* निदेशालय के आदेश संख्या 15/ए.सी.टी./Duggal.com/203/99/23033-23980 दिनांकित 15 दिसंबर 1999 के अनुसार, प्रबंधन को मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूल निधि से किसी भी राशि को सोसायटी या ट्रस्ट या

किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने से रोका जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भी 2009 में पुनर्विलोकन अर्जी पर अपने निर्णय के माध्यम से सोसायटी को धन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी। वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए महावीर जूनियर मोड्सस्कूल के अनंतिम वित्तीय विवरण में महावीर फाउंडेशन (मूल सोसायटी) से 3,52,45,744 रुपए की प्राप्य राशि दर्शाई गई है। , जिसके बारे में स्कूल ने बताया कि यह सोसायटी के पास जमा राशि है, जिस पर स्कूल द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है। रुपए 3,52,45,74 की यह राशि स्कूल, के पास उपलब्ध धनराशि, के समान मानते हुए स्कूल की निधि स्थिति में जोड़ी जाती है और स्कूल को सोसायटी से इस राशि की वसूली करने का निर्देश दिया जाता है।

हालांकि स्कूल ने कहा कि न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह समिति द्वारा निर्धारित फीस और उस पर ब्याज सहित 3.42 करोड़ रुपये की राशि छात्रों को लौटाने की उसकी संयुक्त देयता है। हालांकि, यह मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, जिसके खिलाफ स्कूल ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के ग्रहणाधिकार के तहत बैंक में डेढ़ करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा की है। तदनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई केवल 1.5 करोड़ रुपये की राशि पर विचार किया गया है। इसके अलावा, सीनियर स्कूल के पास कुल रुपए 9,26,780 रुपए की विशिष्ट निर्धारित निधि है और जूनियर स्कूल के पास रुपए 15,170 की विशिष्ट निधि है जिस पर भी विचार किया गया है। तदनुसार विद्यालय द्वारा प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्यालय की निधि स्थिति प्राप्त करते समय 1,59,41,950 रुपए की राशि को समायोजित किया गया है।

-मूल्यहास भंडार के मूल्यांकन पर, यह नोट किया गया कि स्कूल ने अचल संपत्तियों पर मूल्यहास शुल्क लिया था और इसे स्कूल की तुलनपत्र के देनदारियों के पक्ष में मूल्यहास भंडार में स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा, स्कूल छात्रों से फर्नीचर , फिक्स्चर और उपकरणों की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए विकास निधि ले रहा है। हालांकि वित्त

वर्ष 2017-2018 के लिए अनंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार स्कूल (सीनियर और जूनियर दोनों) द्वारा बनाए गए विकास, निधि को स्कूल की निधि स्थिति प्राप्त करने के लिए समायोजित किया गया है, मूल्यहास आरक्षित (जिसे आदेश संख्या एफ.डी.ई./15 (56)ए.सी.टी./ 2009/778 दिनांकित 11 फरवरी 2009) 4 के खंड 14 के अनुसार राजस्व खातों में लगाए गए मूल्यहास के बराबर बनाया जाना है।)। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देश लेख 21 के अनुसार स्कूल की लेखा पुस्तकों में मूल्यहास के उचित लेखांकन उपचार के लिए एक लेखांकन शीर्षक है। इस प्रकार, स्कूल की निधि स्थिति पर मूल्यहास भंडार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। तदनुसार, उपरोक्त तालिका में इस पर विचार नहीं किया गया है।

\*\* स्कूल के प्रबंधक और शिक्षा उप निदेशक (संबंधित जिला) के नाम पर संयुक्त खाते में निश्चित जमा के रूप में वेतन आरक्षित निधि बनाने के लिए स्कूल के पास पर्याप्त धन है जो कर्मचारियों के 3 महीने के वेतन के बराबर है। तदनुसार, स्कूल को सी.ओ.एच.आई.एच. के समतुल्य अनुसूचित बैंक में सावधि जमा करने के निर्देश के साथ स्कूल की निधि स्थिति प्राप्त करते समय रूपए 1.58 करोड़ (रूपए 1,41,50,000 सीनियर स्कूल के लिए और 16,50,000 रूपए जूनियर स्कूल, के लिए जो लगभग स्कूलों के 3 माह के वेतन के खर्च के बराबर है) स्कूल की निधि की स्थिति निकालते समय स्कूल को स्कूल के प्रबंधक और शिक्षा उप निदेशक के संयुक्त नाम से ऊपर उल्लिखित राशि के बराबर एक अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा करने के निर्देश के साथ विचार किया गया है।

महावीर सीनियर मॉडल स्कूल ने 31 मार्च 2018 को उपदान और छुट्टी भुनाने के लिए अपनी देयता के संबंध में बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत

की, जो कुल रुपए 5,92,65,927 थी। इसके अलावा स्कूल ने वित्त वर्ष 2018-2019 रुपए के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों के लिए रुपए 1,71,72,000 की अतिरिक्त राशि का बजट रखा। जूनियर स्कूल के संबंध में, सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयता का बीमाकृत मूल्यांकन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, जूनियर स्कूल ने 31 मार्च 2018 को रुपए 47,51,312 के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान दर्ज किया है और वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रुपए 28,86,479 की अतिरिक्त राशि का बजट रखा है। स्कूलों द्वारा बनाए गए प्रावधानों के खिलाफ, लेखा मानक-15 यानी एल.आई.सी. की समूह उपदान योजना के तहत परिभाषित 'योजना-परिसंपत्तियों' में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभों के लिए दायित्व के लिए सीनियर स्कूल और जूनियर स्कूल द्वारा क्रमशः रुपए 1,81,25,883 और रुपए 18,63,349 सुरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार, उपलब्ध विवरणों के आधार पर, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित देयता की राशि पर विचार किया गया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए स्कूल द्वारा 17.1 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बजट की गई राशि अत्यधिक प्रतीत होती है। महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के संबंध में, सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयता के बीमांकित मूल्यांकन की अनुपस्थिति में, एल.आई.सी. के पास जमा की गई राशि पर विचार किया गया है। तदनुसार, महावीर जूनियर मॉडल स्कूल को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों में एक बीमांकित द्वारा मापे गए सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अपने दायित्व को प्राप्त करे और

इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर बीमांकित द्वारा निर्धारित राशि के बराबर राशि जमा करे। महावीर सीनियर मॉडल स्कूल को निर्देश दिया गया है कि वह स्कूल के कर्मचारियों के प्रति वैधानिक देनदारियों की रक्षा के लिए एल.आई.सी. (या अन्य बीमाकर्ता) के साथ समूह उपदान और छुट्टी भुनाने वाली योजनाओं के लिए रुपए 4,11,40,044 की शेष राशि जमा करे।

## महावीर सीनियर मॉडल स्कूल द्वारा डी.एस.ई.ए.,1973 की धारा 17 (3) के तहत शुल्क के विवरण के साथ प्रस्तुत वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए अनुमानित खर्च के अनुसार, स्कूल ने वित्त वर्ष के दौरान कुल खर्च का अनुमान रुपए 9,44,60,500 (विकास शुल्क के खिलाफ 12,05,000 रुपए के पूंजीगत व्यय सहित) लगाया था। वित्त वर्ष 2018-2019 के इस बजट व्यय को सेवानिवृत्ति लाभ (ऊपर दी गई तालिका में अलग से विचार किया गया है) और मूल्यहास (गैर-नकद व्यय) को पूंजीगत व्यय (विकास निधि के बदले में किए जाने वाले) प्रावधान की राशि के साथ समायोजित किया गया है और 7,48,15,500 रुपए के शुद्ध व्यय पर उपरोक्त तालिका में विचार किया है। इसके अलावा, महावीर जूनियर मॉडल स्कूल के संबंध में, वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए अनंतिम वित्तीय विवरणों में बताए गए रुपए 1,14,21,270 के कुल व्यय के मुकाबले, सेवानिवृत्ति लाभ (उपरोक्त तालिका में अलग से विचार किया गया) के प्रावधान के समायोजन के बाद रुपए 78,03,236 की शुद्ध राशि पर विचार किया गया है।, आरक्षित निधि के लिए प्रावधान (उपरोक्त का तालिका में अलग से विचार किया गया) और मूल्यहास (गैर-नकद व्यय), क्योंकि वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बजट व्यय स्कूल द्वारा अलग से प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

ii. शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 16.04.2010 के निर्देश परिपत्र सं.1978 में कहा गया है कि "सभी स्कूलों को, सबसे पहले,



कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप, वेतन और भत्तों के भुगतान में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा धन/भंडार का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना और उसे समाप्त करना चाहिए। आरक्षित निधि का एक हिस्सा जिसका वर्षों से एक साथ उपयोग नहीं किया गया है, शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव करने से पहले कमी को पूरा करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। "स्कूल के पास मौजूदा फीस संरचना के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए स्कूल के संचालन को जारी रखने के लिए पर्याप्त धन है।

42. इनमें से प्रत्येक मामले में, यह स्पष्ट है कि आदेश में संबंधित स्कूल के विरुद्ध अनौचित्य के विभिन्न आरोप हैं। अंततः, हालांकि, प्रत्येक मामले में, जो निर्णय लिया गया है, वह डीओई की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल को फीस बढ़ाने से प्रतिबंधित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मामले में, उक्त निर्णय से तुरंत पहले यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सातवें सी.पी.सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल के खातों में अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि है।

43. न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या शिक्षा निदेशालय के पास स्कूल को फीस बढ़ाने से रोकने का अधिकार है और यदि फीस पहले ही बढ़ चुकी है, तो क्या उसके पास स्कूल को ऐसी अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश देने का अधिकार है जो डीओई द्वारा निर्धारित स्कूल द्वारा लिए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क से अधिक हो।

44. मुद्दा अब अनिर्णित विषय नहीं है। इस न्यायालय ने **रामजस स्कूल** और **महावीर सीनियर मॉडल स्कूल** मामले में इस मुद्दे की गहराई से जांच की है और इस विषय पर पहले के विभिन्न न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल के मामलों को विनियमित करने की डीओई की शक्ति स्कूल द्वारा लिए जाने वाली फीस का विनियमन करने तक विस्तारित नहीं है। जब तक स्कूल प्रतिव्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी से शिक्षा के वाणिज्यीकरण में लिप्त नहीं है, तब तक डीओई के पास स्कूल द्वारा लिए जाने वाली फीस को विनियमित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

45. **रामजस स्कूल ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन, इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न स्कूल, पी. ए. इनामदार और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाम थॉमस पी. जॉन** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। इन निर्णयों के प्रासंगिक उद्धरण, जो इस मुद्दे पर न्यायिक विचार की दिशा तय करते हैं, इस प्रकार हैं:

टी. एम. ए. पाई से

"35. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा बनाई गई और उसके बाद सरकारों द्वारा अपनाई गई योजना ऐसी थी जिसे संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। आम तौर पर, एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। संस्थान को योग्य और अनुभवी शिक्षकों और उचित सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से सभी के लिए पूंजी निवेश की

आवश्यकता होती है। शिक्षकों को उचित भुगतान करना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, *उन्नी कृष्णन* मामले में योजना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने शैक्षणिक संस्थानों का चलना असंभव नहीं तो मुश्किल आवश्यक बना दिया। इसलिए, ऐसे प्रतिबंधों को उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है।

36. निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करते हैं और यह उनसे अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों के चयन और शुल्क निर्धारण के मामलों में उनकी स्वतंत्रता छीनने का कारण नहीं हो सकता है। संबद्धता और मान्यता की शर्तों को पूरा करने वाले प्रत्येक संस्थान को संबद्धता और मान्यता मिलनी चाहिए। निजी संस्थानों का यह कहना सही है कि न्यायालय द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को संबद्धता या मान्यता प्रदान करने की शर्त के रूप में योजना की शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है; यह पूरी तरह से संस्थागत स्वायत्तता और संस्था की स्थापना के उद्देश्य को नष्ट कर देता है।

\*\*\*\*\*

55. संविधान व्यक्तिगत या धार्मिक संप्रदाय, या धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यदि सहायता या वित्तीय सहायता नहीं मांगी जाती है, तो ऐसी संस्था एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्था होगी। हालाँकि, *उन्नी कृष्णन* मामले में न्यायालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और निजी धन की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन जो योजना बनाई गई थी उसमें शैक्षणिक संस्थान के कामकाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवयवों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबद्धता या मान्यता प्राप्त करने में, बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्धता या मान्यता प्राप्त प्राधिकारी शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह न्यूनतम योग्यता निर्धारित करके

शिक्षकों की गुणवत्ता और अध्ययन और पाठ्यक्रम इंगित कर सकते हैं । समान कारणों से यह एक पूर्व शर्त के रूप में, इसके विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अस्तित्व को भी निर्धारित कर सकता है। लेकिन एक निजी शैक्षणिक संस्थान का सार स्वायत्तता है जो संस्थान के अपने प्रबंधन और प्रशासन में होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से, निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासन में अंतर होना चाहिए। जबकि बाद के मामले में, प्रशासन में सरकार का अधिक अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश और शुल्क तय करना शामिल है, निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले में, आम प्रशासन में अधिकतम स्वायत्तता निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के पास होनी चाहिए। ऐसी संस्था के प्रशासन में नौकरशाही या सरकारी हस्तक्षेप इसकी स्वतंत्रता को कमजोर कर देगा। हालांकि शैक्षणिक संस्थान कोई व्यापार नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को दी जा सकने वाली स्वतंत्रता की सीमा की जांच करने के लिए किसी भी निजी संस्था की तरह, जो सरकार से सहायता लेती हो या सहायता नहीं लेती हो, और जो ऐसे किसी धन द्वारा स्थापित की गई हो, जिसमें इसके ऋण या उधार शामिल हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निजी संस्थान के प्रबंधन के आवश्यक अवयवों में भर्ती होने वाले छात्र और स्टाफ, और लिए जाने वाला शुल्क शामिल है।

56. किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना उस संस्थान द्वारा निर्धारित तंत्र से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम आमतौर पर उन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं जिन्हें निर्धारित योग्यता के अनुसार भर्ती किया जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि बेहतर काम करने की परिस्थितियां बेहतर शिक्षकों को आकर्षित करेगी। अधिक सुविधाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि बेहतर छात्र उस संस्थान में प्रवेश ले सकें। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि छात्रों को सक्षम शिक्षण संकाय और अन्य बुनियादी सुविधाओं के रूप में अच्छी सुविधाएं प्रदान करने में पैसा खर्च होता है। इसलिए, यदि कोई संस्थान

सरकार से कोई सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है तो यह निर्धारित करना उसी पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह छात्रों से कितना शुल्क ले सकता है। इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हम आज एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रहते हैं, जहाँ व्यावसायिक शिक्षा की मांग है। हमारी समझ में एक बड़ी संख्या में पेशेवर और अन्य संस्थान ऐसे निजी पक्षों द्वारा शुरू किए गए हैं जो कोई सरकारी सहायता नहीं लेते हैं। एक मायने में, एक भावी छात्र के पास विभिन्न विकल्प खुले होते हैं, इसलिए, जहां आमतौर पर आर्थिक ताकतों की भूमिका होती है। शुल्क लेने का निर्णय अनिवार्य रूप से उस निजी शैक्षणिक संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सरकार से किसी भी धन की मांग नहीं करता है या उस पर निर्भर नहीं है।

57. हालाँकि, हम एक बात पर जोर देना चाहते हैं और वह यह है कि चूँकि शिक्षा का व्यवसाय एक प्रकार से हितकारी माना जाता है, इसलिए सरकार ऐसे नियमों को निर्धारित कर सकती है जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे, इस दौरान संस्थान प्रतिव्यक्ति शुल्क और मुनाफाखोरी वसूलने पर प्रतिबंध लगाएंगे। चूँकि एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य परिभाषा के अनुसार "पुण्यार्थ" है, यह स्पष्ट है कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है जो उस उद्देश्य को के लिए आवश्यक नहीं है। इसे अलग तरीके से कहें तो किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अनिवार्य रूप से हितकारी प्रकृति की होती है। हालाँकि, कुछ राजस्व अधिशेष शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

61. ....यह आम जनता के हित में है कि बेहतर गुणवत्ता वाले स्कूल स्थापित किए जाएं; नियुक्ति, छात्रों के प्रवेश और लिए जाने वाले शुल्क के अधिकार में स्कूल प्रशासन की स्वायत्तता और गैर-विनियमन यह सुनिश्चित

करेगा कि ऐसे और अधिक संस्थान स्थापित किए जाएं। यह डर कि यदि किसी निजी स्कूल को सामर्थ्य के अनुरूप फीस लेने की अनुमति दी जाती है, तो यह डिग्री की "खरीद" होगी, तर्कहीन है, क्योंकि शिक्षा के मानक मान्यता, संबद्धता और आम अंतिम परीक्षाओं से संबंधित नियमों द्वारा से नियंत्रित किए जा सकते हैं।

\*\*\*\*\*

66. निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा सम्बंधित संस्थान के मामले में मान्यता या संबद्धता प्रदान करने वाला प्राधिकरण निश्चित रूप से मान्यता या संबद्धता प्रदान करने की शर्तें निर्धारित कर सकते हैं; ये शर्तें व्यापक रूप से शिक्षा सम्बन्धी और शैक्षिक मामलों और छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित होनी चाहिए-लेकिन निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को कैसे चलाया जाए, यह ऐसा प्रशासनिक मामला है जिसका ध्यान उन संस्थानों के प्रबंधन द्वारा रखा जाना है।

### इस्लामी शिक्षा अकादमी से

"7. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, हमारे विचार में बहुमत का निर्णय बहुत स्पष्ट है। सरकार द्वारा कोई ठोस फीस संरचना तय नहीं की जा सकती है। प्रत्येक संस्थान को संस्थान चलाने के लिए धन जुटाने और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी फीस संरचना तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें ऐसा अधिशेष उत्पन्न करने में भी समर्थ होना चाहिए जिसका उपयोग उस शैक्षणिक संस्थान की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 56 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थानों जो सरकार से किसी भी धन की मांग नहीं करते हैं और जो किसी भी प्रकार से सरकार के धन पर निर्भर नहीं हैं, द्वारा फीस लेने का निर्णय अनिवार्य रूप से उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रत्येक संस्थान अपनी फीस संरचना को बनाए रखने का हकदार होगा। प्रत्येक संस्थान के लिए फीस संरचना उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, किए

गए निवेश, शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, संस्थान के विस्तार और/या बेहतरी के लिए भविष्य की योजनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। बेशक कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और प्रतिव्यक्ति फीस नहीं ली जा सकती है। अतः इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि बहुमत के निर्णय के अनुसार शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य रूप से हितकारी प्रकृति का काम है इस प्रकार जो अधिशेष/लाभ उत्पन्न किया जा सकता है वह केवल उस शैक्षणिक संस्थान के लाभ/उपयोग के लिए होना चाहिए। लाभ/अधिशेष का उपयोग किसी अन्य उपयोग या उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य व्यवसाय या उद्यम के लिए नहीं किया जा सकता है। चूंकि, वर्तमान में, ऐसे कानून/विनियम हैं जो फीस को अधिनियमित करते हैं और चूंकि इस न्यायालय ने अभी तक उन कानूनों/विनियमों की वैधता पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि **टी.एम.ए. पाई** मामले में निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संबंधित प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा, जिसे उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किया जाएगा। अन्य सदस्य, जिन्हें न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, को प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद (संक्षेप में "एमसीआई") या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में "एआईसीटीई") का प्रतिनिधि भी संस्थान के प्रकार के अनुरूप सदस्य होगा। चिकित्सा शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का प्रभारी राज्य सरकार का सचिव, जो भी हो, समिति का सदस्य और सचिव होगा। समिति को किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामित करने/सह-चयन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक न हो। प्रत्येक शिक्षा सम्बन्धी संस्थान को अपनी प्रस्तावित फीस संरचना को अकादमिक वर्ष से काफी पहले इस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावित फीस संरचना के साथ-साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और लेखा

पुस्तकों को भी जांच के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद समिति यह तय करेगी कि क्या उस संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित हैं और क्या वे मुनाफाखोरी या प्रतिव्यक्ति शुल्क तो नहीं ले रहे हैं। समिति फीस संरचना को मंजूरी देने या संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी अन्य फीस का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगी जो लिया जा सकता है। समिति द्वारा निर्धारित फीस तीन साल की अवधि के लिए बाध्यकारी होगी, जिसके अंत में संस्थान संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। एक बार समिति द्वारा फीस निर्धारित किए जाने के बाद, संस्थान फीस के रूप में निर्धारित राशि के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अन्य राशि नहीं ले सकता है। यदि कोई अन्य राशि ली जाती है, तो किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत या किसी छुपे रूप जैसे दान के तहत, वही प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने के बराबर होगा। यदि पहले से ही तैयार नहीं किए गए हैं, तो सरकारों/उपयुक्त अधिकारियों को उचित नियम बनाने पर विचार करना चाहिए, जिसके तहत यह पाया जाता है कि कोई संस्थान प्रतिव्यक्ति शुल्क ले रहा है या उस संस्थान से मुनाफाखोरी कर रहा है तो उसे उचित रूप से दंडित किया जा सकता है और इसकी मान्यता/संबद्धता खोने की संभावना का भी सामना करना पड़ सकता है।

### मॉडर्न स्कूल से

14. शुरुआत में, 1973 के अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने से पहले, हम यह कह सकते हैं कि अब इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि फीस संरचना के निर्धारण के मामले में गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान बड़ी स्वायत्तता रखते हैं क्योंकि वे, किसी भी अन्य नागरिक की तरह, शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के लिए उपयुक्त अधिशेष के हकदार हैं। यह माना गया है कि ऐसे संस्थानों को अपने निवेश और व्यय की योजना बनानी होगी ताकि उच्च स्तर का लाभ उत्पन्न किया जा सके। हालाँकि, जो प्रतिषिद्ध है वह शिक्षा का व्यावसायीकरण है। इसलिए, हमें ऐसे संस्थानों की स्वायत्तता और



शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बीच संतुलन बनाना होगा हालांकि, पहले किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने उचित अधिशेष लाभ, आय और उपज, की अवधारणा को परिभाषित नहीं किया है, जो 1973 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द हैं।

15. 1957 में **बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमरबागवाला** मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि शिक्षा अपने आप में एक हितकारी कार्य है। शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। तथापि, राज्य अपनी वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा प्रदान करने का कार्य काफी हद तक स्वयं नागरिकों द्वारा किया गया है। उन्नी कृष्णन, **जे.पी बनाम ए.पी. राज्य** मामले में उपरोक्त वास्तविकताओं को देखते हुए, इस न्यायालय ने एक स्व-वित्तपोषित तंत्र/योजना तैयार की, जिसके तहत संस्थान अपनी पसंद के 50% छात्रों को प्रवेश देने के हकदार थे क्योंकि वे स्व-वित्तपोषित संस्थान थे, जबकि शेष सीटें राज्य द्वारा भरी जानी थीं। छात्रों के प्रवेश के लिए, एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी थी। उसमें मुफ्त सीटों और भुगतान सीटों का प्रावधान किया गया था। भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि सहित राज्य और विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों को विनियम बनाने और/या संशोधित करने का निर्देश दिया गया था ताकि उन्हें उक्त योजना के बराबर लाया जा सके। **टीएमए पाई फाउंडेशन** मामले में, उन्नी कृष्णन के मामले में इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई उक्त योजना को संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ के अंतर्गत एक अनुचित प्रतिबंध माना गया था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप राजस्व की कमी हुई जिससे शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुश्किल हो गई। परिणामस्वरूप, उन्नी कृष्णन मामले में निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों और निर्देशों को असंवैधानिक माना गया। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा कि किसी संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार में छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार

शामिल है; एक उचित फीस संरचना स्थापित करने का अधिकार; एक शासी निकाय का गठन करने का अधिकार, कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार शामिल है।

**टी.म.ए. पाई फाउंडेशन** मामले ने पहली बार शिक्षा की अवधारणा को "व्यवसाय" के रूप में अस्तित्व में लाया, यह शब्द संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) में इस्तेमाल किया गया है। यह बहुमत से माना गया था कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 26 क्रमशः सभी नागरिकों और धार्मिक संप्रदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। हालांकि, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक संस्था स्थापित करने का अधिकार उसके खंड (6) के संदर्भ में उचित प्रतिबंध के अधीन है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित और संचालित करने का प्रदत्त अधिकार युक्तियुक्त विनियमों के अधीन माना जाता है जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ जनहित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है। उक्त निर्णय में, यह देखा गया था (पैरा 56 के अनुसार) कि शुल्क निर्धारण के मामले में आर्थिक ताकतों की भूमिका है। निवेश और व्यय का प्रावधान करने के बाद संस्थाओं को उचित लाभ कमाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, प्रतिव्यक्ति शुल्क और मुनाफाखोरी को निषिद्ध माना गया था। उपरोक्त दो निषेधात्मक मापदंडों के अधीन, **टीएमए पाई फाउंडेशन** मामले में इस न्यायालय ने कहा कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारे समक्ष मुद्दा यह है कि 1973 के अधिनियम के उपबंधों के संदर्भ में युक्तिसंगत अधिशेष क्या है। **टीएमए पाई फाउंडेशन** मामले में इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा नहीं था।

पी. ए इनामदार से

“121. राज्य या बोर्ड या ऐसा करने के लिए सक्षम विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता या मान्यता को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संस्थान एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। तथापि, संबद्धता अथवा मान्यता की इच्छा अथवा आवश्यकता से योग्यता सुनिश्चित करने, शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने तथा कुप्रशासन को रोकने की आवश्यकता के अनुरूप शर्तें निर्धारित करके विनियमन की अवधारणा सामने आती है। उदाहरण के लिए, शिक्षकों की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए उनके लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं और अध्ययन के पाठ्यक्रम और करिक्यूलम निर्धारित करके प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अस्तित्व को मान्यता या संबद्धता प्रदान करने के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। छात्रों के प्रवेश, कर्मचारियों की भर्ती और लिए जाने वाले शुल्क की मात्रा सहित प्रबंधन के आवश्यक घटकों को विनियमित नहीं किया जा सकता है।

\*\*\*\*

141. प्रश्न 3 के सम्बन्ध में हमारा उत्तर यह है कि प्रत्येक संस्थान अपनी स्वयं की फीस संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इसे विनियमित किया जा सकता है। कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

142. **इस्लामिक अकादमी** के उस हिस्से पर याचिकाकर्ता आवेदकों के लिए उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा सबसे जोरदार हमला किया गया था, जिसने प्रवेश और शुल्क संरचना से निपटने वाली दो समितियों के गठन का निर्देश दिया है। न्यायालय का ध्यान **पाई फाउंडेशन** के पैरा 35, 37, 38, 45 और 161 (प्रश्न 9 का उत्तर) की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें **उन्नी कृष्णन** मामले में बनाई गई इसी तरह की योजना को

विशेष रूप से रद्द कर दिया गया था। पैरा 45 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति कृपाल ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि **उन्नी कृष्णन** मामले में जहां तक इसमें प्रवेश देने और फीस निर्धारण से संबंधित योजना तैयार की गई थी, सही नहीं था और उस सीमा तक उक्त निर्णय और यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, केन्द्र और राज्य सरकारों को दिए गए परिणामी निर्देशों, आदि को खारिज कर दिया जाता है। पैरा 161 के अनुसार, **पाई फाउंडेशन** ने **उन्नी कृष्णन** को उस हद तक बरकरार रखा की वह प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन इस योजना को नामंजूर कर दिया गया। तथापि, इस सिद्धांत को बरकरार रखा गया कि प्रतिव्यक्ति शुल्क अथवा मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं को सुविधाओं के विस्तार और संवर्धन की लागत को पूरा करने के लिए उचित अधिशेष उत्पन्न करने की अनुमति दी गई थी जिससे मुनाफाखोरी नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि **इस्लामिक अकादमी** ने एक बार फिर ऐसी समितियों को बहाल किया है जिन्हें **पाई फाउंडेशन** द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

### कोचीन विश्वविद्यालय से

"11. शुरुआत में, यह देखा जाना चाहिए कि विवाद केवल दो वर्षों से संबंधित है और आज तक कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हुई है, क्योंकि अब फीस संरचना **टी. एम. ए. पाई** मामले में निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत गठित समितियों द्वारा तैयार की गई है। हमारा यह भी विचार है कि फीस निर्धारण से संबंधित मामला किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का हिस्सा है और यह ऐसे संस्थान पर अधिक भार डालेगा जिसे गणितीय सटीकता के साथ शुल्क लगाने का औचित्य साबित करने के लिए कहा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने शुल्क निर्धारण के संबंध में कई व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं और आज की तिथि में इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों द्वारा उन सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है।

12. प्रारंभ में ही यह समझ लिया जाना चाहिए कि कोई शैक्षणिक संस्थान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के आधार पर वर्षवार अपना कार्यक्रम तैयार करता है और न्यायालय द्वारा इस विशुद्ध प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करना इस अधिकार का अत्यधिक अतिक्रमण होगा। हालांकि, इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थान के पास अपनी पसंद का कोई भी फीस तय करने का पूर्णाधिकार है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त स्वायत्तता छोड़ी जानी चाहिए। श्री राव ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि निस्संदेह एक शैक्षणिक संस्थान अपनी फीस तय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह स्वतंत्रता कुछ व्यापक सिद्धांतों के अधीन है। तदनुसार, हमने अपीलार्थी विश्वविद्यालय द्वारा दायर शपथपत्रों का अध्ययन किया है और उनके अनुसार विश्वविद्यालय ने वर्ष 1995-1996 में नया पाठ्यक्रम बनाया था जिसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास, एक संकाय के विकास के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ होगा शिक्षण और सहायक कर्मचारियों के लिए पर्याप्त वेतन का प्रावधान करना ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। दूसरे शपथपत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि फीस पहले बढ़ाई गई थी और बाद में कम की गई थी क्योंकि अनुभव से पता चला था कि प्रति वर्ष \$5000 अमेरिकी डॉलर की राशि अत्यधिक थी और बड़ी संख्या में उन एन आरआई छात्रों पर विचार नहीं किया गया जो फीस वहन नहीं कर सकते थे और इस श्रेणी के बीच एक बड़े हिस्से को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, फीस कम कर दी गई थी। हमारी राय है कि दो शपथपत्रों में इन दो दृष्टिकोणों को लेने में विश्वविद्यालय की कोई विरोधाभास या गलती नहीं पाई जा सकती है क्योंकि वे एक-दूसरे के पूरक हैं और फीस में प्रारंभिक वृद्धि और बाद में उसे कम करने के संशोधन के लिए औचित्य बनाते हैं।

46. **महावीर सीनियर मॉडल सेकेंडरी स्कूल** ने भी यही विचार अपनाया है। निर्णय से निम्नलिखित अंश प्रत्युत्पादन के योग्य हैं:

"17. भले ही डीएसईए के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया है जिसमें गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शुल्क वृद्धि से पहले डीओई से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, फिर भी डीओई डीएसईए और डीएसईआर की धारा 17(3) और 18(3) और (4) से उत्पन्न नियामक नियंत्रण का प्रयोग करता है। हालांकि, शुल्क संरचना को विनियमित करते समय, डीओई एक अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है। यह विद्यालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक की शुद्धता का विश्लेषण करने की शक्ति के साथ निहित नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का हकदार है कि विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण में शामिल न हो। विनियामक क्षेत्राधिकार की सीमाएँ सीमित और प्रतिबंधित हैं, जैसा कि इसके बाद उल्लिखित न्यायिक पूर्व निर्णय द्वारा स्पष्ट किया गया है।

\*\*\*\*\*

22. ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों ने अपने प्रबंधन और प्रशासन में निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के स्व-शासन और सरकारी पर्यवेक्षण की सीमा के बीच परस्पर क्रिया को व्यापक रूप से स्पष्ट किया है। हालाँकि, यह चर्चा मॉडर्न स्कूल मामले [मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ, (2004) 5 एससीसी 583] के निर्णय के संदर्भ के बिना अपर्याप्त होगी, जिसमें गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस की राशि को विनियमित करने में डीओई के अधिकार क्षेत्र की विस्तार और दायरे पर चर्चा की गई है। इसमें, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को संस्थान के विकास और उन्नति के लिए उचित अधिशेष का अधिकार है और शिक्षा विभाग के पास शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए फीस और अन्य शुल्कों को विनियमित करने का अधिकार है। यदि कोई निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण में शामिल नहीं है, तो उसे अपनी फीस संरचना तय

करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और डीएसईए के तहत इसकी स्वायत्तता का सम्मान और समर्थन किया जाना चाहिए।

\*\*\*\*\*

23. यह हमें आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के आधार पर लाता है। स्कूलों ने आरोपों का जवाब देने का अवसर न दिए जाने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। निष्पक्ष सुनवाई का यह सिद्धांत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आधारशिला है और किसी भी कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश प्रस्तावित अस्वीकृति की पूर्व सूचना के बिना जारी किया गया था। इस तर्क का कोई ठोस जवाब नहीं है। न्यायालय का विचार है कि विवादित आदेश में उल्लिखित कथित विसंगतियों का खुलासा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व स्कूलों को किया जाना चाहिए था, जिससे उन्हें जवाब देने का पर्याप्त अवसर मिल सके। इस सिद्धांत का पालन निर्णय लेने की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाएगा और किसी मामले के परिणाम को प्रभावित करने से पक्षपात या पूर्वाग्रह को रोकेगा। इस प्रकार, डीओई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों को सभी प्रासंगिक सामग्री और जानकारी प्रदान की जाए, जिसमें नियामक प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति या चिंताओं का आधार भी शामिल है, जबकि शुल्क के विवरण को संक्षिप्त किया जाए। इससे स्कूलों को अपना रुख सार्थक तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। उस ने कहा, न्यायालय की राय में, इस समय मामले को डीओई को वापस भेजने के बजाय, अपने गुणावगुण के आधार पर आक्षेपित आदेश की वैधता का मूल्यांकन करना उचित होगा।

\*\*\*\*\*

27. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के शुल्क विवरणों में उल्लिखित निधियों की पर्याप्तता की जांच की है और उन्हें कई शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया है, और फिर निष्कर्ष निकाला है कि जूनियर स्कूल के पास 5,71,43,088 रुपये और सीनियर स्कूल के पास 2,19,81,079 रुपये अधिशेष थे। इन

संचित भंडारों के आधार पर, शिक्षा विभाग ने बढ़ी हुई फीस संरचना को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता स्कूलों ने डीओई की गणना के आधार को चुनौती दी है और दोनों पक्षों ने उपलब्ध धन के तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किए हैं। हालांकि, न्यायालय को आंकड़ों का समर्थन करने वाले अंकगणितीय कामकाज का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक है, और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह डीओई के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है, यह निर्धारित करने के लिए आक्षेपित आदेश में निर्धारित निष्कर्षों तक इसकी जांच को सीमित करेगा।

\*\*\*\*\*

31. वर्तमान मामले में, डीओई ने स्कूलों के पास उपलब्ध अधिशेष की पुनः गणना की है और कहा है कि यह उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार, उन्हें फीस बढ़ाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। डीओई द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण, न्यायालय की राय में, गलत और अस्वीकार्य है। "उचित" अधिशेष का निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा जैसे कि स्कूल का आकार, प्रदान की गई बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं का स्तर, कर्मचारियों का वेतन और स्कूल की समग्र वित्तीय स्थिति। अपने फीस विवरण में, सीनियर स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2018-2019 में होने वाले अनुमानित खर्चों के साथ-साथ उनके द्वारा उत्पन्न आय का एक विस्तृत चार्ट भी शामिल किया है। इसलिए, उनके वित्तीय संचालन में पारदर्शिता है और उन्हें धन के उपयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रबंधन 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्कूल संयंत्र को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने का इरादा रखता है, और इस उद्देश्य के लिए एक वास्तुकार के साथ अनुबंध भी किया है। चूंकि न्यायालय इस मुद्दे पर अपील में नहीं बैठना चाहेगी, इसलिए उसने उसमें उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता की जांच करने से परहेज किया है, फिर भी श्री गुप्ता के निवेदन में पर्याप्त योग्यता पाई गई है कि 1983 से संचालित सीनियर स्कूल को पुनर्निर्माण और सहबद्ध



क्रियाकलाप के लिए धन की आवश्यकता होगी। शिक्षा विभाग को यह याद रखना चाहिए कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने प्रशासन में स्वायत्तता प्राप्त है, जिसमें इसके विकास और विस्तार की कल्पना और योजना बनाने की स्वायत्तता शामिल है; वे अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा के लिए स्कूलों के लिए पर्याप्त राशि के बारे में अपनी व्यक्तिपरक राय नहीं थोप सकते हैं। तत्काल मामले में, स्कूलों द्वारा प्रदान की गई संपरीक्षित लेखा तुलनपत्र और सामग्री पर बिना किसी वैध स्पष्टीकरण के फिर से काम किया गया है। निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के संपरीक्षित लेखा तुलनपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो उनकी वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन दर्शाते हैं। ये दस्तावेज़ स्कूल की आर्थिक स्थिति की एक स्पष्ट और पारदर्शी तस्वीर प्रदान करते हैं और यह आकलन करने में मदद करते हैं कि क्या स्कूल के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और क्या फीस वृद्धि न्यायोचित है। डीओई एक अपीलिय निकाय के रूप में कार्य करते हुए किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में उक्त वित्तीय दस्तावेजों को यह दर्शाने के लिए अस्वीकार नहीं कर सकता है कि खाते लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे या कर अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिए गए थे। उल्लेखनीय रूप से, स्कूलों द्वारा जमा किए गए रिटर्न और दस्तावेजों के प्रारूप पर डीओई ने आपत्ति उठाई थी; हालाँकि, उक्त प्रश्न के उत्तर में, स्कूलों ने स्पष्ट किया था कि वे निर्धारित प्रारूप का उपयोग कर रहे हैं। आक्षेपित आदेश में इस मुद्दे पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसलिए, शिक्षा विभाग ने उचित कारणों का खुलासा किए बिना, या शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण का पता लगाए बिना बैलेंस शीट पर फिर से काम करने की कवायद शुरू की है। यह अभ्यास बिना किसी वस्तुनिष्ठ मानदंड के, डीओई की व्यक्तिपरक राय को दर्शाता है, जो पूरी प्रक्रिया को मनमाना और अनुचित बनाता है। छात्रों से ली जाने वाली फीस का निर्धारण करने के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के अधिकार को केवल उनके लेखा पुस्तकों में उचित अधिशेष की उपस्थिति के कारण ही बाधित नहीं किया जा सकता है। डीओई स्कूलों द्वारा प्रस्तुत अधिशेष

आंकड़ों की सत्यता की जांच कर सकता था, परंतु फीस वृद्धि से इनकार करने के लिए, उन्हें विश्वसनीय आधार पर यह आदेश करना चाहिए कि स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण, मुनाफाखोरी या प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाने में लिप्त है। स्कूल प्रबंधन समिति ने संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट तय करने की कवायद सावधानीपूर्वक की थी और शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के निष्कर्ष के बिना, शिक्षा विभाग ने अपनी शक्तियों से अधिक काम किया है और सीनियर स्कूल की प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को अस्वीकार करने में कानून द्वारा संरक्षित स्कूलों की स्वायत्तता को बाधित किया है।

47. उन गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के समान जो ऐसी भूमि पर स्थित हैं जिनके पट्टा विलेख या किसी अन्य दस्तावेज़ में परिचर "भूमि खंड" नहीं है, उपर्युक्त निर्णय समान रूप से यह मानते हैं कि डीओई के पास स्कूल की फीस विनियमित करने या अपने स्वयं के इस व्यक्तिपरक निर्णय पर पहुंचने का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि स्कूल के खातों में जो अधिशेष राशि है वह उनके द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के समान मुनाफाखोरी के किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, शिक्षा निदेशालय स्कूल को अपनी फीस बढ़ाने से नहीं रोक सकता है।

48. यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अभिभावकों से मिलने वाली फीस पर ही निर्भर रहते हैं। यदि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस जिसे वह वैध रूप से अभिभावकों से ले सकते हैं, के मामले में सख्त करी तो उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की उम्मीद निरर्थक है।

49. "प्रतिव्यक्ति शुल्क" और "मुनाफाखोरी" की परिभाषाएँ पहले से ही कानून या पूर्व निर्णय द्वारा परिभाषित की गई हैं। न्या. एस.बी.सिन्हा, ने *इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन* में अपने समान निर्णय में, अनुमोदन के साथ, "मुनाफाखोरी" की परिभाषा को अपनाया, जैसा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निहित है, "अत्यधिक लाभ कमाने के लिए असामान्य या असाधारण परिस्थितियों का लाभ उठाना"। "आरटीई अधिनियम की धारा 2(ई) में "प्रतिव्यक्ति शुल्क" को "स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार के दान या योगदान या भुगतान" के रूप में परिभाषित किया गया है।

50. वर्तमान मामले में आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने या मुनाफाखोरी में लिप्त था।

51. श्री झा ने तर्क देते हैं कि भले ही विवादित आदेश में "प्रतिव्यक्ति शुल्क" या "मुनाफाखोरी" शब्दों का विशेष रूप से उपयोग नहीं किया गया हो, अगर विवादित आदेश में आरोप प्रतिव्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी के तत्वों को निर्धारित करते हैं, तो यह इसके जारी करने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।

52. मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार दोहराया है कि डीओई द्वारा हस्तक्षेप का दायरा, एक गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा शुल्क के निर्धारण के साथ, उस

मामले तक सीमित है जिसमें स्कूल प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने या मुनाफाखोरी में लिप्त होता है। इसलिए इन शब्दों को केवल नाम मात्र नहीं माना जा सकता है। वे विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं, जिनके विशिष्ट कानूनी संकेतार्थ हैं। यदि शिक्षा विभाग का मानना है कि कोई शैक्षणिक संस्थान प्रतिव्यक्ति शुल्क ले रहा है या मुनाफाखोरी में लिप्त है, तो वह विशेष रूप से आरोपी होगा। इस तरह के किसी भी आरोप के अभाव में, उन शब्दों में, डीओई के पास स्कूल द्वारा निर्धारित शुल्क में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

53. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि इसमें प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने या मुनाफाखोरी करने का कोई आरोप नहीं है। इस बात का कोई आरोप नहीं है कि स्कूल अपने द्वारा अधिसूचित फीस से अधिक फीस ले रहा था। प्रतिव्यक्ति शुल्क लेना लगभग भर्षाचार के बराबर है। इसमें ऐसे विद्यालय, या शैक्षिक संस्थान शामिल हैं, जो फीस को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ गोपनीय शुल्क छात्रों या उनके अभिभावकों या अभिभावकों से अतिरिक्त राशि के रूप में लेते हैं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है।

54. न ही ऐसा कोई आरोप है कि याचिकाकर्ता मुनाफाखोरी में लिप्त था। वास्तव में, जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित लाभ का संबंध है, आक्षेपित आदेश में

केवल यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास मौजूद अधिशेष सातवें सीपीसी द्वारा डाले गये अतिरिक्त वित्तीय बोझ से निपटने के लिए पर्याप्त था। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता अत्यधिक लाभ कमाने के लिए किसी भी असाधारण परिस्थितियों का लाभ उठा रहा था।

55. इसलिए, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने या मुनाफाखोरी का न तो कोई प्रत्यक्ष और न ही कोई गुप्त आरोप है।

56. जिन निर्णयों को ऊपर उद्धृत किया गया है, वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि "शिक्षा के व्यावसायीकरण" की अवधारणा प्रतिव्यक्ति शुल्क और मुनाफाखोरी के विचार तक सीमित है। इसलिए, यदि यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि स्कूल प्रतिव्यक्ति शुल्क ले रहा है या स्कूल मुनाफाखोरी में लिप्त है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहा है।

57. इसलिए, यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत निर्णयों में निर्धारित कानून की परिधि के अंतर्गत आता है और इस न्यायालय द्वारा रामजस स्कूल और महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के मामले में अपने निर्णयों में इसका उल्लेख किया गया है।

58. श्री कमल गुप्ता के इस तर्क का यह सार है कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है जिसका **रामजस स्कूल** और **महावीर सीनियर मॉडल स्कूल** के निर्णयों के अनुसार, आक्षेपित आदेश

पारित करने से पूर्व निष्ठा से पालन किया जाना आवश्यक था। याचिकाकर्ता को न तो विवादित आदेश के पैरा 1 से 7 में निहित आरोपों के बारे में सूचित किया गया था, न ही उसे डीओई को यह समझाने का कोई अवसर दिया गया था कि वास्तव में उसे अपने शुल्क में वृद्धि करने की आवश्यकता थी क्योंकि उसने अपने अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, डीओई, अन्यथा भी, याचिकाकर्ता की प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता था कि उसके विचार में याचिकाकर्ता के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिशेष राशि थी।

59. श्री झा द्वारा यह भी इंगित करने की मांग की गई थी कि आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अन्य आरोप हैं जैसे कि उसके खातों में परिवहन भत्ता की प्रविष्टि न होना, इसकी प्रारंभिक और समापन शेष राशि के बीच विसंगति, डीओई द्वारा अधिसूचित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विकास शुल्क का उपयोग। ये ऐसे विचार नहीं हैं जिनके आधार पर डीओई याचिकाकर्ता को अपनी फीस बढ़ाने से रोक सकता था। जैसा कि श्री कमल गुप्ता ने सही बताया, इस तरह के आरोप लगभग हर आदेश में मौजूद हैं। **रामजस स्कूल और महावीर सीनियर मॉडल स्कूल** में चुनौती के तहत आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि, उन मामलों में भी समस्या के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आने से पहले विभिन्न वित्तीय विसंगतियों का आरोप लगाया गया था, जो 7 वीं सीपीसी

सिफारिशों के अनुपालन की आवश्यकता से उस पर डाले गए अतिरिक्त वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए स्कूलों के खातों में अधिशेष राशि "पर्याप्त" थी।

60. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान मामले में इस न्यायालय के सीमित परिहार को देखते हुए मैं विवादित आदेश के पैरा 1 से 7 में निहित आरोपों के विवरण या गुणावगुण में नहीं जा रहा हूं। डीओई को उक्त आरोपों के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी, निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता के प्रतिकूल कोई भी निर्णय अधिनियम, नियमों और विनियमों और लागू दिशानिर्देशों का पालन किए बिना और नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं लिया जाएगा।

### **निष्कर्ष**

61. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-स्कूल द्वारा फीस में वृद्धि को प्रतिबंधित करने का आक्षेपित आदेश तथ्यों या कानून द्वारा कायम नहीं रह सकता है। इसलिए, 01.08.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और जुर्माने के किसी आदेश के अभाव में उक्त सीमा तक अपास्त कर दिया जाता है।

**रि.या.(सि.)6419/2019**

62. जहां तक कानूनी स्थिति का संबंध है, इस मामले के तथ्य काफी हद तक रि.या.(सि.) 8794/2018 के तथ्यों के समान हैं। इस मामले में आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:

"शिक्षा उप-निदेशालय का कार्यालय  
उत्तरी जिला  
लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली-110054

सं. डीडीई(एन)/पीआर. बीआर./2019/188-192 दिनांक: 20/04/19

**आदेश**

लीलावती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी. स्कूल, शक्ति नगर, दिल्ली-110007 एक गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल है जो दिल्ली के शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि. के उत्तर जिला अधिकार क्षेत्र में चल रहा है और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के तहत निहित प्रावधानों का पालन करने और समय-समय पर शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

और हर स्कूल को डी.एस.ई.ए.आर., 1973 के खंड 17 (3) और शिक्षा निदेशक के आदेश सं. डीई.15 (318)/पीएसबी/2016/19742 के माध्यम से डी.एस.ई.ए.आर., 1973 की धारा 2 की उपधारा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिनके अनुसार "निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा अभिभावकों से एकत्रित की गई या एकत्रित की जाने वाली फीस के विनियमन के सम्बन्ध में डी.एस.ई.ए.आर., 1973 की धारा 17 (3) के अर्थ, विस्तार और दायरे के अंतर्गत और उक्त प्रावधान के



अधीन लगाई गई सीमाओं और शर्तों के अधीन रा.रा.दि.स. के शिक्षा निदेशालय की शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन शिक्षा निदेशक (जिला) द्वारा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन स्कूल द्वारा दायर फीस के पूरे विवरण की जाँच करके और स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस लेने के मामले में उसे अतिरिक्त फीस को कम/बदलने या वापिस करने के निर्देश देकर किया जाएगा” और साथ ही मॉडर्न स्कूल मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के अधीन फीस का पूर्ण विवरण देना होगा।

और जबकि, 27/04/2017 को अभिभावकों द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि स्कूल ने उक्त सत्र की ट्यूशन फीस बढ़ा दी थी।

और जबकि, उक्त अभिभावकों ने 20/11/2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 10804/2017 भी दायर की है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 (3) के तहत स्कूल द्वारा दायर फीस के पूर्ण विवरण की जांच करने का निर्णय लिया गया।

और जबकि, तदनुसार लीलावती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शक्ति नगर, दिल्ली, स्कूल के प्रबंधक/एचओएस को कार्यालय आदेश दिनांक 02-08-2018, 06-08-2018 और 23-02-2019 के माध्यम से वर्ष 2017-18 से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

और जबकि, नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, स्कूल के अध्यक्ष/प्रबंधक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और तदनुसार आदेश संख्या 198/VII द्वारा 20/02/2019 को शाम 4:00 बजे

उप-निदेशक शिक्षा के कार्यालय में उपस्थित होने और 23/02/2019 को नोट किए गए विभिन्न मुद्दों पर दस्तावेज/सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था और स्कूल 23/02/2019 को शाम 4:00 बजे शिक्षा उप-निदेशक के कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहा, और साथ ही उसकी तरफ से नोट किए गए मुद्दों पर कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

और जबकि, स्कूल नोट किए गए पूर्वोक्त मुद्दों पर दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा और इसलिए, 23/03/2019 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में, 03/04/2019 को संख्या 305 के माध्यम से एक अनुस्मारक भी जारी किया गया, जिसमें अपनी बात के समर्थन में स्कूल अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत न करने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। स्मरणपत्र के उत्तर में, स्कूल ने अंततः दिनांक 15-04-2019 के पत्र संख्या 5594/एलवीएम द्वारा कुछ अभिलेख और स्पष्टीकरण के साथ एक उत्तर प्रस्तुत किया।

और जबकि, स्कूल की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया गया है कि स्कूल द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज और स्पष्टीकरण अधूरे हैं। स्कूल के उत्तर विश्लेषण नीचे दिया गया है:

बिं

क्र.सं. वा र	आवश्यकताएं	स्कूल का उत्तर/प्रस्तुतीकर ण	टिप्पणी
भाग क			

	<p>वित्त वर्ष 2012-13, 2013- 14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए स्कूल द्वारा ली गई उपदान और अवकाश नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति;</p>	<p>केंद्र सरकार के सेवा नियमों के अनुसार उपदान और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया गया है और फंड के विरुद्ध निवेश निर्धारित किया गया है। उपदान के विरुद्ध एफडीआर के रूप में निवेश की राशि रु. 1,56,25,852 है।</p>	<p>स्कूल ने उपदान और अवकाश नकदीकरण के लिए बीमांकिक रिपोर्ट जमा नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रावधान प्रबंधन अनुमान के आधार पर किये गये हैं। इसके अलावा, स्कूल एलआईसी (या किसी अन्य एजेंसी) के साथ ऐसे प्रावधानों के सन्दर्भ में निवेश नहीं कर रहे हैं।</p>
2	<p>यदि एलआईसी (या किसी अन्य एजेंसी) के साथ उपरोक्त प्रावधान के सन्दर्भ में कोई निवेश किया गया है?</p>		
3	<p>लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ वित्त वर्ष 2017-18 (पूर्ण सेट) के लिए संपरीक्षित लेखा वित्तीय विवरणों की प्रति;</p>	<p>वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संपरीक्षित लेखा बैलेंस शीट की प्रति संलग्न है।</p>	<p>अभिलेख पर लिया गया</p>

4	डीएसईआर, 1973 के नियम 180 के तहत दायर विवरणी प्रस्तुत करते समय विभाग के पास दायर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजटीय प्राप्ति और भुगतान खाते की प्रति;	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों की प्रति संलग्न है।	अभिलेख पर लिया गया
5	कृपया सत्र 2017-18 के वास्तविक व्यय की तुलना में सत्र 2018-19 के लिए प्रस्तावित व्यय में वृद्धि/कमी के लिए उचित न्यायोचित्य प्रदान करें।	व्यय में वृद्धि और कमी का न्यायोचित्य संलग्न है।	अभिलेख पर लिया गया
6	कृपया सत्र 2017-18 के वास्तविक व्यय की तुलना में सत्र 2018-19 के लिए प्रस्तावित आय में वृद्धि/कमी के लिए उचित न्यायोचित्य प्रदान करें		
7	कृपया वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान स्कूल द्वारा रखी गई /खरीदी गई कार, बसों की आरसी और चालान की प्रति लाएं।	स्कूल वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।	स्कूल के प्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट नहीं है कि स्कूल के पास कितनी बसें और कारें उपलब्ध हैं। स्कूल को पूर्ण आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।
8	कृपया आज की स्थिति के अनुसार एफडीआर की प्रति लाएं। एफडीआर का विवरण भी साझा करें जैसे कि इसे किस निधि के विरुद्ध बनाए रखा गया है।	संबंधित उपयोग के साथ संलग्न एफडीआर की सूची	स्वीकृत।
<b>भाग बी</b>			

1	कृपया वेतन के भुगतान की प्रक्रिया को परिभाषित करें। क्या कर्मचारियों को भुगतान नकद प्रणाली के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से किया जा रहा है;	वेतन के भुगतान का तरीका स्टाफ सदस्यों के संबंधित खाते में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से होता है	अभिलेख पर लिया गया														
2	क्या स्कूल वर्ष के दौरान विक्रेताओं को 20,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान कर रहा है। यदि हां, तो ऐसे लेनदेन की मात्रा क्या है;	इस वर्ष के दौरान 20000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं किया गया है।	अभिलेख पर लिया गया														
3	आय और व्यय खाते से राशि 'छात्र निधि और कर्मचारी हितकारी निधि खाते में अंशदान' के नाम से काटी जाती है। इस तरह के व्यय का उद्देश्य और प्रकृति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ऐसे लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:		कोई स्पष्टीकरण या न्यायोचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। स्कूल को स्पष्टीकरण के साथ उचित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>वि.व 2012--13</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>वि.व2013-14</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>वि.व 2014-15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>वि.व 2015-16</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>वि.व2016-17</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	1.	वि.व 2012--13	2.	वि.व2013-14	3.	वि.व 2014-15	4.	वि.व 2015-16	5.	वि.व2016-17	कुल			
क्र.सं.	विवरण																
1.	वि.व 2012--13																
2.	वि.व2013-14																
3.	वि.व 2014-15																
4.	वि.व 2015-16																
5.	वि.व2016-17																
कुल																	

4	<p>वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, स्कूल ने 18,01,694 रुपये की कार खरीदी है। स्कूल को वित्त वर्ष 2012-13, 2013- 14, 2014-15, 2015-16 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में खरीदी गई कार का विवरण जैसे आरसी की कॉपी, चालान की कॉपी, ऐसी कार का उपयोगकर्ता, ऐसी कार के रखरखाव के लिए किए गए खर्च को जमा करना होगा।</p>	<p>स्कूल ने 2 कारों और 1 बस की आरसी जमा की है</p>	<p>स्कूल की दलील से यह स्पष्ट नहीं है कि स्कूल के पास कितनी बसें और कारें उपलब्ध हैं। खरीदी गई कार के चालान की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त कार का उपयोग कौन कर रहा है।</p>
5	<p>स्कूल ने वित्त वर्ष 2013-14 में 37,100 रुपये का दान दिया है। ऐसे दान का उद्देश्य रसीदों की प्रति सहित प्रदान किया जाना चाहिए। स्कूल को यह बताना होगा कि इस व्यय को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए योग्य व्यय क्यों माना जाना चाहिए।</p>	<p>कोई जबाव नहीं</p>	<p>स्कूल इस व्यय के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।</p>
6	<p>वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान, स्कूल फंड का उपयोग भवन निर्माण के लिए 13,78,982 रुपये और 5,29,850 रुपये का किया गया है। स्कूल को बताना होगा कि यह खर्च सोसाइटी से क्यों नहीं वसूला जाता, क्योंकि भवन निर्माण सोसाइटी की जिम्मेदारी है।</p>	<p>कोई जबाव नहीं</p>	

	<p>वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान, स्कूल फंड का उपयोग भवन निर्माण के लिए 13,78,982 रुपये और 5,29,850 रुपये का किया गया है। स्कूल को बताना होगा कि यह खर्च सोसाइटी से क्यों नहीं वसूला जाता, क्योंकि भवन निर्माण सोसाइटी की जिम्मेदारी है।</p>	<p>कोई जबाब नहीं</p>	<p>स्कूल इस व्यय के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है। 04 मई, 1997 के सार्वजनिक नोटिस के खंड 2 के अनुसार, "इमारत पूरी होने या अन्यथा होने पर स्कूल को बिल्डिंग फंड और विकास शुल्क नहीं लेना चाहिए।" चूंकि यह उस समाज की जिम्मेदारी है जिसने स्कूल की स्थापना की है कि वह अपने स्वयं के संसाधनों या अन्य संघों के दान से इस तरह की धनराशि जुटाए क्योंकि स्कूल की अचल संपत्ति सोसायटी की संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निर्माण सोसायटी की जिम्मेदारी है और इसलिए, यह राशि सोसायटी से वसूल की जानी चाहिए।</p>
	<p>स्कूल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में सोलर प्लान्ट लगाने पर खर्च किया है। कुल व्यय राशि 73,08,894 रुपये है। स्कूल को इतने बड़े खर्च का कारण बताना होगा</p>	<p>स्कूल की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं। इसने केवल 4 चालान की प्रतियाँ जमा की है।</p>	<p>स्कूल को यह बताना होगा कि ऐसी स्थापना के बाद उसे कितनी लागत की बचत हुई।</p>

ता लि का = सी (	यह ध्यान दिया जाता है कि स्कूल द्वारा किए गए व्यय आम तौर पर असंगत होते हैं क्योंकि या तो इनमें बड़ी वृद्धि या बड़ी कमी होती है। स्कूल को नीचे तालिका-सी में उल्लिखित विभिन्न खर्चों में इस तरह की वृद्धि या कमी के लिए उचित दस्तावेजों के साथ पूर्ण औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता है:	स्कूल ने पूछे गए व्ययों के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं दिया है जैसे कि स्कूल के खर्चों में असंगत गतिविधि क्यों हैं। इसने बिलों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।	व्यय में गतिविधि का कोई न्यायोचित्य नहीं दिया गया है।
--------------------------------	--	--	---

संख्या रूपये दर्शाती है)

क्र .	विशिष्ट ताएँ	2012-13	2013-14	वृद्धि/(कमी)%	2014-15	वृद्धि/(कमी)%	2015-16	वृद्धि/(कमी)%	2016-17	वृद्धि/(कमी)%
1.	शिक्षण कर्मचारी वेतन	4,34,47,918	4,84,41,420	11%	5,16,85,846	7%	5,45,44,358	6%	5,52,80,972	1%
2.	सहायक कर्मचारी वेतन	15,31,140	12,74,968	-17%	19,04,286	49%	20,52,778	8%	21,77,868	6%
3.	मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतन	26,13,587	20,89,219	-20%	30,71,629	47%	29,70,389	-3%	29,60,000	0%



4.	कंप्यूटर शिक्षा	40,28,4 56	40,74,8 20	1%	41,87,6 68	3%	37,68,8 08	-10%	46,48,5 00	23%
5.	डिजिटल इंटरएक्टिव कार्यक्रम शुल्क	33,16,0 00	28,56,0 00	-14%	28,56,0 00	0%	28,56,0 00	0%	30,76,1 10	8%
6.	समारोह और त्यौहार	9,95,23 0	20,28,9 14	104%	12,86,9 14	-37%	27,15,6 52	111%	2,56,64 0	-91%
7.	विद्यार्थियों और कर्मचारियों के कल्याण कोष में योगदान	20,00,0 00	20,00,0 00	0%	25,00,0 00	25%	5,00,0 0	-80%	5,00,0 0	0%
8.	सुरक्षा सेवा शुल्क	11,18,2 05	15,31,8 54	37%	16,68,0 68	9%	21,07,9 04	26%	24,46,0 25	-16%
9.	श्रमिकों/ संविदा कर्मचारियों को वेतन भुगतान	10,40,9 84	24,47,0 77	135%	32,92,2 77	35%	51,14,0 41	55%	77,03,6 64	51%

1 0.	स्वच्छता एवं संरक्षण	11,82,2 73,	19,71,5 45	67%	28,85,6 25	46%	25,43,5 63	-12%	23,68,8 82	-7%
1 1.	बिजली व्यय	11,76,2 80	13,92,0 60	18%	15,96,3 10	15%	21,06,2 87	32%	7,81,11 0	-63%
1 2.	वाहन संचालन एवं रखरखाव	6,38,03 4	6,71,92 5	5%	6,35,55 5	-5%	5,59,27 7	-12%	6,32,64 8	13%
1 3.	मरम्मत और रखरखाव	24,04,9 46	24,45,7 27	2%	47,99,6 53	96%	49,45,3 33	3%	92,55,1 98	87%
1 4.	सफेदी व्यय	9,80,56 0	8,03,27 2	-2%	19,97,4 95	149%	28,69,1 80	44%	25,83,1 58	-10%
1 5.	कैंटीन का दैनिक खर्च	-	-	0%	-	0%	26,65,3 50	0%	38,97,6 43	46%
	कुल	6,64,73 ,813	7,40,28 ,811		8,43,67 ,326		9,23,18 ,900		9,85,68 ,418	

और जबकि, स्कूल द्वारा प्रस्तुत खातों के विवरण और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री पत्राचार का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया है और विस्तृत निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

वित्तीय अनियमितताएँ:

1. 04 मई, 1997 की सार्वजनिक सूचना के खंड 2 के अनुसार, " जब भवन पूरा हो गया हो या अन्यथा तो स्कूल को भवन निधि और विकास शुल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह उस समाज की जिम्मेदारी है जिसने स्कूल की स्थापना की है कि वह अपने स्वयं के संसाधनों या अन्य संघों से दान से इस तरह के धन को जुटाए क्योंकि स्कूल की अचल संपत्ति समाज की संपत्ति बन जाती है। इसलिए, छात्रों पर भवन निधि और विकास शुल्क एकत्र कर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए"

इसके अतिरिक्त, डीएसईआर, 1973 के नियम 177 के अनुसार फीस के रूप में गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्राप्त आय का उपयोग सर्वप्रथम स्कूल के कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बशर्ते कि बचत, यदि ऐसे स्कूल द्वारा एकत्र की गई फीस में से कोई हो, का उपयोग उसकी प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल की पूंजी या आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए या निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए किया जाए, अर्थात् छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, उसी सोसाइटी या ट्रस्ट के प्रबंधन के तहत जिसके द्वारा पहला उल्लेखित स्कूल संचालित किया जाता है, के द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल की स्थापना, या किसी अन्य स्कूल या शैक्षणिक संस्थान की सहायता करना, जो कॉलेज नहीं है।

और, ऊपर उल्लिखित बचत निम्नलिखित के लिए प्रदान करने के नियत की जाएगी:

- क. स्कूल के कर्मचारियों को स्वीकार्य पेंशन, उपदान और अन्य निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ;
- ख. विद्यालय का आवश्यक विस्तार या विकासात्मक प्रकृति का कोई व्यय;

- ग. स्कूल भवन का विस्तार या किसी भवन के विस्तार या निर्माण या छात्रावास की स्थापना या छात्रावास आवास के विस्तार के लिए;
- घ. छात्रों की सह-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ;
- ङ. उचित आरक्षित निधि, ऐसी बचत के दस प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, भवन का निर्माण सोसायटी की जिम्मेदारी है और स्कूल के फंड से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसलिए, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 78,86,032 रुपये के भवन के लिए उपयोग की गई स्कूल निधि 04.05.1997 की सार्वजनिक सूचना और डीएसईआर, 1973 के नियम 177 का उल्लंघन है। इस राशि को स्कूल के पास उपलब्ध निधि का हिस्सा माना गया है और स्कूल को सोसायटी से इस राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5,50,65,084 रुपये की राशि के भवन निर्माण के लिए स्कूल निधि का भी उपयोग किया गया है। यह राशि स्कूल द्वारा सोसायटी से वसूल की जानी है।

2. प्रतिबंधित निधि से संबंधित आईसीएआई द्वारा जारी "स्कूल द्वारा लेखांकन" पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 99 के अनुसार, " जहां निधि पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए है, व्यय होने पर, संबंधित परिसंपत्ति खाते से डेबिट किया जाता है जिसका इस दिशानिर्देश लेख में निहित सिफारिशों के अनुसार मूल्यहास किया गया है। तत्पश्चात्, संबंधित प्रतिबंधित निधि खाते को परिसंपत्ति की लागत की सीमा तक आस्थगित आय माना जाता है और

प्रतिवर्ष प्रभारित मूल्यास के अनुपात में आय और व्यय खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

उपर्युक्त पैरा से संज्ञान लेते हुए, स्कूल को विकास निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियों की लागत की सीमा तक विकास निधि उपयोग खाते को आस्थगित आय के रूप में मानना चाहिए था और इस आस्थगित आय खाते से प्रभारित मूल्यास के अनुपात में राशि को आय और व्यय खाते के क्रेडिट में अंतरित कर दिया था। तथापि, यह नोट किया गया है कि स्कूल ने विकास निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए विकास निधि उपयोग खाता नहीं बनाया है और इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यास के अनुपात में इस उपयोग खाते से आय और व्यय खाते में कोई राशि अंतरित नहीं की है। इस प्रकार, स्कूल ने आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट - 21 के उपर्युक्त पैरा 99 का पालन नहीं किया है: स्कूलों द्वारा लेखांकन और इसका पालन करने के लिए अनुदेश दिया जा सकता है।

3. स्कूल ने प्रबंधन आंकलन के आधार पर उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान किए हैं न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 15 द्वारा अपेक्षित है। यदि प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए होते तो स्कूल की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता था। बीमांकिक मूल्यांकन अभिलेख के अभाव में इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अभिलेख पर सभी सामग्री की विस्तृत जांच के बाद और स्कूल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यह अंततः मूल्यांकन / निष्कर्ष निकाला गया कि:

1. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल 23,72,57,471 रुपये की कुल राशि उपलब्ध है, जिसमें से वित्त वर्ष 2017-18 में 14,86,71,332 रुपये का

नकद बहिर्वाह अनुमानित है। इसके परिणामस्वरूप 8,85,86,139 रुपये का कुल अधिशेष बचता है। विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	राशि	टिप्पणि याँ
संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 31.03.17 को नकद और बैंक बैलेंस	1,09,23,435	
जोड़ें: संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 31.03.17 को निवेश	14,71,11,538	
जोड़ें : भवन निर्माण के लिए सोसायटी से वसूली योग्य राशि	19,08,832	
घटाना: वित्त वर्ष 2016-17 के लिए तुलन पत्र संपरीक्षा के अनुसार 7 वें सीपीसी के लिए बकाया	1,16,87,834	
कम: डीडीए के प्रति निवेश	35,000	
कम: 31.03.2017 को अवधान द्रव्य राशि	23,75,750	

कम: 31.03.2017 को उपदान और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के विरुद्ध निवेश	3,71,87,586	नोट 1
घटाना: विकास निधि	1,44,82,845	नोट 2
उपलब्ध निधि	9,41,74,790	
जोड़ें: संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिए शुल्क (हमने माना है कि वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त राशि कम से कम वित्त वर्ष 2017-18 में अर्जित होगी)	14,21,07,563	
जोड़ें: परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अन्य आय (हमने माना है कि वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त राशि कम से कम वित्त वर्ष 2017-18 में अर्जित होगी)	9,75,118	
2017-18 के लिए निधियों की अनुमानित उपलब्धता	23,72,57,471	

घटना: सत्र 2017-18 के लिए वास्तविक व्यय स्कूल द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.04.2019 (पूजीगत व्यय सहित) के माध्यम से प्रस्तुत परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार	14,86,71,332	नोट 3
अनुमानित अधिशेष	8,85,86,139	

नोट1: बीमांकक के अभिलेख के अनुसार उपदान और अवकाश नकदीकरण के प्रावधानों का रखरखाव नहीं किया गया है। हालांकि, चूंकि स्कूल के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है, इसलिए इन प्रावधानों के प्रति वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संपरीक्षित लेखा वित्तीय विवरणों के अनुसार निवेश की गई वास्तविक राशि पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूल को निर्देश दिया जाता है कि वह उपदान और अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त करे और आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर एलआईसी (या किसी अन्य एजेंसी) के साथ उपरोक्त राशि निवेश करें।

नोट 2: उच्चतम न्यायालय ने मॉडर्न स्कूल के मामले में माना कि मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फर्नीचर और फिक्स्चर और उपकरणों की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए संसाधनों के पूरक के लिए विकास शुल्क छात्रों से कुल वार्षिक ट्यूशन शुल्क का 15% से अधिक नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, निदेशालय के दिनांक 16.04.2010 के परिपत्र संख्या 1978 में कहा गया है कि "सभी स्कूलों को, सबसे पहले, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप वेतन और भत्ते के



भुगतान में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा धन/भंडार का उपयोग करने की संभावना तलाशनी और खत्म करनी चाहिए। आरक्षित निधि का एक हिस्सा जिसका उपयोग वर्षों से नहीं किया गया है, का उपयोग शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव करने से पहले कमी को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। स्कूल ने कई वर्षों में विकास निधि जमा की है और वित्त वर्ष 2016-2017 के अपने संपरीक्षित लेखा वित्तीय विवरणों में 7,13,17,041 रुपये का समापन शेष दिखाया है। तदनुसार, फर्नीचर और जुड़नार और उपकरणों की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए अपनी आवश्यकता से अधिक विकास शुल्क एकत्र करके स्कूल द्वारा बनाई गई विकास निधि के संचित भंडार को वित्तीय निहितार्थ को पूरा करने के लिए स्कूल के पास उपलब्ध मुफ्त रिजर्व माना गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2016-2017 में छात्रों से 1,44,82,845 रुपये की राशि के बराबर विकास निधि को स्कूल के पास उपलब्ध धन के रूप में नहीं माना गया है।

नोट 3: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्कूल द्वारा कुल व्यय बजट/प्रस्तावित 15,38,30,000 रुपये था जिसमें 1,51,30,000 रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार मूल्यहास और भवन में परिवर्धन से पहले वास्तविक कुल व्यय 14,86,71,332 रुपये है। चूंकि, वित्त वर्ष 2017-18 पहले ही पारित किया जा चुका है इसलिए वास्तविक व्यय को उपरोक्त तालिका में माना गया है। वास्तविक व्यय की तुलना में बहिर्वाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े रुपये को दर्शाते हैं)।

विवरण	2017-18
वेतनमान	9,54,26,227
स्कूली शिक्षा का खर्च	1,47,99,501

प्रशासन और जनरल	1,20,57,086
मरम्मत और रखरखाव	2,01,10,894
अन्य व्यय	7,397
कुल राजस्व व्यय	14,24,01,105
घटाना: मूल्य हास	(1,13,45,214)
कुल (क)	13,10,55,891
पूँजीगत व्यय	7,26,80,525
घटाना: भवन बढ़ाने का कार्य	(5,50,65,084)
कुल (ख )	1,76,15,441
कुल व्यय (क +ख)	14,86,71,332

उपरोक्त परीक्षण के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि स्कूल के पास अपने खर्चों को पूरा करने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम निहितार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है और वर्ष 2017-18 के लिए शुल्क में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्कूल प्राधिकरण को अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने के अधीन निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

1. शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए स्कूल द्वारा डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 (3) के तहत दायर पूर्ण शुल्क विवरण के अनुसरण में कोई बढ़ा हुआ शुल्क नहीं लेना चाहिए और यदि शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए शुल्क पहले ही बढ़ा दिया गया है और शुल्क लिया गया है, तो इसे

अभिभावकों को वापस कर दिया जाएगा या बाद के महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

2. शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल के शुल्क वृद्धि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बारे में अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और परिपत्र के माध्यम से अभिभावकों को सूचित करना।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेतन और भत्ते फीस से बाहर आएंगे, जबकि पूंजीगत व्यय आधुनिक स्कूल बनाम भारत संघ के अपने निर्णय में माननीय दिल्ली के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बचत पर एक शुल्क होगा। इसलिए, स्कूल डीएसईए, 1973 की धारा 17 (3) के तहत स्कूल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शुल्क ढांचे के एक घटक के रूप में पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं करेगा।

4. डीएसईआर, 1973 के नियम 177 के प्रावधानों और समय-समय पर इस निदेशालय द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों के अनुसार छात्रों से एकत्र किए गए शुल्क का उपयोग करना।

5. ऊपर सूचीबद्ध सभी वित्तीय और अन्य अनियमितताओं को दूर करना और 30 दिनों के भीतर डीडीई को अनुपालन अभिलेख प्रस्तुत करना।

इस आदेश या यहां दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और डीएसईए, 1973 और डीएसईआर, 1973 की धारा 24 (4) के प्रावधान से निपटा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-  
20.04.2019  
नीलम यादव  
डीडीई (उत्तर)"

63. रामजस स्कूल, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल में आक्षेपित आदेश के समान उपरोक्त आदेश के मामले में उपरोक्त आदेश में याचिकाकर्ता/स्कूल के विरुद्ध प्रारंभिक आरोप भी शामिल हैं और याचिकाकर्ता ने जिस तरह से फीस वसूलने का इरादा किया है, उसके साथ-साथ याचिकाकर्ता के खातों का विश्लेषण करने के तरीके के सावधानीपूर्वक विच्छेदन द्वारा आरोपों का पालन व्यय के विरुद्ध आय और हानि के विरुद्ध लाभ की तुलना के साथ किया गया है। रामजस स्कूल, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और पर ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल के मामलों में शिक्षा निदेशालय जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह यह है कि “स्कूल के पास वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वित्तीय निहितार्थ को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है और वर्ष 2017-2018 के लिए फीस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।”

64. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रामजस स्कूल और महावीर सीनियर मॉडल स्कूल में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है और जैसा कि पहले ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिव्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी से शिक्षा के व्यावसायीकरण के किसी भी तत्व के अभाव में स्कूल की वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध धन की पर्याप्तता के बारे में अपने स्वयं के व्यक्तिपरक निर्णय पर आने का शिक्षा निदेशालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस तरह का निर्णय स्पष्ट

रूप से स्कूल को मिलने वाली स्वायत्तता को प्रभावित करता है - ऐसी गतिविधि जिसे टीएमए पाई मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी फटकार लगाई है।

65. इसलिए, रि.या.(सि.) 8794/2018 में दिया गया तर्क यथोचित परिवर्तनों के साथ वर्तमान मामले पर लागू होता है।

### **निष्कर्ष**

66. इसलिए, याचिकाकर्ता - स्कूल द्वारा फीस में वृद्धि को प्रतिबंधित करने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है।

67. हालांकि, यह डीओई को डीएसई अधिनियम या डीएसई नियमों के प्रावधानों के स्कूल द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन के संबंध में कोई निर्णय लेने से नहीं रोकेगा, जैसा कि ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल के मामले में अनुमति दी गई है।

### **समग्र निष्कर्ष**

68. इसलिए, उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं को पैरा 61 और पैरा 66 उपरोक्त में उपदर्शित सीमा तक जुर्माने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

**न्या.सी. हरि शंकर,**

**7 फरवरी, 2024**

**वाईजी/आर.बी/डीएसएन**

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।